हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

02 मार्च, 2017

खंड 1, अंक 05

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 02 मार्च, 2017

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

गुरुनानक कन्या महाविद्यालय, सन्तपुरा, यमुना नगर के अध्यापकों एवं छात्रों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

वॉक–आउट

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

जिला सिरसा में रानियां निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में दुधारु पशुओं में फैल रही बीमारी के सम्बन्ध में मामला उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

कैनेडियन प्रतिनिधि मंडल तथा सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) की पत्नी का अभिनन्दन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 02 मार्च, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में सुबह 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब मंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, यह सदन पहली मार्च, 2017 को नारायणगढ–सढौरा रोड़ पर एक ट्रक एवं टवेरा कार की भीषण टक्कर में मारे गये आठ निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जो शोक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं मैं भी अपनी भावनाएँ उनके साथ जोड़ता हूं। मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूँगा कि वे दिवगंत आत्माओं की शान्ति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Upgradation of Schools

***1984.Sh. Makhan Lal Singla.** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools of village Natar and Phulkan; if so, the time by which the said schools are likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, माननीय विधायक श्री मक्खन लाल सिंगला ने सिरसा के नाटर और फुलकां के विद्यालय का दर्जा बढाने के बारे सवाल पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नाटर के 5 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय न

होने के कारण उसका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्तर तक दर्जा बढाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो कि इसी तरह में बढ़ा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न राजकीय उच्च विद्यालय, फूलकां के बारे में पूछा है यह स्कूल नार्म्ज पूरे नहीं करता। इसलिए उसका दर्जा नहीं बढ़ाया जा सकता।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या नं0 1957

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री हरि चन्द मिड्ढा, सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

Upgradtion Of PHC TO CHC

***1965 Sh. Balkaur Singh. :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to upgrade the PHC of Kalanwali to CHC on 25-08-2016; if so, the time by which the said PHC is likely to be upgraded as CHC ?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Yes, Sir. It will be done in the year 2017-18.

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के कालांवाली में पी.एच.सी बनी हुई है जो काफी समय पहले बनी थी। इस पी.एच.सी. के साथ तकरीबन 50 से 60 हजार की आबादी लगती है। पिछली बार जब हमारे मुख्यमंत्री जी वहां गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि इस पी.एच.सी को सी.एच.सी बना दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बलकौर सिंह जी, मंत्री जी पहले ही आपको सी.एच.सी. बनाने का आश्वासन दे चुके हैं।

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उस पी.एच.सी में केवल नाम मात्र स्टाफ है। वहां पर दो मेडिकल ऑफिसरों की पोस्ट हैं, जो अभी तक खाली हैं। डेंटल सर्जन और फार्मासिस्ट की भी पोस्टें खाली हैं और लेडी डॉक्टर

भी नहीं है, यहां तक की स्विपर भी नहीं है। इस तरह से वह नाम मात्र की ही पी. एच.सी. है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस पी.एच.सी. में स्टाफ की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी कालांवाली गए थे और उन्होंने कालांवाली की पी.एच.सी को सी.एच.सी बनाने की घोषणा की थी। उसकी सारी मंजूरी भी मुख्यमंत्री जी से मिल गई है। आने वाले एक साल के अंदर–अंदर उसमें सी.एच.सी के मुताबिक स्टाफ की भर्ती कर ली जाएगी।

श्री बलकौर सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय मत्री जी से एक और बात बताना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर है जो डैपुटेशन पर लगा हुआ है। वहां पर डॉक्टर नियमित रूप से लगाया जाए। आम गरीब लोग जो इस अस्पताल में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर डैपुटेशन पर होने के कारण बहुत कम मरीज आते हैं। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि वहां पर पक्के तौर पर डॉक्टर लगाया जाए।

श्री अनिल विज : स्पीकर महोदय, ये बात अच्छी है कि वहां दो डॉक्टरों की पोस्टें हैं। उसमें एक डॉक्टर को डैपुटेशन पर लगाया गया है और दूसरी पोस्ट पर रैगूलर डॉक्टर लगा देंगे।

.....

Shortage of Irrigation Water

***1684. Shri Jagbir Singh Malik.:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is acute shortage of irrigation water on tails of Guhna minor, Bhainswal minor, Kailana minor, Lath minor and rajbahas of Gamri, Khanpur and Garhi; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply adequate irrigation water in above-said minors and rajbahas?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनंखड़) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के जवाब को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न के इस भाग का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गुहना माईनर में मोगा नंबर 32999 से आगे कभी पानी नहीं आया। आप वहां पर आने वाले एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं कि मांगे राम गुहना निवासी की कितनी दरख्वास्त आती है, कितनी वहां पर पेंडिंग पड़ी हुई है। वह हर बार दरख्वास्त देता है कि वहां तक पानी नहीं जाता, इसके आगे दो गांव और लगते हैं। इसके अलावा लाठ माईनर की टेल पर पानी की भारी कमी है। ये बता सकते हैं कि कितनी परसेंट इनकी इरिगेशन है, इनके पास रिकॉर्ड होगा कि इनके गांव में इन माईनरों की टेल पर इरिगेशन की कितनी परसेंटेज है। आप इसका जवाब दें, सिर्फ न कहने से काम नहीं चलता, लोगों को पानी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी कहा था कि इस बार हमारे पास पानी की कमी है। भाखड़ा डैम के पिछले साल के लैवल में और इस साल के लैवल में 45 फीट का अंतर है। पिछले साल भाखड़ा डैम में 21 लाख 40 हजार एकड़ फीट पानी था और इस बार उसमें 11 लाख 50 हजार एकड़ फीट पानी रह गया। मौटे तौर पर इस साल 10 लाख एकड़ फीट पानी की कमी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय सदस्य के सवाल पर आता हूं क्योंकि इनके सवाल का उत्तर इसी बात में छुपा है। जो पानी हम पहले भाखड़ा से 10 हजार क्यूसिक लेते थे, वह हम अभी 8 हजार क्यूसिक यानी 20 प्रतिशत पानी कम ले रहे हैं और उस 20 परसेंट पानी कम लेने का असर यह हुआ है कि जो पानी हम हरियाणा को 4 बार में देते थे, अब वह 5 बार में दे पा रहे हैं। जो हमारे मलिक साहब कह रहे हैं कि पूरा एक महीना ऐसे ही निकल जाता है और नहर में पानी नहीं पहुंचता। जो पानी पहले 24 दिन बाद 25वें दिन आता था वह अब 32 दिन बाद 33वें दिन आता है । यह कठिनाई आज हमारे सामने है, इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी । पूरे महीने पानी न आने के कारण किसान परेशान होता है और किसान को लगता है कि उसके यहां पानी नहीं आया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फरवरी के

महीने में गुहना माईनर में टेल पर पानी लगातार पहुंचा है । 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक गुहना माईनर की टेल पर एक फीट तक पानी रहा है । यह जानकारी विभाग द्वारा दी गई है, वही बता रहा हूं । जनवरी के महीने में वहां पानी नहीं गया क्योंकि 32 दिन बाद नम्बर आता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दिसम्बर महीने में लाठ माईनर में पानी गया था । लाठ के लोगों ने हमें लिखित में रिकवैस्ट की थी कि उन्हें फरवरी के महीने में पानी न दिया जाये । क्योंकि बरसात हो गई तो उनके यहां फरवरी के महीने में ज्यादा पानी आने से नुकसान होने का भय था । इसी तरह से भैंसवाल माईनर में भी फरवरी के महीने में पानी टेल तक गया था । फरवरी महीने में गुहना माईनर और भैंसवाल माईनर में करीबन एक फीट तक टेल पर पानी रहा है और लाठ माईनर के लिए लोगों ने मना कर दिया था । दिसम्बर के महीने में लाठ, भैंसवाल और गुहना इन तीनों माईनर्ज पर टेल तक करीबन एक फीट पानी पहुंचा है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, भैंसवाल माईनर पर मेरे खुद के खेत दो जगहों पर लगते हैं । भैंसवाल गांव में ग्राउंड वाटर बहुत खराब है जिसके कारण लोग खेती करना बंद कर रहे हैं । मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गोहाना हल्के में 11 टेल लगती हैं जिनमें दिन के समय में तो कुछ पानी आ जाता है लेकिन रात के समय में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिलकुल पानी नहीं आता । मंत्री जी आप ग्राउंड रियलिटी की जानकारी लें, जो मैं जानकारी दे रहा हूं वही पोजीशन मिलेगी ।

.....

Construction of Four Lane Road

***1679 Sh. Balwan Singh Daulatpuria.** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Fatehabad to Surewala Chowk via Bhuna; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। यद्यपि, उकलाना से सुरेवाला चौंक तक सड़क के भाग को चारमार्गीय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए यातायात के अच्छे साधन बहुत बड़ा योगदान होता है । हमारा फतेहाबाद जिला नैशनल हाई वे पर पड़ता है और दूसरी तरफ हिसार से सुरेवाला चौक कैथल–कलायत तक बन रहा है । अगर फतेहाबाद से सुरेवाला चौक वाया भूना सड़क को चारमार्गी बनाया जायेगा तो चण्डीगढ़ आने के लिए सिरसा और फतेहाबाद वालों के लिए ठीक रहेगा । उसके अंदर उकलाना हल्का और आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी हल्का अटैच होता है । फतेहाबाद पैडी और कोटन बैल्ट है यदि वहां पर कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट इण्डस्ट्री लगाना चाहे तो उसके लिए भी यातायात के साधन अच्छे होने चाहिंए । अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में सड़कों का काम ठीक चल रहा है । माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे मंत्री हैं और इन्होंने कई दफा कहा भी है कि ये प्रदेश में सड़कों पर कहीं भी गड्डे नहीं छोड़ेंगे तो हमारे उपर भी कृपा करके फतेहाबाद से सुरेवाला चौक वाया भूना सड़क को चारमार्गी बनाया जाये ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने बलवान सिंह जी के यहां बहुत काम करवाये हैं और भविष्य में भी करवायेंगे । इनके अकेले विधान सभा क्षेत्र में हमने 30 करोड़ रुपये के काम इस साल करवाये हैं और 57 करोड़ रुपये के काम प्रोग्रेस में हैं । इसके अतिरिक्त 31 करोड़ रुपये के काम अगले साल करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, चारमार्गी सड़क बनाने के लिए नार्म्ज के मुताबिक ट्राफिक वोल्यूम 20 हजार होनी चाहिए लेकिन जिस सड़क को माननीय साथी चारमार्गी बनाने की बात कर रहे हैं उसका ट्राफिक वोल्यूम 13 हजार है । सैंटर गवर्नमैंट ने ट्राफिक वोल्यूम नार्म्ज को कम किया है और हम भी कोशिश करेंगे की चारमर्गी सड़क बनाने के लिए ट्राफिक वोल्यूम नार्म्ज को कम किया जाये । उसके बाद जिस सड़क का माननीय साथी जिक्र कर रहे हैं, उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अनूप धानक : स्पीकर सर, जो माननीय मंत्री ने उकलाना से सूरेवाला मोड़ तक चार मार्गी सड़क के बारे में बताया है। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक बनेगा? इसके अलावा माननीय मंत्री जी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने वहां पर आर.यू.बी. के निर्माण की बात पिछले सैशन में की थी। क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह आर.यू.बी. कब तक बन जायेगा?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि अगले फाईनैंशियल ईयर में इन सारे के सारे कामों को कम्पलीट कर दिया जायेगा।

.....

To Bring out the Small Farmers from the Losses

***1688. Shri Parminder Singh Dhull. :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether any scheme is being formulated by the Government for the upliftment of small farmers and to bring them out from the losses; if so, the details thereof together with the time by which it is likely to be implemented?

कृषि मन्त्री (ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा जाता है।

कथन

छोटे किसानों को घाटे से बाहर निकालना

आर्थिक–सहायता के प्रावधान के माध्यम से छोटे किसानों सहित किसानों को ऊपर उठाने के लिए स्कीमों को दर्शाने वाले कथन।

किसानों के उत्थान के लिए लाभदायक खेती करने में उनकी सहायता करने के लिए आर्थिक–सहायता का प्रावधान करने, उत्पादकता को बढ़ानें तथा उपज के विपणन के माध्यम से बहुत सी स्कीमें लागू की जा रही हैं। हाल में नामकृत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग तथा बागवानी विभाग, पशुधन तथा मत्स्य विभाग अपनी सभी स्कीमों में छोटे किसानों पर फोक्स कर रहे हैं। कुछ स्कीमें जिनमें छोटे किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं वे निम्न अनुसार है:–

1. तिलहन तथा दलहन पर राष्ट्रीय मिशन (एन0एम0ओ0ओ0पी0)।
2. कृषि इंजीनियरिंग तथा परीक्षण बोरिंग के लिए स्कीम।
3. फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (सी0डी0पी0)।

4. बागवानी किसानों के लिए खेत में विपणन सहायता के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी0सी0डी0पी0)।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने चार स्कीम्ज का जिक्र किया है। यह बात तो निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचल में निवास कर रही है और इस आबादी में भी अधिकतर किसान हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2014 में नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट आई थी। उसमें किसान की आय 6426/– रूपये प्रति महीना बताई गई थी जिसमें 3078/– रूपये केवल कल्टीवेशन से थी जो कि सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी चार गुणा कम है। सौ घंटे किसान परिवार को मजदूरी करनी होती है। इसी डाटा में यह बताया गया था कि जो 70 परसैंट फार्मर मार्जिनल हैं जो कि पूरे देश में 6.26 करोड़ हैं। इस 70 परसैंट में हरियाणा प्रदेश का 70 परसेंट से भी ज्यादा हिस्सा आता है। इसमें यह बताया गया है कि 856/– रूपये प्रति महीना खर्च कम है। इसका मतलब यह हुआ कि वे कर्ज में पूरी तरह से दबे हुए हैं और उनका कर्ज लेकर ही लगातार काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी के अंदर सन् 1966 में जो एक सरकारी कर्मचारी और किसान की वेजिज थी उसके भी तुलनात्मक आंकड़ें दिये हुए हैं। उस समय किसान अपनी गेहूं के 4–5 क्विंटल बेचकर उस समय की सरकारी कर्मचारी के बराबर हो जाया करता था। आज स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। आज यह स्थिति आ गई है कि In 1966, when the Government started to procure food-grain at minimum sport price, the farmers earned as much as the lowest level of government employees by selling a few bags of wheat. Today, an average farmer cannot even meet out with said level by selling all his agricultural produce. क्या मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर फार्मर के 36.1 परसैंट सुसाईड केस बढ़े हैं उनकी बढ़ोतरी का यह भी एक मुख्य कारण है। यह पूरे देश का डाटा है। पूरे देश में किसानों द्वारा किये जा रहे सुसाईड का मुख्य कारण उनके ऊपर जो कर्ज है वही है। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि जो प्रदेश के मार्जिनल फार्मर हैं इनको कर्ज से मुक्ति दिलवाने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है। सरकार

को चाहिए कि वह अपने स्तर पर ऐसे कदम उठाये ताकि इनकी आमदनी बढ़े और ये अपने परिवार का पेट पाल सकें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हमारे सामने सदियों से ज्यों की त्यों खड़ा है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी का एक ब्यान आया था कि वर्ष 2022 तक हम इन मार्जिनल फार्मर्ज की आमदनी दुगुनी कर देंगे। किसानों की हालत पर बराबर बात होती रहती है। एक तरफ तो किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है और दूसरी तरफ उसके ऊपर कर्ज के ब्याज का बोझ है। इस प्रकार से उसके ऊपर बहुत से बोझ हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश के इस मार्जीनल फार्मर को इस कर्ज के बोझ से किस प्रकार से निकालेगी? हमारे प्रदेश के जो छोटे किसान हैं उनकी जो खराब हालत है अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में उनकी हालत और भी खस्ता हो जायेगी। यही कारण है कि वह बड़ी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटिड है। इसी के कारण वह दुखी हो रहा है। आप इसी का एक और कारण देंखें कि वर्ष 2011 के जो सैंसस आये थे उसके अंदर इस बात का उल्लेख था कि किसानों ने खेती करनी छोड़ दी थी। जो कल्टीवेशन का नम्बर था वह 127.3 मिलियन से घटकर 118.8 मिलियन रह गया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो वह जायेगा कहां? वह क्या करेगा? उसको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। किसान को आज मिनीमम वेजिज भी नहीं मिल पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मार्जिनल फार्मर को इस खस्ताहाल स्थिति से निकालने के लिए कोई विशेष योजना है? मैंने पिछले सैशन में भी यह कहा था कि प्रदेश में इण्डस्ट्रियल सैक्टर की ग्रोथ के लिए जो सरकार द्वारा स्पैशल इकॉनोमिक जोन बनाये जा रहे हैं हम उनके खिलाफ नहीं है बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब सरकार यह विचार करे कि खेती और किसानों की बेहतरी के लिए भी एक स्पैशल जोन बनाया जाये। जिसके माध्यम से सरकार की किसानों और खेती से सम्बंधित जो योजनाएं हैं उनको इम्पलीमैंट किया जाये। जिस प्रकार से माईक्रो इरीगेशन की बात है। इस पर विचार किया जाये और किसान की मिनिमम वेजिज भी सरकार द्वारा फिक्स की जाये।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि माननीय सदस्य का जो सवाल है वह वास्तव में प्रश्न उत्तर की कैटेगरी में नहीं आता है । वह

कालिंग अटैन्शन मोशन की कैटेगरी में आता है । उन्होंने सवाल नहीं एक रैजोल्यूशन पूछ लिया है ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, तो फिर मैं नियम 73–ए के तहत नोटिस दे देता हूं उसको आप स्वीकार कर लें और उसके जवाब में सरकारी की तरफ से विस्तृत उत्तर दे दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह पूरे हाउस का कंसर्न है, पूरे देश का कंसर्न है और इस बात से सभी लोग चिंतित हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए । माननीय सदस्य ने स्वयं भी प्रधानमंत्री जी की बात का उल्लेख किया है कि वे भी इस प्रयास में लगे हुये हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाये ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी कृपया सदन को यह भी बतायें कि किसानों की आमदनी दुगनी हो कर कितनी हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने वर्ष 2022 तक कहा है । यह एक दम से दुगनी नहीं हो पायेगी ।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि जब आप चुनाव में गये थे और आपने सभी वर्गों से वायदे किये थे क्या वे टाइम बाउंड थे, उस समय आपने टाइम बाउंड वायदे नहीं किये थे कि हम यह काम इतने समय में करेंगे । टाइम बाउंड तो आप अब कर रहे हैं कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और इसको केवल राजनीतिक तौर पर गेंद मेरे पाले में या तेरे पाले में छोड़ने से काम नहीं चलेगा । यह सवाल वास्तव में सभी राजनीतिक दलों का है, यह सभी पार्टियों का कंसर्न है और इस कंसर्न पर सभी को मिल कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है और किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है । कोई एक राज्य ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मेरे राज्य में किसानों की अवस्था अच्छी है और किसी दूसरे राज्य में अच्छी नहीं है । यह देशव्यापी सवाल भी है और अपने प्रदेश का सवाल भी है । जिस वर्ष की चर्चा श्री परमिन्द्र सिंह ढुल कर रहे हैं यह उन्हीं वर्षों में शिफ्ट हुआ है । हम वर्ष 1966

से पहले की बात करें तो उस समय गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई था । हमारे इनपुट, हमारी सारी मजदूरी, हमारे बैल सभी चीजें हमारे हाथ में थी और गांव में किसान अपनी इकॉनोमी स्वयं चलाता था । किसान स्वयं के लिए और जो बाकी की आबादी थी उसके भरण पोषण के लिए अनाज देता था लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन आ गई कि देश की जरूरत के लिए खाद्यान उत्पन्न किये जायें । उसके बाद सारी की सारी इनपुट मार्केट बाजार में आ गई लेकिन किसान की आउटपुट की कोई संगठित मार्केट नहीं है, वह कमजोर है । इनपुट की मार्केट वर्ल्ड वाइड संगठित मार्केट है । यहां पर अमेरिका तक की कम्पनियां भी अपने बीज बेचती हैं तथा खेती से संबंधित अपने दूसरे सामान बेचती हैं । उनके नाम भी इस देश और प्रदेश में चले हुये हैं, चाहे मोनसैंटो है, चाहे कारगिल कम्पनी है। ये सभी वर्ल्ड वाइड कम्पनीज हैं लेकिन आउटपुट की किसी एक कम्पनी का नाम भी देश में नहीं आता है । केवल कॉआपरेटिव सैक्टर में दूध की कम्पनी अमूल को छोड़कर और कोई कम्पनी नहीं है जो किसान की आउटपुट को बाहर देशों में भेजती हो । उत्तर यहीं से शुरू होता है कि जब तक आउटपुट की मार्केट संगठित नहीं होगी और क्रॉप मैनेजमैंट और क्रॉप मार्केट मैनेजमैंट नहीं होगी तब तक किसानों की समृद्धि का रास्ता नहीं खुलता है । उसमें बड़ी कठिनाई समाज की मानसिकता भी है । जब भी देश में खाद्यान के या फल सब्जियों के रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं तो प्याज और टमाटरों की माला गले में डाल कर लोग प्रदर्शन करते हैं कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं । इसके विपरीत जब किसान की फसल का उचित रेट नहीं मिलता है तथा किसान अपनी सब्जियों को फेंक कर जाता है उस समय कोई नहीं कहता कि किसान को घाटा हो रहा है । उस समय कोई आवाज नहीं उठाता । इसमें चाहे मीडिया की बात हो और चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, टमाटर और प्याज की माला डालकर प्रदर्शन करते हैं। इससे किसान के घर में जो कुछ ज्यादा जाने की स्थिति आती है तो वह स्थिति नहीं बनती है । इस प्रकार की सामाजिक मानसिकता भी कहीं न कहीं इसमें बाधक है । निश्चित रूप से जो परिवर्तन है उसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि किसान को अपने बिचोलियों को समाप्त करके बाजार तक खुद पहुंचना पड़ेगा। जब तक यह चेन सीधी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचती तब तक किसान को अच्छा दाम नहीं मिल सकता क्योंकि किसान इस चेन से कट जाता है । बहुत वर्षों से यह सवाल उठ रहे हैं कि चिप्स का दाम इतना है और आलू का दाम इतना है

लेकिन चिप्स वाले दाम में किसान शामिल नहीं है । जिस दिन चिप्स वाले दाम में किसान शामिल हो जाएगा तो किसान की आमदनी भी बढ़ जाएगी । इसी तरह से सोस का दाम इतना और टमाटर का दाम इतना है लेकिन जब सोस का दाम मिलता है तो उसमें भी किसान शामिल नहीं है क्योंकि किसान इस तरह की चेन से कटा हुआ है । हम इस चेन को लगातार जोड़कर किसान को अपने ब्रांड के साथ खुद बाजार में उतरने की स्थिति में लेकर आएंगे । इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिये हम बहुत सारी स्कीमें शुरू कर रहे हैं । परमिन्द्र जी, उसमें हम पहला काम यह कर रहे हैं कि हम किसान से पैरी अर्बन कन्सैप्ट के साथ खेती शुरू कराना चाहते हैं । हम देखतें हैं कि दिल्ली से बाहर निकलते ही हमारे धान और गेंहू के खेत हैं । बिजिंग के आस–पास 18 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्होंने बिजिंग की जरूरतों के लिये खेती करने के लिये दिया है । हम चाहते हैं कि हरियाणा के किसान भी दिल्ली की चार करोड़ की मार्किट के हिसाब से खेती करना शुरू करे और उस मार्किट में जितनी महंगी चीजें हैं उनको किसान अपने खेतों में उगाए और उस बाजार तक सीधी आपूर्ति करने वाला किसान बने । उस नाते से हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे हरियाणा की 25 प्रतिशत जमीन होर्टिकल्चर खेती पर आ जाए । उसके लिये एफ.पी.ओज.(उत्पादक संगठन) बनाए जा रहे हैं और हर जिले में एक्सीलैंसी सैंटर खोले जा रहे हैं । हमने 140 कलस्टर चिन्हित किये हैं और प्रदेश में 340 गांवों में हम केवल बागवानी की खेती कराएंगे तथा उन गांवों तक कलैक्शन सैंटर लेकर तेजी से किसानों का सामान पहुंचाने की कोशिश करेंगे । हमारे कुछ इलाकों में फूलों की खेती भी शुरू हुई है जिसके लिये हम एक फूलों की मंडी भी डिवैल्प कर रहे हैं ताकि फूलों की खेती करने वाले किसानों को भी वाजिब दाम मिल सकें । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक 600 एकड़ का बहुत पुराना प्रोजैक्ट है । अगर हम उसमें बागवानी की इतनी बड़ी मण्डी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं । वैसे तो अब बागवानी की युनिवर्सिटी भी आ गई है । इसके साथ–साथ हम किसी न किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हर जिले में एक्सीलैंसी सैंटर भी खोल रहे हैं । बागवानी के लिये यह 600 एकड़ की मण्डी भी जल्दी ही डिवैल्प हो इस काम में भी हम लगे हुए हैं । इस प्रकार से हरियाणा में ये चेंज हो इस पर हम काम कर रहे हैं। जहां तक दुग्ध उत्पादन की बात है तो उसमें भी हमारा हरियाणा तीसरे नम्बर पर हैं क्योंकि किसान केवल खेती पर ही डिपैंड नहीं

रह सकता । अतः किसान को हम कैसे एक नम्बर पर लाएं । इसके लिये हम दूध पर बोनस भी दे रहे हैं और उसके साथ–साथ दूध के उत्पादन पर ईनाम भी दे रहे है ताकि किसी न किसी तरीके से हमारा हरियाणा नम्बर एक पर आ जाए और पंजाब तथा गुजरात से आगे चला जाए । इसका तीसरा रास्ता यह भी है कि किसान को जोखिम फ्री किया जाए । इसके लिये हम अधिक से अधिक किसानों तक फसल बीमा योजना को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । हमारी यह कोशिश है कि अगर ओले पड़ने से किसान की फसल नष्ट होती है तो किसान की फसल के नुकसान की भरपाई प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजे के रूप में की जाए ताकि किसान पर उस नुकसान का असर न पड़े । इसके साथ–साथ हमारी सरकार पशु बीमा पॉलिसी भी शुरू कर रही है ताकि यदि किसान की भैंस मर जाए, गाय मर जाए तो किसान को तकलीफ न हो । उस नाते से हम समस्त उपाय लेकर चल रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी किसानों के पक्ष में महती प्रयासों और पॉलिसिज में भी और ज्यादा चेंजिज करने की आवश्यकता है ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विशेष कृषि जोन बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे । मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हरियाणा में किसानों ने अपने आप पांच कृषि जोन बनाए हुए हैं जैसे सोनीपत में 5 हजार एकड़ में एक कृषि जोन बना हुआ है । एक कृषि जोन दादरी के पास बनाया गया है । इस तरह से किसानों ने कई कृषि जोन बनाए हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में किसानों के लिए विशेष कृषि जोन बनाए जाएंगे या नहीं क्योंकि विशेष कृषि जोन में किसान इक्ट्ठे होकर जिसको मार्किट की जरूरत होती है उसको अपनी फसल बेचते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषिमंत्री जी ने सारी बातें बहुत विस्तार से कही हैं कि सरकार बागवानी को, होर्टिकल्चर को, फुल्लोरी कल्चर को किस तरह से डिवैल्प करना चाहती है लेकिन पिछली सरकार में गन्नौर में जो इंटर नैशनल वेजिटेबल एण्ड होर्टिकल्चर मार्किट बनी थी उसकी डिवैल्पमैंट के लिये माननीय कृषि मंत्री महोदय वहां दो बार गये भी हैं और कृषि विपणन बोर्ड की अध्यक्षा भी वहां पर गई हैं उन्होंने कहा था कि छः महीने में यह मण्डी चालू हो जाएगी । मैं वहां से विधायक हूं । वह मण्डी दिल्ली के सबसे नजदीक है इसलिए उस मण्डी के बनने से, उसके विस्तारीकरण से और उसके चालू हो जाने से उस

इलाके में फूल और सब्जी की खेती को बहुत बढ़ावा मिल सकता है । माननीय कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है और साथ में यह प्रश्न भी है कि उस मण्डी पर कब काम चालू होगा तथा उसको कब तक कम्पलीट कर दिया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, तीन बातें सामने आई हैं कि किसान कहीं भी कृषि जोन डिवैल्प करेंगे तो उसके लिये किसानों को जो भी सुविधा देने की बात है । उस संबंध में बताना चाहता हूं कि जैसे संयोग से सोनीपत में ही हमारा खुम्बी का जोन डिवैल्प हो गया है । उसके लिये जो भी सुविधा की आवश्यकता है उसके लिये कृषि मंत्रालय पूरी तरह से खुले मन से उन किसानों की मदद करेगा । अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी वैसे इस प्रश्न से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन मुझे लगता है अगर मैं दूंगा तो सभी सदस्यों को फायदा होगा। जो लोग एयर कडीशन में रहते हैं उनको विटामिन–डी की कमी हो जाती है जिसके लिए उन्हें विटामिन–डी की गोलियां खानी पड़ती हैं और इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। खुम्बी/मशरूम एक मात्र ऐसी सब्जी है जो मनुष्य की तरह से विटामिन–डी लेती है और जो लोग डेली खुम्बी/मशरूम खाते हैं उनको विटामिन–डी की कमी नहीं रहती। यह जानकारी मुझे भी नई मिली है और जब मैंने इस जानकारी को अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो मेरी भी गोलियां छूट गई क्योंकि यहां चंडीगढ़ में मंत्री बनकर आने के बाद मुझे एयर कंडीशन में रहने का मौका मिला है इसलिए मुझे यह दिक्कत हो गई थी। जिन सदस्यों को विटामिन–डी की कमी आती है उन्हें रोजाना नाश्ते में खुम्बी/मशरूम का प्रयोग करना चाहिए। खुम्बी/मशरूम को तोड़ने के बाद जब धूप में रखते हैं तो यह मनुष्य की तरह विटामिन–डी लेती है। निःसंदेह यह जानकारी अफसर साहेबान के भी काम आयेगी। इसके पकाने से भी इसके अन्दर विद्यमान विटामिन–डी में कमी नहीं आती है। मनुष्य के शरीर के अलावा यह विटामिन–डी का एक दूसरा ऐसा नैचुरल स्रोत है जो सीधे विटामिन–डी लेता है। यह जानकारी सबके काम की है इसलिए मैंने इसको सदन में सबके समक्ष बताया है क्योंकि इस जानकारी का प्रयोग करके मुझे लाभ हुआ है। दूसरी बात मैं सदन के समक्ष कहना चाहूँगा कि जहां कहीं भी नैचुरली कृषि जोन डिवेलप हो रहे हैं, उन सभी को प्रोटैक्ट करना, आगे बढ़ाना, संरक्षण व सुविधायें देने का काम सरकार की तरफ से निश्चित रूप से किया जायेगा। अब मैं गन्नौर मंडी के बारे में सदन के समक्ष बताना चाहूँगा। निःसंदेह यह हरियाणा की एक प्रेस्टिजियस मंडी है और यदि पिछली सरकार के समय इस मंडी पर गम्भीरतापूर्वक

विचार किया जाता तो आज यह मंडी डिवैल्प हो जाती। 600 एकड़ में फैली गन्नौर की इस विशाल मंडी की डी.पी.आर. रांगिस पेरिस जो कि फ्रॉस की प्रोजैक्ट मैनेजमैंट ऐजेंसी ने बनाई थी जिसे पिछली सरकार ने नाराज करके वापिस भेज दिया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वह नाराज होकर क्यों चले गए और उन्होंने इस काम को क्यों छोड़ दिया। भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि इतनी बड़ी मंड़ी को एक तरह से डिवेलप करने की जिम्मेवारी ले ले। मैं माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम डे–टू–डे इस मंडी को जल्द से जल्द चलाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में अभी हमें एक टैंडर भी प्राप्त हुआ है लेकिन आप जानते हैं कि केवल एक टैंडर के उपर यदि निर्भर रहेंगे तो तमाम तरह की दिक्कतें सरकार को पेश हो सकती हैं लेकिन मेरी आज सदन के माध्यम से माननीय कुलदीप जी को यह कमिटमैंट है कि हम डे–टू–डे पर इस मंडी को चालू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त एस.वी.पी.(स्पेशल व्हीकल परपज) बनाकर भी मंडी को जल्द से जल्द चालू करवाने का कार्य किया जायेगा। जहां तक बात है मंडी को 6 महीने में चालू करवाने की तो मैंने कभी भी इस तरह का आश्वासन नहीं दिया है लेकिन मेरा एक संकल्प जरूर है कि इसी सरकार के कार्यकाल में गन्नौर मंडी का कार्य पूर कर लिया जायेगा।

.....

Shortage of Doctors

***1755. Smt. Kiran Choudhary. :** Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of doctors in hospitals of Bhiwani District especially in Ch. Bansi Lal General Hospital, Bhiwani ; and

(b) if so, the time by which the vacant posts of doctors are likely to be filled up in the Government hospitals of Bhiwani district ?

Health Minister (Shri Anil Vij) :

(a) Yes, Sir.

(b) Upon the completion of the ongoing process for recruitment of doctors .

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की तरफ से बहुत ही फेक आंसर दिया गया है। चौधरी बंसी लाल मैडिकल कॉलेज में स्थित अस्पताल में डॉक्टर्ज न होने की वजह से बहुत बुरा हाल बना हुआ है। पहले तो यहां पर 58 डाक्टर्ज की ऑन लाईन ट्रांसफर्ज की गई और उसके बाद सारी की सारी ट्रांसफर्ज को कैंसिल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस बारे में जब मंत्री जी जवाब दें तो जरूर बतायें कि ऐसा क्यों किया गया? सरकार को सत्ता में आये अढ़ाई वर्ष हो चुके हैं लेकिन आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि डॉक्टर्ज की रिक्रूटमैंट पूरी नहीं हो पाई है। 58 डॉक्टर्ज की ट्रांसफर्ज को कैंसिल करने का मतलब तो यह हुआ कि सरकार हमारे इस अस्पताल में डॉक्टर्ज भेजेगी ही नहीं? माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि चौधरी बंसी लाल मैडिकल कॉलेज में स्थित अस्पताल में जल्द से जल्द डॉक्टर्ज की नियुक्ति की जाये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में कल भी यह बात कही थी कि प्रदेश में डॉक्टर्ज की बहुत कमी है। जैसा कि अभी माननीय सदस्या कह रही थी कि अढ़ाई साल सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए है, अतः डॉक्टर्ज की भर्तियां कब की जायेगी, के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी डाक्टर्ज की भर्ती की गई है और इस साल भी हमने 662 डॉक्टर्ज की भर्ती का विज्ञापन निकाला हुआ है जिसकी एवज में लगभग 1800 से ज्यादा ऐप्लीकेशंज प्राप्त हो चुकी हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हम नए डॉक्टर्ज को भर्ती कर लेंगे। डॉक्टर्ज की कमी के मामले को लीगली एग्जामिन भी करवाया जा रहा है और हमने निर्णय लिया है कि यदि भविष्य में कोई कानून बनाने की भी जरूरत पड़ती हैं तो हम ऐसा कानून जरूर बनायेंगे जिसमें यह प्रावधान हो कि जो लोग हरियाणा से एम.बी.बी.एस. करें उन्हें दो साल के लिए हरियाणा के सरकारी अस्पतालों मे नौकरी अवश्य करनी पड़ेगी। अगर यह संभव हुआ तो निःसंदेह आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर्ज की एक सीट की भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। जहां तक माननीय सदस्या ने 58 डॉक्टर्ज की ट्रांसफर्ज को कैंसिल करने के संबंध में प्रश्न पूछा है तो इस संदर्भ में

मैं बताना चाहूँगा कि इस टोटल लिस्ट को ही हमने कैंसिल कर दिया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमने केवल इन्ही की कांस्टीच्यूएंसी में डॉक्टर्स की ट्रांसफर्ज कैंसिल नहीं की थी बल्कि हमने सभी डॉक्टर्स की ट्रांसफर्ज कैंसिल कर दी थी । अगले महीने में जब ट्रांसफर्ज का सीजन आएगा तो उस समय हम डॉक्टर्स की ट्रांसफर्ज करेंगे । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम अगली ट्रांसफर्ज ऑनलाइन करेंगे । इससे जो डॉक्टर्स जहां जाना चाहेंगे वहां पर जा सकेंगे । विभाग में अंग्रेजों के जमाने का एक कानून था कि डॉक्टर्स होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी नहीं लग सकते । हमने डॉक्टर्स को सहूलियत देने के लिए इस कानून को खत्म कर दिया है । अंग्रेजों को तो इससे कोई डर होता होगा लेकिन हमें कोई डर नहीं है । स्पीकर सर, हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दें इसीलिए हमने रूल्ज में रिलैक्सशेन दी है । अब बेशक वे होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर लें । अब स्वास्थ्य विभाग में होम डिस्ट्रिक्ट में भी डॉक्टर्स लग सकते हैं । स्पीकर सर, हमारे प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग में बहुत सुधार आया है । स्पीकर सर, इस बात की आंकडें गवाही देते हैं । हमारी जो ओ.पी.डी. है वह इतने ही डॉक्टरों से 19.17 परसेंट बढ़ गई है । इसका कारण यह है कि हम व्यवस्था को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर महोदय, खानपुर मेडिकल कॉलेज की ओ.पी.डी. में एक दिन में 2500 मरीजों को देखने की क्षमता थी लेकिन आज यह संख्या घटकर 1400 रह गई है । It is very strange. (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 58 डॉक्टर्स के ट्रांसफर्ज किये थे जोकि कैंसिल कर दिए गए हैं । क्या माननीय मंत्री जी उन डॉक्टर्स को वहां वापिस भेजेंगें ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वहां पर 58 डॉक्टर्स की तो स्ट्रैंग्थ ही नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्या सदन में गलत इन्फर्मेशन प्रस्तुत कर रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, वहां पर अस्पतालों में मरीजों का बहुत बुरा हाल है । वहां पर डॉक्टर्स की आवश्यकता थी इसीलिए तो माननीय मंत्री जी ने 58 डॉक्टर्स को वहां भेजा था । (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, वहां पर डॉक्टरों की सैंग्शंड स्ट्रैंग्थ 55 है इसलिए नैचुरली हम 58 डॉक्टर्स की ट्रांसफर्ज कर ही नहीं सकते? वहां पर 55 डॉक्टर्ज की स्ट्रैंग्थ के अगेंस्ट 32 डॉक्टर्ज ऑलरेडी लगे हुए हैं । मैं पुनः बता रहा हूं कि वहां पर 32 डॉक्टर्स आज भी लगे हुए हैं । हुड्डा साहब इनके कान में उल्ट पुल्ट कहते रहते हैं और ये बोलती रहती हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को सत्य को इधर–उधर नहीं मोड़ना चाहिये । मैंने मंत्री जी से एक बात पूछी है कि जब इन्होंने खुद ही ट्रांसफर्ज किये हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर डॉक्टर्ज की कमी इतनी ज्यादा है । वहां डॉक्टर्ज की बहुत ज्यादा कमी है और मरीजों के बुरे हाल हो रहे हैं । अब मंत्री जी मुझे यह बता दें कि ये उनको वापिस वहां ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को ऑन द रिकॉर्ड एग्जैक्ट फिगर्ज बता देता हूं । वहां प्रिंसिपल मैडिकल ऑफिसर की सैंक्संड स्ट्रैंग्थ एक है जोकि वेकेंट है । सीनियर मैडिकल ऑफिसर की सैंक्संड स्ट्रैंग्थ 5 है जबकि 7 एस.एम.ओज. लगे हुए हैं । इस तरह वहां दो एस.एम.ओज. सरप्लस हैं । वहां जो दो एस.एम.ओज. सरप्लस हैं उन्हें हम कहीं और ट्रांसफर कर देंगे । वहां पर मैडिकल ऑफिसर्स की सैंग्शंड स्ट्रैंथ 55 है जिसमें से 32 पोस्ट्स भरी हुई हैं तथा 23 पोस्ट्स खाली हैं । ये एक्चुअल फिगर्ज हैं । अगर माननीय सदस्या यह प्रश्न मुझसे सीधे ही पूछ लेती मैं इन्हें वैसे ही बता देता । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने माननीय सदस्य से पूछकर ही क्वैश्चन लगाना हो तो विधान सभा में क्वैश्चन आवर की क्या प्रासंगिकता रह जाएगी । दूसरी बात यह है कि मैं सदन में ठीक बात कहती हूं । मैं गलत बात नहीं कहती हूं । मैं पूछना चाहती हूं कि जब मंत्री जी ने ऑनलाइन ट्रांसफर्ज किये हैं और फिर उनको कैंसिल किया है तो क्या वजह थी कि इतने सारे डॉक्टर्ज की पहले तो ऑनलाइन ट्रांसफर्ज की गई और फिर ट्रांसफर्ज कैंसिल की गई ?

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहती हूं कि डबवाली हलके का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर न तो आर्थोपैडिक डॉक्टर है, न ही कोई लेडी डॉक्टर है और वहां पर जितनी भी एक्स–रे मशीनें हैं वे सब खराब पड़ी हैं । मैंने चौटाला गांव के हॉस्पिटल के बारे में पिछले विधान सभा सत्र में भी माननीय मंत्री जी से कहा था कि वहां एक लेडी डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है । अभी 22 नवम्बर को गांव में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई । दुःख की बात है कि वहां पर अभी तक किसी लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है । वहां की सारी मशीनें बंद पड़ी हैं और वहां पर एक भी एम.ओ. नहीं लगा हुआ है । मुझे लगता है कि शायद मैंने ही आपको चिकित्सकों की कमी बारे सबसे ज्यादा लैटर लिखे हैं । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्या ने मुझे इस संबंध में बहुत पत्र भेजे हैं ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अगर माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं तो उन्हें हमारे वहां डॉक्टर की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आजकल हम किसी भी डॉक्टर की ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं । फिलहाल एग्जाम्स के दिन हैं और बच्चों के पेपर चल रहे हैं । ऐसे में अगर हम ट्रांसफर्ज करते हैं तो सारी फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाएंगी । अतः हमने डिसाइड किया है कि हम अगले महीने यानी मार्च–अप्रैल में जब नया सेशन शुरू होगा तो उस समय ट्रांसफर्ज करेंगे । इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर हम इन्हीं उपलब्ध डॉक्टर्स में से ट्रांसफर्ज करते रहे तो किसी जगह डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा और किसी जगह सीट खाली हो जाएगी । डॉक्टर्ज की ट्रांसफर्ज इस समस्या का प्रोपर समाधान नहीं है । इस तरह के बहुत सारे प्रश्न माननीय सदस्यगण के लगे हुए हैं जो डॉक्टर्ज की पोस्टिंग से संबंध रखते हैं। इस बात को मैंने स्वीकार किया है।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, डबवाली में लेडी डॉक्टर्ज डिलीवरी केसिज़ नहीं लेती है, इस ऐवज में औरतें कहाँ जाएंगी?

श्री अनिल विजः बहन जी, यदि हमारे पास लेडी डॉक्टर्ज उपलब्ध होंगी तो वहाँ पर नियुक्ति कर दी जायेगी। एक्स–रे की मशीन भी डबवाली में लगवा देंगे।

.....

Functioning of Sewerage System

***1676. Shri. Ved Narang.** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is fact that sewerage system is not functioning in Barwala and Millgate area: if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to made the above said sewerage system functional togetherwith the details thereof?

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : नही, श्रीमान् जी, इसलिए प्रश्न के इस हिस्से का सवाल ही नहीं उठता।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बरवाला शहर और बरवाला हल्के का मिलगेट क्षेत्र का एरिया जो नगर निगम हिसार में पड़ता है, दोनों ही जगह सीरवरेज़ व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। हालात तो यह है कि बारिश के दिनों में सप्ताह में 1–2 दिन पानी सड़कों पर और नीचे के एरिया में खड़ा रहता है। अध्यक्ष महोदय, आज तो हालत यह है कि सीवरेज़ व्यवस्था बंद होने की वजह से आम दिनों में भी सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। जिससे लोगों को आने–जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ बीमारियां भी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बार–बार यह बात उठाये जाने के बाद भी या तो अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं या सरकार सोई हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस विषय पर आज तक कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया है।

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, first read the question and then its answer. The question is – will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that sewerage system is not functioning in Barwala and Millgate

area: if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make the above said sewerage system functional togetherwith the details there? The answer of the Minister is – No, Sir; this part of the question, therefore, does not arise. What is this answer? Will the Minister explain what they mean by it? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन शर्मा जी का यह तरीका अच्छा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, यह आपका प्रश्न नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार बरवाला शहर की जनसंख्या 43384 के करीब है। इस शहर की पेयजल आपूर्ति दो नहरी आधारित योजना के द्वारा की जाती है। वर्तमान में बरवाला शहर में जल आपूर्ति की स्थिति 110 लीटर प्रति व्यक्ति की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है और मंत्री जी कुछ और बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि पानी और सीवरेज़ दोनों का इक्ट्ठा विभाग है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यदि माननीय सदस्य को अपने प्रश्न के उत्तर से संतुष्टि नहीं है तो फिर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं । लेकिन माननीय सदस्यों का इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, The Minister is not giving the correct answer. He is replying about the water supply while the question relates to the sewerage system. (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सीवरेज के बारे में बताएं ना की पानी के बारे में? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, प्लीज आज बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, The Minister is not ready with the answer. He is misleading the House. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नारंग जी, मंत्री जी पानी और सीवरेज़ दोनों का जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वेद नारंग का सवाल है और माननीय मंत्री जी प्रश्न का जवाब ठीक ढंग से दे रहे हैं लेकिन उसे देने नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) सभी मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में आते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह बात अलग है कि पंडित कुलदीप शर्मा जी स्पीकर रहे हैं परन्तु उनकी अंग्रेजी श्रीमती किरण चौधरी जी से अच्छी नहीं है और वे अंग्रेजी में हमको डाट मारते हैं। बहुत अच्छा सवाल वेद नारंग जी ने पूछा है। डॉ0 बनवारी लाल जी बहुत अच्छा जबाव दे रहे हैं।

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, he is the fourth Minister who has stood to reply this question.

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, जब शर्मा जी इधर बैठते थे तब भी शोर करते थे और अब भी शोर कर रहे हैं।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः गोयल जी, वे शोर नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने समय की पुरानी बात बता रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के समय में जब मैं विपक्ष की सीट पर बैठता था और माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी स्पीकर की चेयर पर बैठते थे तो उस समय इन्होंने मुझे भी धमकाया था और मैंने इनके खिलाफ एक एफ.आई.आर. चण्डीगढ थाने में दर्ज करवाई थी जो आज भी थाने में पैंडिंग है। सर, इसी तरह से आज शर्मा जी एक एस.सी. मिनिस्टर को धमका रहे हैं, मेरा यह कहना है कि प्रिविलेज मोशन लाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Kuldeep Sharma: Speaker Sir, it is not a reply.

श्री अध्यक्षः शर्मा जी आप बैठिये, माननीय मंत्री जी जबाव दे रहे हैं ?

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष जी, आज भी माननीय सदस्य के खिलाफ चंडीगढ थाने में दर्खास्त पैंडिंग है। मैंने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दरखास्त दे रखी है।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सवाल का जबाव देने की बजाय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, बैठिए माननीय मंत्री जी डिटेल में रिप्लाई दे रहे हैं। अतः पहले उनको अपनी बात पूरी करने दें ?

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, अगर विपक्ष सवाल पूछता है और मंत्री जी अपने डिफेंस में कास्ट का बहाना बनाकर कहते हैं कि एक शिडयूल कास्ट मिनिस्टर से जबाव पूछा जा रहा है। यह बात ठीक नहीं है। क्या एक मंत्री की यही कैपेबिलिटी होती है ? (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः नहीं, ये तो इन्होंने वैसे ही कह दिया होगा। मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।(शोर एवं व्यावधान)

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है वही अपनी सप्लीमैन्ट्री पूछ सकता है दूसरा सदस्य बीच में इन्ट्रप्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई सदस्य करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, I can raise the supplementary. (शोर एवं व्यावधान)

श्री पिरथी सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए।(शोर एवं व्यावधान)

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारी बात सुनिए।(शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः श्री पिरथी सिंह जी क्या आपको जबाव नहीं चाहिए। नारंग जी आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले बोलना बन्द करें तभी मंत्री जी जवाब दे सकेंगे।

डॉ0 बनवारी लालः स्पीकर सर, बरवाला शहर की सीवरेज सिस्टम प्रणाली का कार्यात्मक व सुचारू रूप से चल रही है तथा सीवर की गाद/मिट्टी निकालने के लिए बकैट टाईप मशीनों द्वारा कार्य किया जा रहा है। नई अनुमोदित कालोनियों में सीवर लाईन बिछाने का कार्य अनुमान 250 और 407 लाख के अन्तर्गत किया जा रहा है और 157.4 लाख रूपये का बजट पहले ही आबंटन किया जा चुका है। (शोर एवं व्यवधान) मिल गेट क्षेत्र बरवाला शहर का क्षेत्र 50 प्रतिशत सीवरेज सिस्टम 8 व्यास और 30 व्यास तक पहले से ही लाभांवित है शेष क्षेत्र को लाभांवित करने के लिए तथा मौजूदा सीवरेज सिस्टम दुरूस्त करने के लिए 630 लाख रूपये की राशि वर्ष 2012– 2013 में अनुमोदित हो चुकी है। लेकिन यह रेतीला क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में काम रुका हुआ था इसी कारण आर.सी.सी सीवर पाईप की जगह एच.डी.पी.ई. पाईप टैंडरलैस तकनीक का बदलाव किया गया है मिल गेट क्षेत्र में टैंडरलैस तकनीक द्वारा एच.डी.पी.ई. पाईपलाईन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और मिल गेट क्षेत्र को मुख्य सीवर से जोड़ दिया गया है तथा इस क्षेत्र की सीवर लाईन प्रणाली कार्यात्मक और सुचारू रूप से चल रही है जिसे 15.2.2017 से जोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्षः वेद नारंग जी, मंत्री जी ने आपके सवाल का डिटेल में रिप्लाई दे दिया है।

श्री वेद नांरगः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सरकार की भावी योजनाओं के बारे में बताया है लेकिन मेरा सवाल यह था कि बरवाला और मिलगेट क्षेत्र में जो सीवरेज सिस्टम खराब पड़ा है उसको चालू किया जाएगा या नहीं। (शोर एवं व्यवधान) इसके बारे में कोई जबाव नहीं दिया है।

श्री अध्यक्षः वेद नांरग जी, मंत्री जी ने आपके सवाल का डिटेल रिप्लाई दे दिया है। जयप्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछें। (शोर एवं व्यवधान) आप कितने सप्लीमैंट्री पूछेंगे? आप केवल दो सप्लीमैंट्री ही पूछ सकते हैं, जिनमें आप दोनों के दोनों पूछ लिए और उसका जवाब भी आपको मिल गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का विरोध करता हूं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं ।

गुरु नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर के अध्यापकों एवं छात्रों का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मैं सदन की जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूं कि गुरुनानक गर्ल्ज कॉलेज सन्तपुरा (यमुनानगर) के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरा आपसे एक अनुरोध करता हूं (विघ्न)

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन आवर चल रहा है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, कृपया उन्हें जवाब देने दें। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाना बाकी है।

श्री अध्यक्ष : नायब सैनी जी, कोई बात नहीं अभय सिंह जी को बोलने दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आपका जब क्वेश्चन आवर होता है और जिस मंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता हो और यदि मंत्री बैठे हो तो केवल और केवल या तो मंत्री जी जवाब दें या पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बताएं।

श्री अध्यक्ष : सारा जवाब तो मंत्री ने ही बताया है, इनके अलावा तो जवाब किसी ने नही दिया। जब टोका–टिप्पणी उधर से आती है तो इधर से कोई बोलता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं कृपया आप उस पर जरूर ध्यान दें। जितने भी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनसे आप ये जरूर कहें कि जो भी क्वेशन उनसे पूछे जाते हैं वे उसी से रिलेटेड जवाब दें तो ज्यादा अच्छा है। बजाय उसको घुमा फिराकर के अपने आपको बचाने का प्रयास न करें और दूसरे मंत्रियों से भी कहें कि वे भी इस मामले में खड़े न हों। (हंसी)

वाक–आउट

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है इसलिए एज ए प्रोटैस्ट मैं सदन से वॉक–आउट करता हूँ।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री वेद नारंग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा दिए गए उनके प्रश्न के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉक–आउट कर गए।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Extension of Grain Market

***1714. Shri Jai Parkash.** : Will the Agriculture Minister be pleased to state the time by which the extension work of the Grain Market of Kalayat is likely to be completed ?

कृषि मंत्री (ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, इस मंडी के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है अतः इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जयप्रकाश जी ने कलायत अनाज मंडी के विस्तार कार्य के पूरा होने के बारे में अपना प्रश्न पूछा है। माननीय सदस्य जी को भी यह मालूम है कि इस अनाज मंडी का विस्तार विभाग भी करना चाहता है। इस मण्डी को बनाने के लिए विभाग द्वारा 42 एकड़ 2 कैनाल 7 मरले जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाया हुआ है और इसके बारे में अधिसूचना

जारी हो गई है। लेकिन इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगा हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे किसी तरह से सभी लोगों की सहमति करके इस बारे में कोई रास्ता निकलवायें ताकि उस मंडी को हम तुरंत बना सकें और विभाग की भी यही इच्छा है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह तो बात सही है, कल आपके प्रिंसिपल सैक्रेट्री साहब का फोन मुझे आया था उन्होंने बताया कि एक आदमी ने अपना केस विड्रॉ नहीं किया है बाकि सभी लोगों ने अपने केस विड्रॉ कर लिए हैं। इसके लिए थोड़ा सरकार प्रयास करे और थोड़ा मैं भी प्रयास करूंगा। हम चाहते हैं कि अनाज मंडी वहां पर जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि वहां पर फसल बहुत ज्यादा आती है और वह बहुत ही पुरानी मंडी है। पिछली सरकार ने इस अनाज मंडी को बनाने के लिए मंजूर किया था। कृपया उसको जल्दी बनवाया जाए। मैं इसके लिए एक सुझाव देता हूं, जब तक यह मामला सब्जूडिश है, तब तक सरकार वहां पर सड़कें बना दें, क्योंकि वहां पर दो छोटी–छोटी सड़कें हैं। कलायत अनाज मंडी से खरक पाण्डु तक और कलायत से आई.टी.आई तक ड्रेन के साथ जो जमीन है वह जमीन सरकार की है। आप वहां पर जल्दी से सड़कें बना दें, क्योंकि वहां धान के सीजन में बहुत बुरा हाल होता है। वहां पर लोगों को अपना धान लाने और बेचने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर एक छोटी 2 किलोमीटर की ही सड़क है।

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी आप मण्डी के विस्तार की बात करते करते सड़कों के बारे में बात करने लग गए हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 के बाद से उस मण्डी की एक्सटेंशन नहीं हुई है और 1962 के बाद से हमारे किसान की पैदावार ग्रीन रेवील्यूशन को लेकर के बढ़ गई है, इस कारण वहां पर ट्रैफिक बहुत कंजस्टेड हो जाता है और जाम लग जाता है। वहां पर अनाज मण्डी से आई.टी. आई कलायत तक दो छोटी सड़क भी बनवा दी जाए, जिससे सड़क पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और यह बड़ा अच्छा होगा। इन सड़कों से फसलों को मण्डी में ले जायेगा। सरकार इन दो सड़कों की आज घोषणा कर दें, जिससे जब किसान फसल लेकर मंडियों में आए तो उसे जाम का सामना नहीं करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जमीन भी एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कलायत से खरकपाण्डू और कलायत अनाज मण्डी से आई.टी.आई. तक की दो सड़कों को बनाने की मांग की है । इन दोनों सड़कों के बारे में हम जानकारी ले लेंगे यदि ये वायबल होंगी तो बना दी जायेगी।

.....

Construction of ROB

***1768.Shri Udai bhan. :** Will the PW(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Railway over bridge on Bamni Khera-Hassanpur road in Hodal Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : जी हां, सर। रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जनरल अरेंजमैंट ड्राईंग के आधार पर डीपीआर तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड द्वारा ऋण की स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य आरम्भ किया जाएगा।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस आर.ओ.बी. को बनाने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों द्वारा घोषणा की हुई है । पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 2013 में और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने 2015 में इस आर.ओ.बी. को बनाने की घोषणा की थी । मौजूदा सरकार को बने हुए अढ़ाई साल का समय हो गया लेकिन इस आर.ओ.बी. को बनाने के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई । दूसरे कामों को प्रायोरिटी दी जा रही है । पलवल और हसनपुर की यह मुख्य लाईन है । इस आर.ओ.बी. को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है । मंत्री जी हमें यह जानकारी दें कि इस आर.ओ.बी. को बनाने की मंजूरी कब तक मिलेगी और इस पर कार्य कब शुरू होगा ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह मेरी जानकारी में नहीं है कि पिछली सरकार में इस आर.ओ.बी. को मंजूर किया था । हमने अढ़ाई साल के शासन में तकरीबन 24 आर.ओ.बी. बनाये हैं, 30 ओर.ओ.बीज. पर कार्य चल रहा है और आने वाले साल में 49 आर.

ओ.बीज. पर काम शुरू कर देंगे । जहां तक माननीय सदस्य ने बामनी खेड़ा–हसनपुर आर.ओ.बी. बनाने की मांग की है । यह केस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड में भेजा हुआ है । उनके बोर्ड की जल्द ही मीटिंग होने वाली है जिसमें इसकी एप्रूवल मिल जायेगी । उसके बाद जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में 37 करोड़ रुपये के काम कर दिए गए हैं और 36 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं । (विघ्न)

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में ज्यादातर सड़कों की हालत बहुत खराब है और मंत्री जी कह रहे हैं कि 37 करोड़ रुपये के कार्य कर दिए गए हैं। हमें नहीं पता कि वे कार्य कहां किए गए हैं ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 2005 में भी विधायक थे और इनकी सरकार भी थी । उस समय तो इन्होंने अपने हल्के में कोई काम नहीं करवाया ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा था कि यदि किसी की सड़क खराब है तो उसकी फोटो खींचकर व्हाट्स–एप पर भेज देना, सड़क का काम करवा दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, आज तक न तो व्हाट्स–अप नम्बर मिला और न ही काम किए गए ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मैं मंत्री बना उस समय नैयना चौटाला जी के सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि आपकी सभी सड़के बनवा दी जायेंगी । अध्यक्ष महोदय, अगले ही दिन किरण चौधरी जी मेरे पास अपने हल्के की 38 सड़कों की लिस्ट लेकर आ गई कि इन सड़कों को बनवा देना । मैंने कहा बहन जी मैं तो कल ही मंत्री बना हूं आप तो दस साल तक मंत्री रही हैं, क्या उस समय आपने कोई काम नहीं करवाया ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अढ़ाई साल का समय हो गया उन 38 सड़कों में से मंत्री जी ने एक भी सड़क आज तक नहीं बनवाई है । जबकि मंत्री जी ने यह भी कहा था कि व्हाट्स–एप पर सड़क की फोटो खींचकर भेज देना तुरंत सड़क बनवा दी जायेगी ।

राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के बारे में मैं बहन जी को कल जवाब दूंगा कि कौन–कौन सी सड़क बनवाई है ।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन किरण चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि खेड़ी मोड़ से भिवानी की सड़क को चौड़ा करने का कार्य मंत्री जी करवा रहे हैं । जिस पर आज भी काम चल रहा है । इसके लिए ये मंत्री जी का धन्यवाद करें ।

श्री जय तीर्थ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसवां मिल–बहादुरगढ़ रोड़ पर बिंदरोली आर.ओ.बी. का 12.1.2017 को उद्घाटन कर दिया लेकिन वहां गड्डे पड़े हुए हैं । उसका पूरा काम भी नहीं हुआ है और ट्रैफिक आने–जाने में बहुत दिक्कत हो रही है । इस तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें ।

.....

Industrial Package for Haryana

***1717. Sh. Ram Chand Kamboj :** Will the Industries & Commerce Minister be please to State:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to announce any special Industrial Package for setting up Industry in Rania Assembly constituency; and

(b) whether the Government provides any special subsidy for setting up Industries in such type of backward areas?

11.00 बजे

उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री (श्री विपुल गोयल) : अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रश्न के संबंध में विवरण इस प्रकार हैः–(क) नहीं, श्रीमान जी तथा (ख)हां, श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, श्री राम चन्द कम्बोज जी द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि रानिया विधान सभा क्षेत्र के लिए गवर्नमैंट और इण्डस्ट्री ने किसी स्पैसिफिक आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की है। औद्योगिक दृष्टि से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश को किसी जगह विशेष की वस्तुस्थिति के हिसाब से, उद्योगों के प्रकार के हिसाब से और वहां के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ए, बी, सी और डी चार भागों में बांटा है। इसके तहत

चार तरह के पैकेज सरकार ने तय किये हैं। रानिया हल्का डी कलस्टर के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा सबसिडी का प्रावधान डी कलस्टर के तहत किया गया है। इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री रामचन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। मेरा पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ हां और ना में ही जवाब मेरे पास आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरा रानिया विधान सभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर कोई भी उद्योग लगता है तो उसका रॉ मैटीरियल खेती से ही मिलता है। चाहे धान, गेहूं और कपास की खेती से जुड़ी कोई भी इण्स्ट्री हो। मैं यहां यह बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि कपास की खेती में तो मेरे क्षेत्र का पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला स्थान है। मैं आपके माध्यम से मानीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डी कैटेगरी में मेरे रानिया विधान सभा क्षेत्र को डाला गया है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने सिरसा जिले के पन्नी वाला मोटा में शूगर मिल लगाने का काम किया था। उसके बाद जो 10 साल का कांग्रेस पार्टी का शासन काल रहा उस दौरान मेरे रानिया विधान सभा क्षेत्र में जो कि पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है उसमें कोई भी रोजगारपरक उद्योग नहीं लगाया गया। यह आप सभी मानते हैं कि किसी भी इलाके का विकास उद्योगों पर निर्भर करता है। वर्तमान सरकार ने यह नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास लेकिन अगर गुरूग्राम और रानिया की तुलना की जाये तो हमें जमीन–आसमान का अंतर नजर आता है। यह जो मेरा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ है मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत सरकारी स्तर पर मेरे रानिया विधान सभा क्षेत्र में कुछ बड़े और छोटे उद्योग विशेष तौर पर स्थापित करके वहां का औद्योगिक पिछड़ापन दूर किया हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस दिशा में कब तक काम शुरू कर दिया जायेगा?

श्री विपुल गोयल : स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य ने पूछा है इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहूंगा कि टैक्सटाईल सैक्टर, एग्रो इण्डस्ट्री और इनफ्रॉस्ट्रक्चर रिलेटिड इण्डस्ट्री रानिया क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार के उद्योग अगर वहां पर लगते हैं तो उनको डी कैटेगरी के तहत जो भी रियायतें

देय हैं वे निर्विवाद रूप से मिलेंगी। ये रियायतें देने का प्रावधान हमने इस पॉलिसी में रखा हुआ है। इसी प्रकार से सरकार की टैक्सटाईल पॉलिसी भी जल्दी ही आनी वाली है। रानिया क्षेत्र में जो भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहेगा उसको ये सारे के सारे इंसैंटिव दिये जायेंगे।

श्री रामचन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये उद्योग कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे।

श्री विपुल गोयल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि सरकार अपने उद्योग नहीं लगाती जो भी इनवैस्टर अपने उद्योग लगाते हैं सरकार उन लोगों को इंसैंटिव देने का काम करती है। इसके अलावा सरकार एक और पॉलिसी लेकर आ रही है कि अगर कोई उद्योगपति पंचायतों की जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है तो वह भी बिजनैसमैन को दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Declaration of Forest Area In Village Mangar

***1701.Shri. Karan Singh Dalal**. : Will the Forest Minister be pleased to state :-

(a) the total area of village Mangar in District Faridabad is likely to be declared as forest area; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to acquire such area to maintain Green Hub ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रश्न का विवरण इस प्रकार हैः–

(क) वर्तमान में जिला फरीदाबाद के गांव मांगर में कोई क्षेत्र वन घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

.....

Tohana To Hisar Bus Service Via Uklana Mandi

***1758. Sh. Anoop dhanak. :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start Bus service from Tohana to Hisar via Uklana Mandi; if so, the time by which the said bus service is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्री मान जी, टोहाना से हिसार वाया उकलाना मण्डी बस सेवा पहले से ही संचालित है।

.....

Construction of Bridge on Agra Canal

***1772. Sh. Tek Chand Sharma.** : Will the PW (B&R) Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the new bridge on the Agra Canal in Village Chandwali on Ballabhgarh Mohana route in place of old bridge ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Total Number Of Pensioners

***1726.Shri Jaiveer Singh.** : Will the Minister of State for Social Justice & Empowerment be pleased to state the total number of pensioners to whom old age and widow pension has been released in the state during the period from November, 2014 till to date togetherwith the details thereof?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : श्रीमान् जी, संबंधित संख्या इस प्रकार हैः–

क्रम सं0	वर्ष	अदायगी किये गये बुढ़ापा पेंशनरों की संख्या	अदायगी किये गये विधवा पेंशनरों की संख्या
1.	2014–15 (अदायगी 03/2015 में)	1399122	599662
2.	2015–16 (अदायगी 03/2016 में)	1368551	585653
3.	2016–17 (अदायगी 02/2017 में)	1432380	629857

Upgradation of School

***1734 Sh. Lalit Nagar. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the High school in village Sehatpur of Tigaon Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान्, राजकीय उच्च विद्यालय सेहतपुर को शैक्षणिक सत्र 2017–18 से वरिश्ठ माध्यमिक के स्तर तक स्तरोन्नत करने का निर्णय ले लिया गया है।

.....

To Metal The Unmetalled Passage

***1783.Shri Om Prakash Barwa.** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under

consideration of the Government to metal the unmetalled passage from Loharu Town to village Ladanda; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :नहीं, श्रीमान् जी, लोहारू कस्बे से गांव लाडन्दा तक के कच्चे रास्ते को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Sugar Mills in Heavy Loses in State

***1975.Smt. Prem Lata:** Will the Co-Operation Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the co-operative sugar mills in the State are running in heavy loses; if so, the details of the accumulated loses of all the sugar mills separately ;

(b) whether there is any scheme/plan to made these sugar mills profitable ; and

(c) if so, whether there is any proposal to convert these sugar mills as composite sugar complexes where zero waste concept can be achieved ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) मिलानुसार संचित हानि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रूपये करोड़ों)

मिलों के नाम	आरम्भ से 2015–16 तक संचित (+)लाभ (-)हानि
पानीपत सहकारी चीनी मिल लि0 पानीपत	-252.63
हरियाणा सहकारी चीनी मिल लि0 रोहतक	-261.01
करनाल सहकारी चीनी मिल लि0 करनाल	-136.21
सोनीपत सहकारी चीनी मिल लि0 सोनीपत	-220.87
शाहबाद सहकारी चीनी मिल लि0 शाहबाद	-33.92
जींद सहकारी चीनी मिल लि0 जींद	-225.56
पलवल सहकारी चीनी मिल लि0 पलवल	-181.57
महम सहकारी चीनी मिल लि0 महम	-281.03
कैथल सहकारी चीनी मिल लि0 कैथल	-289.91
चौ0 देवी लाल सहकारी चीनी मिल लि0 गोहाना	-174.33
हैफेड सहकारी चीनी मिल असंध	-92.73
कुल	**-2149.77**

चीनी मिलों को लाभदायक बनाने का संबंध मुख्य रूप से चीनी की कीमतों पर निर्भर करता है जोकि गन्ने की कीमत, घरेलु आपूर्ति व मांग, अन्तराष्ट्रीय चीनी की कीमतें तथा बाजार की धारणाओं आदि पर निर्भर करती हैं। हालांकि, घाटे को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं जैसे किः–

1. गन्ने की किस्मों के संतुलन में सुधार।

2. अधिकतम चीनी प्राप्ति के लिए, मिल के अधिकृत क्षेत्र में गन्ने की अधिक चीनी वाली अगेती किस्मों को बढ़ावा देना।

3. चीनी मिलों द्वारा व्यवहार्य मुल्य वर्धित परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना। राज्य सरकार ने शाहबाद चीनी मिल में 60 किलोलीटर प्रति दिन क्षमता के इथेनॉल प्लांट की स्थापना, पानीपत सहकारी चीनी

मिल को गांव डाहर में 5000 टी.सी.डी विस्तारित क्षमता सहित बिजली उत्पादित संयत्र, डिस्टलरी/इथेनॉल प्लांट को पी.पी.पी मोड में तथा करनाल चीनी मिल के विस्तारीकरण एंव अधुनिकीकरण सहित 14 मैगावाट बिजली उत्पादित संयत्र लगाने की स्वीकृति दी है।

.....

To Create a New Block

***1708. Shri Aseem Goel.** : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to create a new Block by Bifurcating the Ambala-I block having 114 villages; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी; प्रश्न के इस भाग का, इसलिए सवाल नहीं उठता।

.....

Proper Disposal of Garbage

***1807.Shri Pirthi Singh Namberdar:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the Garbage of Narwana City is being thrown openly by the Municipal Committee; and

(b) If so, whether there is any proposal under onsideration of the Government for proper disposal of the Garbage?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री कविता जैन) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) इसलिए प्रश्न का यह भाग प्रासंगिक नहीं है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Shortage of Teachers

418. Sh. Jagbir singh malik.:Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is shortage of teachers/masters/lecturers in Government Schools in Gohana constituency; if so, the details thereof; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to meet out the shortage of teachers in schools of Gohana Constituency?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्री मान जी, संबंधित प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से हैः–

(क) हाँ, श्रीमान जी, गोहाना विधान सभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0 संख्या	**पद संज्ञा**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पद**	**अतिथि अध्यापक**
1	प्राधानाचार्य	25	19	6	0
2	मुख्याध्यापक	14	7	7	0
3	प्रवक्ता	394	284	110	21
4	मुख्याध्यापक मौलिक विद्यालय	55	43	12	0
5	मास्टर	286	156	130	23
6	सी0एण्डवी0	236	160	76	3
7	मुख्य शिक्षक	63	13	50	0

8	जे0बी0टी0 अध्यापक	246	218	28	7
	कुल	1319	900	419	54

(ख) अध्यापकों के रिक्त पदों को पदोन्नति/वैज्ञानीकरण/सीधी भर्ती के माध्यम से शीघ्र भरा जाएगा जिस हेतु प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

.....

Depleting Ground Level in Haryana

407. Shri. Ram Chand Kamboj. : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that the ground water level is depleting in whole Haryana; if so, whether any policy has been framed by the Government to check the problem of depleting ground water level togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (ओम प्रकाश धनखड) : श्रीमान्जी, यह बयान सदन के पटल पर रखा गया है।

बयान

जी हां, राज्य के भू–जल स्तर में गिरावट आई है। राज्य में भू–जल के अधिक दोहन को रोकने तथा जल सरक्षंण के उपायों को अपनाने व किसानो को लाभ देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैः–

1 हरियाणा राज्य भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम, 2009श लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 15 मई से पहले धान की बिजाई व 15 जून से पहले धान की रोपाई को प्रतिबन्धित किया गया है ।

2 विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 से राज्य में कम पानी वाले क्षेत्रों में भू–जल पुनर्भरण के लिये श्त्वरित भू–जल पुनर्भरणश नामक राज्य योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 2016 तक 677 पुनर्भरण ढांचों का निर्माण किया गया है।

3 विभाग द्वारा सिंचाई जल की बचत के लिये किसानों को टपका तथा फव्वारा सिंचाई ढ़ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा राज्य में वर्ष 2015–16 तक 1,65,166 फव्वारा सयंत्र लगाये जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 तक 2,74,976 हैक्टेयर क्षेत्र में टपका सिंचाई पर 20329.01 लाख रूपये खर्च किए गए हैं।

4 जल के रिसाव एवं वाष्पीकरण के नुक्सान से बचाने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 से भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 तक 2,06,223 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाईप लाईन विछाने पर 242.645 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं।

5 लेजर लेवलर द्वारा वैज्ञानिक ढ़ग भूमि समतलीकरण से फार्म इनपुटस को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक कुल 5150 लेजर लेवलर अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

6 जीरोटीलेज तकनीक के प्रयोग को प्रदर्शनों एवं सहायता प्रदान करके विभाग द्वारा बढावा दिया जा रहा है। वर्ष 2001–02 से 2015–16 तक कुल 25,581 जीरो–टिल–शीड–कम–फर्टीलाईजर–ड्रील मशीनें पूर्व में ही हरियाणा के किसानों को अनुदान पर प्रदान की जा चुकी हैं।

7 राज्य में प्राकृतिक जल संसाधनों के सरंक्षण के लिए धान की सीधी बिजाई एंव फसल विविधिकरण कार्यक्रम को लागू किया गया है। सीधी बिजाई के धान को रोपण के बजाय सीधे ही खेत में बोया जाता है जिससे पानी, श्रम व उर्जा की 15– 20 प्रतिशत तक बचत होती है और प्राकृतिक संशाधन संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, सूरजमूखी एवं गर्मियों मूंग आदि को ज्यादा पानी लेने वाली धान के स्थान पर पदोन्नत किया जा रहा है।

8 जल स्तर की गहराई एवं गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए जिला रोहतक, झज्जर, करनाल तथा कुरूक्षेत्र के सभी 23 खण्डों में डिजीटल वाटर डाटा लोगर्स वर्ष 2011–12 में स्थापित किए गये थे। शेष 17 जिलों में भी डिजीटल वाटर डाटा लोगर्स वर्ष 2012–13 में स्थापित किये जा चुके है।

9 किसानों को भू–जल सरंक्षण तथा सिंचाई के पानी के सदुपयोग बारे शिक्षित करने के लिए समय समय पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाये जा रहे है।

.....

Project For Discovery of Sarasvati River

413. Shri Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The details of the project launched for discovery of Saraswati River in the state;

(b) The scientific evidence/material relied on by the government in respect of ‘a’ above; and

(c) The amount sanctioned for the project at ‘a’ above together with the status of the project?

90

सरस्वती नदी की खोज के लिए परियोजना

❖ 413 श्री करण सिंह दलाल, विधायक : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे–

(क) राज्य में सरस्वती नदी की खोज के लिए आरम्भ की गई परियोजना का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ऊपर 'क' सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस वैज्ञानिक प्रमाण/सामग्री पर भरोसा किया गया;तथा

(ग) ऊपर के भाग 'क' में परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा परियोजना की स्थिति क्या है ?

उत्तरः

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा :

श्रीमान जी,

(क) अधिसूचना कमांकः 1/13/2015–आई.पी. दिनांक 12.10.2015 को सरस्वती नदी का संरक्षण, बांध और जल स्रोत, (जलाशय);पुरापाषाण (पेलियो चैनल) नदी मार्ग विकास; नदी का आगे का विकास; पुरातात्विक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक केन्द्र विकास; सरस्वती तीर्थों का विकास; पर्यावरणीय प्रभावी अध्ययन, निर्धारण एवं प्रबन्धन योजना; प्राचीन सरस्वती नदी मार्ग पर जल स्रोतों का संरक्षण/पारिस्थिति की कायाकल्प और अनुसंधान के लिए नदी, सरस्वती नदी और इसकी धरोहर के बारे शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) सरस्वती नदी एवं धरोहर विकास के लिए वैज्ञानिक प्रमाण/सम्बन्धित सामग्री सरकार द्वारा अनेक संतोषजनक स्रोतों से ली गई है। वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को वर्ष 2015–16 के लिए 3.01 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2016–17 के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

परियोजना की स्थिति वक्तव्य में मौजूद है।

91

वक्तव्य

~~अतारांकितप्रश्नसंख्या 413 श्री करण सिंह दलाल, विधायकपरवक्तव्य~~

वैज्ञानिकसाक्ष्य

विलुप्त नदी के अस्तित्व के असंख्य वैज्ञानिक साक्ष्य है। बोर्ड मुख्यतः निम्नलिखित पर निर्भर हैः–

1. **"पेलियो चैनलस आफ नार्थ वेस्ट इण्डियाः** (रिव्यू एण्ड एसैसमेन्ट" रिपोर्ट आफ दि एक्सपर्ट कमेटी टूरिव्यू एवलेबल इन्फारमेशन आन पेलियो चैनलस)
   15 अक्तूबर, 2016 (वेबसाइट http://mowr.gov.in/writereaddata/PalaeochannelExpertCommittee_15thOct2016.pdfपरउपलब्ध है)।
2. भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, ओ.एन.जी.सी, इसरो, हरसैक, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड इत्यादि के अध्ययन के मुख्य प्रसंग विभिन्न सम्बंधित पूर्व अध्ययन की जानकारी (वेबसाइट http://hshdb.in/studies/पर उपलब्ध है)।

परियोजना की स्थिति

1. भू–राजस्व रिकार्ड के अनुसार सरस्वती नदी का निशान देही का कार्य पूरा हो चुका है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र/रिकार्ड के अनुसार निशानदेही का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2. घग्घर–सरस्वती नदी के प्रवाह की निरन्तरता को सुचारु रुप से रखने हेतू से, आदिबद्री से घग्घर–सरस्वती के मुहाने तक नदी के सभी अंतरालों, बंधों एवं धाराओं की पहचान कर ली गई है और इस 204 किलोमीटर लंबे प्रवाह मार्ग में से 190 किलोमीटर क्षेत्र मे आंतरिक अवरोधों के लिए खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है।
3. सरस्वती नदी के निरन्तर धारा के जल स्रोत चिन्हित करने का कार्य प्रगति पर है।
4. सरस्वती नदी के पेलियों चैनलों की पहचान एवं मानचित्रण का कार्य हरसक, केन्द्रीय भू–जलबोर्ड, इसरों से परामर्श करके लगभग पूरा कर लिया है और इसके प्रवाह को भी सुनिश्चित कर दिया है।
5. जुलाई 2016 के दौरान शाहाबाद फिडर के माध्यम से यमुना नदी के बाढ़ के अतिरिक्त जल का प्रयोग करके सरस्वती नदी का पहली बार

उंचा–चांदना, यमुनानगर से पिपली, कुरूक्षेत्र तक सफल परीक्षण किया गया।

6. जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ओ.एन.जी.सी ने 10 अन्वेषणात्मक कुओं को सैद्धांतिक सहमति दी है।

7. यमुनानगर और कुरूक्षेत्र जिले की 18 ग्रामीण सड़कों पर पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे 30–6–17 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

8. सरस्वती नदी की तरफ जाने वाले प्रदूषित जल का उपचार करने के लिए कुरूक्षेत्र शहर में मल उपचार संयंत्र का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार सीचेवाल मॉडल पर आधारित गांव के प्रदूषित जल के उपचार के लिए यमुनानगर के 19 तथा कैथल के 5गांवों की पहचान की गईहै।

9. हरियाणा राज्य में पहली बार सरस्वती नदी प्रवाह मार्ग के सभी गाँवों का अक्श–शिज़रे का डिजिटाइजेंशन किया गया है।

10. भविष्य के संदर्भ के लिए सरस्वती नदी से सम्बन्धित सभी मानचित्र, सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो द्वारा लिए गए उपग्रह मानचित्र तथा हरसेक से लिए गए उपग्रह मानचित्र औरइसरो से पुरा पाषाण नदी (पेलियो चैनल) मार्गके चित्र भी प्राप्त किए गए हैं।

11. सरस्वती धरोहर सभी स्थानों मुख्यतः आदिबद्री, सरस्वती नगर, कुरूक्षेत्र, कलायत, कुनाल, भिंरडाना, राखी–गढ़ी के विकास के लिए भारत सरकार की स्वदेश–दर्शन योजना के तहत पर्यटन वृत के लिए विचारा गया है।इस प्रस्ताव का पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है औरउसी के लिए विस्तार परियोजना रिर्पोट का काम भी शुरू किया जा चुका है।

Total Number of Visitors

421. Shri. Parminder Singh Dhull. : Will the Tourism Minister be pleased to state the total number of tourists and wildlife enthusiasts visited the Kalesar National Park and Sultanpur National Park from April, 2015 to March, 2016 togetherwith the total revenue accrued from both the National Parks?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, नवम्बर, 2015 और मार्च, 2016 के बीच में कुल 1886 वन्य जीव प्रेमियों ने कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया और जिसके परिणामस्वरूप 58,230/– रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार, अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के बीच में कुल 57407 वन्य जीव प्रेमियों ने सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया और 4,99,610/– रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।

.....

To Construction an Auditorium

430. Sh. Jasbir Singh Deswal. : Will the information Public Relations & Languages Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an auditorium in Sub-Division,Safidon to promote the Folk Arts of our culture?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): नहीं श्रीमान जी, उप–मण्डल, सफीदों में सभागार निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

Construction of Bridge on Ghaghar River

426. Sh. Ravinder Singh Baliala. : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Bridge on

Ghaghar river to Link the villages Nathwan and Kanwalgarh; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हाँ, श्रीमान जी। अभी इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि निर्माण के लिए व्यवहारिता (फिज़ीबिलिट्ी) की जाँच की जा रही है।

.....

Construction of Multi Level Parking cum-Commercial Complex

443. Sh.Umesh Aggarwal. : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:

(a) The basis and terms and conditions on which the work was handed over to M/s International Infra Build Pvt. Ltd. of Multi Level Parking-cum-Commercial Complex in Sec.29, Gurugram after offering the tender.

(b) Whether the above said company had participated in the said tender, if so, the details thereof;

(c) Whether the said company fulfilled all the terms and conditions of the tender and deposited the full amount in HUDA in accordance with the terms and conditions; if so the details thereof;

d) Whether the said company had utilized excess area by violating the terms and conditions for commercial and parking purpose; and

(e) Whether any irregularities have come to the notice of Government; if so, the action taken by the Government against the delinquent persons?

उत्तर

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा :

महोदय,

बिंदु अनुसार सवाल का जवाब इस प्रकार है -

(क) सेक्टर 29, गुरुग्राम नजदीक एम्यूजमेंट पार्क / मेट्रो स्टेशन में पीपीपी आधार पर मल्टी-लेवल पार्किंग सह कमर्शियल काम्प्लेक्स के निर्माण करने का काम (साइट क्षेत्र 1.92 एकड़), मेसर्स इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड को निविदा आमंत्रित करने के बाद आवंटित किया गया था। बाद में, मेसर्स इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड के अनुरोध पर, इसकी सहायक कंपनी मेसर्स इंटरनेशनल इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को पार्किंग के निर्माण करने के लिए कंसेसियनार एग्रीमेंट क्रियान्वयन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दी गयी थी :-

(i) एसपीवी कंपनी का बोलीदाता / मूल कंपनी से बेहतर कोई अधिकार नही होगा और इसके अधिकार मूल कंपनी से प्राप्त होंगे उसके कृत्यों और कर्मों से मूल कंपनी बाध्य होगी।

(ii) एसपीवी कंपनी के काम का दायरा इस विशेष परियोजना के लिए ही सीमित होगा।

101

(iii) मूल कंपनी पूरी तरह हुडा की ओर वित्तीय दायित्वों की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगी ।

(iv) कंसेसियनार यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण अवधि के दौरान और इस परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए एसपीवी की 51% से अधिक इक्विटी स्वामित्व कंसेसियनार कंपनी के पास रहेगा। वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सी ओ डी) से पांच वर्ष की अवधि के उपरान्त कंसेसियनार द्वारा एसपीवी कंपनी का 51% इक्विटी स्वामित्व किसी अन्य इक्विटी को मुख्य प्रशासक, हुडा के पूर्व अनुमोदन से कम / हस्तांतरित किया जा सकता है।

(ख) पैरा (क) में व्याख्यित तथ्यों के अनुसार मेसर्स इंटरनेशनल इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की मूल कंपनी ने बोली में भाग लिया था ।

(ग) बिडर कंपनी मेसर्स इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड ने इस निविदा के लिए सभी नियमों और शर्तों का पालन किया है तथा कंसेसियनार एग्रीमेंट के अनुसार पूरी राशि जमा की है।

(घ) नहीं, महोदय ।

(ङ) नहीं, महोदय ।

Halting of Buses In the Hathin Bus Stand

435. Sh. Kehar Singh. : Will the Transnport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to halt buses in the bus stand of Hathin Town of Hathin Assembly Constituency and to start bus service from Hathin to Nuh, Alwar, Chandigarh, Hodal and

Sohna; if so, the time by which the said bus service is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, नहीं।

To Augment the Capacity of JD-6A Branch

446. Dr. Hari Chand Middha.: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the capacity of JD-6A Branch in Jind Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the capacity of JD-6A Branch is likely to be augmented?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, उपरोक्त के संबंध में विवरण इस प्रकार है:–

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

.....

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे ग्वाल पहाड़ी गांव की शामलात देह भूमि के विवाद बारे कांग्रेस दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी और दो अन्य विधायकों से स्थगन प्रस्ताव दिनांक 28.02.2017 को प्राप्त हुआ और इसी विषय से संबंधित एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री जाकिर हुसैन, विधायक, और चार अन्य विधायकों से भी आज सुबह प्राप्त हुआ है। मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित करके स्वीकार कर लिया है और जवाब के लिये सरकार के पास

भेज रहा हूँ । आने वाले दिनों में किसी भी दिन इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कार्य सूची में ले लिया जाएगा । माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करने के बाद इसी सैशन में लाएंगे क्योंकि आपने हमारे एडजर्नमैंट मोशन को तो खारिज कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : हां जी, इसी सैशन में लेकर आएंगे । आपका एडजर्नमैंट मोशन तो वैसे भी स्वीकार नहीं हो रहा था वह तो मैंने दरियादिली दिखाई कि इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल दिया नहीं तो वह कैंसिल ही था ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे कालिंग अटैंशन मोशन को अभी स्वीकार किया है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आपका भी कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकार कर लिया है ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपका ध्यान चार–पांच बातों की और दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिए।

जिला सिरसा में रानियां निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में दुधारू पशुओं में फैल रही बीमारी के संबंध में मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही जरूरी और अहम बात है । हमारे सिरसा जिले का जो रानियां विधान सभा क्षेत्र है उसके 7–8 गांवों में पिछले 3–4 दिन से पशुओं में महामारी फैली हुई है । 500 से ज्यादा पशु उस बीमारी में मर चुके हैं । यह ठीक है डाक्टर्ज की टीम वहां पर गई हुई है लेकिन बावजूद इसके यह महामारी बढ़ती जा रही है। उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर आप यूनिवसिर्टिज के डॉक्टर्ज की टीम को भेजें ताकी उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अगर किसान का पशुधन मर जायेगा तो मानकर चलो कि उसका एक रोजगार का साधन खत्म हो जायेगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी वह टीम भेजने का कष्ट करें?

श्री रामचंद कंबोजः अध्यक्ष महोदय, केहरवाला गांव में 38 पशु इस महामारी की वजह से मर गए हैं। डॉक्टर्ज की पूरी टीम यहां पर बैठी हुई है परन्तु यह महामारी उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार गांव केहरवाला गउंशाला के कई दुधारू पशु भी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन किसानों के पशु मरे हैं, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, किसान पहले से ही बहुत दबा व पिछड़ा हुआ है और इस अवस्था में यदि उसकी आय का साधन अर्थात पशुधन जिसका दूध बेचकर वह अपनी आय कमाता है, यदि छीन जाता है तो ऐसी अवस्था में किसान की हालत बहुत नाजुक हो जायेगी। अतः इस दिशा में सरकार की तरफ से बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय साथी से अनुरोध है कि जिन गांवों में यह घटना घटी है क्या वह उन गांवों के नाम बता सकते हैं?

श्री रामचंद कंबोजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को उन गांवों के नाम बताता हूँ। गांव बचेर, केहरवाला, मतुवाला, नाथौर, बनी तथा मम्मड़ ऐसे गांव हैं जहां पर यह माहमारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि जिन किसानों के दुधारू पशु मरे हैं उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था जरूर की जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, पहले जींद में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी तब भी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया गया था और अब यदि माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटना घटित हुई है कि दुधारू पशु किसी महामारी की वजह से मर गए हैं तो निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक सहयोग करते हुए यूनिवर्सिटी की एक टीम अभी हाउस के चलते चलते इनके क्षेत्र में पहुंच जायेगी। यदि उपरोक्त गांवों के अतिरिक्त और कोई सूचना माननीय सदस्य देना चाहते हैं तो मुझे लिखकर दे सकते है। जहां तक बात मुआवजे की है तो निःसंदेह जिन लोगों के दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया जायेगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू(पेहवा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जब भी बजट सत्र आता है तो प्रदेश के लोगों के मन में एक आशा होती

है कि आने वाले सालों में उन्हें कुछ सुख सविधाये दी जायेंगी। हमारा देश और प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है तो इन परिस्थितियों में खासतौर से खेती से जुड़े लोगों के मन में एक बात आती है कि क्या उन्हें आर्थिक तौर पर संपन्न कराने वाली कोई योजना सरकार द्वारा बनाई जायेगी। किसानों के प्रति सरकार का जो नज़रिया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शाया गया है उसको पढ़ने के बाद प्रदेश के लोगों में एक तरह से निराशा ही हाथ लगी है। बजट से पूर्व सरकार ने आर्म्ज लाईसेंस, ड्राईविंग लाईसेंस तथा डिवेलपमैंट चार्जिज संबंधी फीस को बढ़ाकर के प्रदेश के लोगों को आर्थिक तौर पर और ज्यादा कंगाल करने का काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम के उपर किसानों को किस तरह ठगा गया यह सबको मालूम है? फसल बीमा योजना के नाम पर बिना किसान की मंजूरी के उनके खातों में से पैसे निकलवाने का काम किया गया। जो फसलें, फसल बीमा योजना के तहत कवर ही नहीं होती, जैसे गन्ने की फसल है, गन्ने वाले खेतों का भी धक्के से प्रशासनिक अधिकारियों ने बीमा करने का काम किया है। पिछले वर्ष में किसानों के साथ धान व बाजरा में नमी के नाम पर हजारों–हजार करोड़ रूपये की ठगी करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। 150 से 200 रूपये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, उसमें पैसे कम करके देने का काम सरकार द्वारा किया गया। आज प्रदेश का किसान बड़ा दुखी और परेशान है। आलू पैदा करने वाले किसान को उसके आलू की बाजार कीमत दो रूपये किलो से ज्यादा नहीं मिल पा रही है। मटर की वह फसल जिसको उगाने में बहुत भारी खर्चा आता है और जिसके बीज की कीमत ही हजारों रूपये होती है, की बाजार कीमत अढाई से चार रूपये किलो हो गई है। पापलर की बहुत ही कम कीमत हो गई है जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों ने पापलर की होली जलाने का काम भी किया है। आर्थिक तौर पर पहले से ही बद्तर हालत का शिकार हो चुका किसान आज अढाई साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में और भी अधिक बद्तर हालत में पहुंच चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की सरकार ने किसानों को ट्यबवैल न देने का जो निर्णय लिया है वह भी बहुत ही गलत निर्णय है। सरकार की तरफ से कई क्षेत्रों को डार्क जोन तो घोषित कर दिया गया है लेकिन वहां पर नए ट्यूबवैल लगाने की सरकार इजाजत नहीं दे रही है। वहां हमारे जो खास तौर से कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र और यमुनानगर आदि जिले थे जोकि ज्यादा धान उगाने वाले जिले हैं वहां हमें जीरी के सीजन में आठ जिलों में रकबे के आधार पर

6–6 इंच के टैम्परेरी मोगे दिए जाते थे लेकिन आज इन मोगों का साइज घटकर 3–3 इंच रह गया है जिसकी वजह से हर साल पानी कम प्राप्त हो रहा है । यह सरकार किसानों के साथ बहुत भद्दा मजाक कर रही है । मैं सरकार को यह भी कहना चाहूंगा कि ट्यूबवैल के जो कनैक्शंज ओवरलोडडिड थे, जिनका कुछ समय पहले सरकार ने लोड बढ़ाने की इजाजत दी थी उस पर भी कम से कम अप्रैल के महीने तक काम पूरा तक करने का काम करें । इसके साथ ही कृषि मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष के एक सवाल के जवाब में सदन में स्वयं इस बात को माना कि हरियाणा प्रदेश के जो रजबाहे हैं जिनकी संख्या लगभग 1400 हैं, उनमें से अढ़ाई सौ टेल्स ऐसी हैं जिन पर आज प्रदेश की सरकार पानी नहीं पहुंचा सकी है । मैं यह मानकर चलता हूं कि प्रदेश का पांचवा–छठा हिस्सा आज भी ऐसा है जिसकी सिंचाई रजबाहों से होती है । हमारे प्रदेश के वे किसान आज सूखे की मार झेल रहे हैं । उनको सरकार के द्वारा न पीने का पानी मिल पा रहा है और न खेत को देने के लिए पानी मिल रहा है । यह बात माननीय कृषि मंत्री जी ने खुद यहां मानने का काम किया है । माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि के मुतल्लिक ही 351 घोषणाएं की थी जिनमें से अब तक सिर्फ 50 घोषणाएं ही पूरी हुई हैं । इससे पता लगता है कि सरकार किसानों के बारे में कितनी सीरियस है । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पहली बार यह कहा है कि हैफेड ने अब की बार मूंग दाल की खरीद करने का काम किया है । सभी जानते हैं कि आज आलू और सब्जियों की कीमत कम होने से किसानों की हालत कितनी खराब हुई है । अतः जब तक सरकार छोटी–बड़ी फैक्टरियां लगाकर किसान का आलू खुद खरीदने का काम नहीं करती तब तक किसान की हालत इसी तरह बद से बदतर होती रहेगी । आज बाजार में आप एक आलू का पोटेटो चिप्स का छोटा–सा पैकेट ले लो जिसमें सिर्फ 50 ग्राम आलू होता है या आप कॉर्न फ्लैक्स का पैकेट ले लो अगर उसकी कीमत कलैक्ट करके देखें तो वह लगभग 1200 रूपये प्रति किलोग्राम पड़ता है । यह रेट वे कम्पनियां सिर्फ मक्की को भूनकर और नमक लगाकर बेचने के ही ले लेता हैं जबकि आलू और मक्की को उगाने वाले किसान को सिर्फ 10 रूपये प्रति किलो का भाव मिलता है । इसलिए सरकार जब तक इस बारे में सीरियस नहीं होती तब तक किसान इसी तरह लुटता रहेगा फिर चाहे वह आलू की खेती करता हो या मक्की की खेती करता हो या अन्य सब्जियों की खेती हो । इसमें हरियाणा प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को आगे

आकर सीरियस तौर पर काम करना चाहिए । जहां तक गन्ने की बात है तो गन्ने का भाव 310 रूपये प्रति क्विंटल से 320 रूपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है । आज जो किसान का लागत मूल्य है वह बहुत बढ़ गया है क्योंकि आज बिजली के भाव भी बढ़ गए हैं । इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार हर महीने डीजल के भाव बढ़ा रही है । इन तमाम बातों को लेकर आज फसल का जो लागत मूल्य है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है । इस वजह से आज इन सब्जियों की जो कीमतें हैं सरकार को इन्हें भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये कीमतें कई सालों से एक जैसी ही चली आ रही हैं । इसी तरह महामहिम राज्यपाल ने पैरा नं. 56 में लिखा है कि हरियाणा सरकार रेल पटरियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक्वायर की हुई जमीन के अतिरिक्त जो जमीन बचती है उस पर वृक्ष लगाने का काम करने जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को यह कहना है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपनी सरकार के वक्त ये जो सड़कों के किनारे वृक्ष लगते थे उन्हें किसानों को ही दे दिया जाता था । इन पेड़ों की छाया से किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद और खराब हो जाती है । यदि सरकार ऐसा काम करने जा रही है तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जब ये पौधे तैयार होकर पूर्ण वृक्ष बन जाएंगे तो प्रदेश की सरकार इन्हें किसानों को देने का काम करेगी । अगर सरकार ऐसा न करें तो फिर वे पौधे लगाए ही न जाएं । इससे किसान की फसल को बहुत भारी क्षति होती है । अध्यक्ष महोदय, एक जो विशेष बात मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि नैशनल हाइवे नंबर 65 कैथल, पिहोवा और अंबाला की तरफ आ रहा है । इसको बनाने का काम अभी जारी है । इस हाइवे के लिए सरकार ने काफी जमीन एक्वायर की थी । सबको पता है कि जो सड़क पक्की बनती है वह थोड़े एरिया में बनती है । वह सड़क बनाने का जिन कम्पनियों के पास ठेका है वे क्या कर रहे हैं कि किसान से एक्वायर की गई जमीन को सड़क बनाने के अतिरिक्त जितनी जमीन बाकी बचती है वहाँ से ही मिट्टी उठाकर कर वहीं मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः संधू साहब, जल्दी वाईंड अप कीजिए क्योंकि आपके बोलने का थोड़ा समय रह गया है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, जिस समय आप मुझे बैठने का आदेश देंगे मैं उसी समय बैठ जाउँगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के क्रमांक न. 50 पर बागवानी फसलों के बारे में जिक्र किया है। उसमें

कहा गया है, ''कि वर्ष 2030 तक बागवानी उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देश्य से राज्य का 'बागवानी विजन' तैयार किया है।'' एक तरफ तो सरकार डायवर्सिफिकेशन प्रणाली के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े दावे करती है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब वर्ष 2017 चल रहा और सरकार द्वारा 13 साल आगे का विजन पहले से ही रख दिया गया है। किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वह आज के दिन किसानों के साथ धोखा है। बागवानी को तो इस स्कीम में लिया ही नहीं गया है। बागवानी के बारे में सरकार का क्या नजरिया है? और उसमें क्या करने जा रही है? इस बात का कुछ भी पता नहीं है और ना ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी जिक्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब वह माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना जवाब दें तो बागवानी के ऊपर विशेष तौर पर जवाब देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार विकास के नाम पर बड़े–बड़े दावे करती है। लेकिन असली बात यह है कि खेल विभाग में अभी तक 138 घोषणाओं में से कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। परिवहन विभाग में 40 घोषणाओं में से केवल 5, स्वास्थ्य विभाग में 114 घोषणाओं में से केवल 7, सिंचाई विभाग में 218 घोषणाओं में से केवल 12, शिक्षा विभाग में 110 घोषणाओं में से केवल 12, बिजली विभाग में 99 घोषणाओं में से केवल 18 और पब्लिक हैल्थ विभाग में 124 घोषणाओं में से केवल 9 घोषणाएं सरकार ने पूरी की है। यह है इस सरकार का विकास का नजरिया? अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी के बारे में भी सरकार ने बहुत कुछ कहा है। श्री राम बिलास शर्मा कहते हैं कि यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती नदी आदिबद्री में से होकर निकलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आदिबद्री में सरस्वती नदी की धारा देखने गया था। सरस्वती नदी की धारा ऐसे टपक रही थी जैसे मानो आँखों में आई–ड्रॉप्स डालते हैं। यदि सरकार इसी नदी को सरस्वती नदी कहती है तो यह नदी सरकार को ही मुबारक हो। अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विशेषतौर पर मेरे इलाके पेहवा के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें जो सरस्वती नदी है।

श्री अध्यक्षः संधू साहब, एक तरफ तो आप सरस्वती नदी को मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ सरस्वती नदी को मान रहे हो।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं वेद–पुराण ग्रन्थ के आधार पर ही बता रहा हूँ कि पेहवा में से सरस्वती नदी गुजरती थी।

श्री अध्यक्षः संधू साहब, आदिबद्री में से भी सरस्वती नदी गुजरती थी, इस बात को मान लो।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्षः संधू साहब, यह बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि हमारे पूर्वज बताते आ रहें कि इस जगह सरस्वती नदी बहती थी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तीर्थ स्थल पेहवा में गए थे। वहाँ के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक मांग पत्र दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि पेहवा का तीर्थ स्थल सरस्वती नदी का तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल को सुविधाजनक और सुंदर बनाने के लिए पेहवा के पश्चिम की ओर से जहाँ सरस्वती तीर्थ है वहाँ पर एक बाईपास रोड़ बनवाया जायेगा। यह बाईपास रोड़ कब तक बनवाया जायेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार देने की बात कही थी । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि जब भी सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलेगा और प्रार्थी एप्लाई करेंगे तो उसके साथ बोर्ड/कॉरपोरेशन/विभाग से नॉ–ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर लगाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वोट लेने के लिए 6000 और 9000 रूपये बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं ऊपर से यह नई चीज और थोप दी है। कुरूक्षेत्र यूनिवसिर्टी में नर्सिंग स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनको आज भी केवल 5400 रूपये सैलेरी के रूप में दिये जा रहे हैं तथा दिन–रात उनसे काम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आज बेटी बचाओ, बेटी पढाओं का नारा सरकार ने दिया है। इसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मिल वर्कर या अतिथि अध्यापक हैं।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आप वाइन्ड अप करें क्योंकि आपका टाईम पूरा हो गया है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया जाना था लेकिन उस बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार के खिलाफ ये सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरपंचों के बारे में कहा गया था पढे–लिखे सरपंच हो गये हैं लेकिन उनकी अनदेखी की

जा रही है। प्रदेश के अधिकारी उनको जन प्रतिनिधि न मानकर सरकारी कर्मचारी की तरह व्यवहार करते हैं। सरकार ने कहा था कि जहां–जहां सर्वसम्मति से चुनाव हो जाएंगे उन पंचायतों को 10–10 लाख रूपये दिये जाएंगे। यह वायदा अभी पूरा नहीं किया है। मेरे अपने इलाके मदनपुर की पंचायत में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। सरकार ने सांसदों तथा विधायकों द्वारा जो गांव गोद लेने की बात कही थी।(शोर एवं व्यावधान)

मुख्य संसदीय सचिव (सरदार बख्शीश सिंह विर्क): अध्यक्ष महोदय जी, पूरे हरियणा के संबंधित गांवों में 11–11 लाख रूपये पहुंच गया है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: आपके इलाके में पहुंच गये होंगे हमारे वहां पर नहीं पहुंचे हैं।

सरदार बख्शीश सिंह विर्कः नहीं, पूरे हरियाणा की पंचायतों में 11–11 लाख रूपये पहुंच गये हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: विर्क साहब, मदनपुर गांव में आपकी रिश्तेदारी है। अगर नातोफार्म में पहुंच गये हो तो बताने का कष्ट करें।

सरदार बख्शीश सिंह विर्कः संधू साहब, वहां पर पहुंच गये हैं अपना खाता नं0 बताकर बैंक से पैसे निकलवा लें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: विर्क साहब, आप पैसे निकलवाकर खाता धारक को दे देना, मैं आपको उनके फोन नम्बर दे देता हूं। अध्यक्ष जी, सरकार ने एक–एक गांव गोद लेने के लिए विधायकों को कहा था। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः संधू साहब, आपका टाईम पूरा हो चुका है। आप वाइन्ड अप कीजिए।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदयः सरकार ने अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है। मेरे हल्के के गांव है भटेड़ी में आपकी रिश्तेदारियां हैं वहां पर चव्वनी भी नहीं पहुंची। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): धन्यवाद सर । अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने विधान सभा में जो अपना अभिभाषण पढा है उसे सुनकर इस

सरकार के तीसरे वर्ष की शुरूआत में बहुत ज्यादा निराशा हरियाणा के लोगों को हुई है। उन्होंने अपने अभिभाषण में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के मंत्रियों और सरकार द्वारा जो चहूंमुखी विकास करने और हरियाणा को हर तरीके से आगे बढाने की बातें कही गई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वह इसलिए खोखली नजर आती हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों की घोषणाओं की अपनी एक मान्यता होती है और लोगों के मन में एक श्रद्धा होती है। कोई भी बात जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री कहते हैं तो प्रदेश क्या दूसरे प्रदेशों के लोग भी यह बात मानते है कि यह घोषणा जरूर पूरी हो जाएगीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनके संबंध में ट्रिब्यून न्यूज सर्विस अखबार में 13 फरवरी 2017 के अंक में लिखा है कि हरियाणा सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं में लगभग 64 प्रतिश्त सी.एम. घोषणाएं पैंडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार में जितनी भी घोषणाएं की हैं उनके संबंध में हरियाणा के लोगों का यह मानना है कि अगर मुख्यमंत्री जी को 15 साल लगातार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले (शोर एवं व्यवधान) तो भी ये घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार/मुख्यमंत्री जी से यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो घोषणाएं की गई है जिनको पूरा नहीं कर सकते। ये घोषणाएं जो इन्होंने अपनी अनुभवहीनता से, या सरकार न चलाने की अनुभवहीनता के कारण किसी दबाव में या किसी भावनाओं में आकर की हैं। उन घोषणाओं को वापिस लेकर प्रदेश की जनता से माफी मांगे। जो घोषणाएं पूरी कर सकते हैं उन्हें अपने स्तर पर अधिकारियों की कमेटी बनाकर यह सुनिश्चित करें और जो बातें कहीं गयी हैं उनको पूरा करें। अध्यक्ष महोदय जी, दूसरी बात जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि जो पंचायतीराज सस्थाएं हैं उनके सुधारीकरण के लिए संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन किया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं उनको इतने अधिकार दिये जाएं कि वो अपने अधिकार प्राप्त करके जो काम सरकारें नहीं कर सकती वह काम ग्राम पंचायत की संस्थाएं करें। पिछले दिनों एक प्रथा थी कि ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारी ए.डी.सी हुआ करते थे और वे इस मामले में यह महसूस नहीं करते थे कि वे इतने बड़े अधिकरी होकर ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों की बैठक के कार्यकारी अधिकारी बने हैं और उनके द्वारा पंचायतों और जिला परिषदों

के कामों में कोई भी रुचि नहीं ली जाती थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो एच. सी.एस अधिकारियों का फैसला किया है, मैं इस फैसले को ठीक मानता हूं, लेकिन इनसे एक निवेदन और करता हूं कि जो ए.डी.सी ऑफिस में डी.आर.डी.ए जो एक संस्था है, जिसमें अरबों–खरबों रुपए आते हैं। डी.आर.डी.ए के तहत उन पैसों को सिवाए खुर्द–वुर्द करने के ज्यातार संस्थाएं उन पैसों का ठीक इस्तेमाल नहीं करती और वह अरबों–खरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और अधिकारियों की जेबों में चला जाता है या ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है। जहां इन्होंने एच.सी. एस अधिकरियों को ये पंचायती राज इंस्टीच्यूशन में कार्यकारी अधिकरी बनाया है वह काम ठीक तरीके से कर सके और उन्हें पूर्ण रूप में अधिकार दिया जाए और डी.आर.डी.ए मे जितना भी पैसा अध्यक्ष महोदय जाता है। डी.आर.डी.ए के उस तमाम पैसे को समाप्त करके सीधा पंचायती राज इंस्टीयूशन को अगर दें तो मैं मानता हूं कि शायद हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों का या गांवों में रहने वाले लोगों का बहुत भला हो सकता है। आगे यह सरकार की मर्जी है वह इसे ठीक समझे या न समझे। इसी तरह जो बी.डी.पी.ओ हैं वह पूरे हरियाणा में न जाने कितने ब्लॉक बिना मर्जी के बनाये हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आधार पर इन्होंने ब्लॉक बनाने की घोषणा की और आज हालत यह है कि बी.डी.पी.ओ के तकरीबन सभी ऑफिस खाली पड़े हैं और वहां कोई बी.डी.पी.ओ नहीं है जिनमें ज्यादातर खाली हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि या तो इन बी.डी.पी.ओ की भर्ती करें वरना एक हाउस कमेटी बनाकर, इस पर फिर से पुनः विचार करें कि जो ज्यादा ब्लॉक बनाए गए हैं, उनकी अगर जरूरत नहीं है तो उन्हें दूसरे ब्लॉक में समावेश करें। जिससे की प्रदेश के अंदर ग्रामीण लोगों का जो काम रुका हुआ है, वह काम ठीक तरीके से हो सके और जो यह राजनीतिक आधार पर इन्होंने ये ब्लॉक बनाये हैं, उनमें राजनीतिक आधार पर कई ब्लॉक गलत बनाए हैं और उनके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और व्यवस्था के मुताबिक जितने ब्लॉक बनाने की जरूरत है तो सिर्फ उन ब्लॉकों को ही बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से सातवें वेतन आयोग में हमारे पिछले दिनों हुड्डा साहब ने पुलिसकर्मियों को पंजाब के बराबर वेतन मान देने की घोषणा की थी और इनके भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में यह एलान था कि ये पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के पुलिसकर्मियों को वेतन मान देंगे। लेकिन ये जो सातवां वेतनमान आया है, भारत सरकार से वेतनमान की जो रिकमंडेशन आई है,

फिर भी इस प्रदेश में पे–कमीशन को इतने गलत तरीके से लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभी जो श्रम कर्मचारी वर्ग हैं, वह इस वेतनमान को ठीक नहीं मानते और खासकर हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को सरकार ने बिल्कुल ही गैर–जिम्मेवाराना तरीके से वेतन मानों को दिया है, इस पर सरकार पुनर्विचार करना चाहिए।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज): अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में भी बता दिया जाए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ये हरियाणा पुलिस सिपाही एसोसिएशन ने मुझे लिखकर भेजा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे आपको भिजवा देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा।

श्री कर्ण देव कम्बोज : ये हमारे पास भी आया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास भी आया है तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने सरस्वती नदी के बारे में जो बात कही। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी विडम्बना की बात है, सरकारों को हक है कि वो गुड़गांवा को गुरुग्राम करें, हमारे मुख्यमंत्री जी का श्री नाम मनोहर लाल खट्टर है तो खट्टर हटाकर के ये श्री मनोहर लाल करें। ये कोई और हरियाणा के नाम से गांवों के नाम बदलें, लेकिन सरस्वती नदी जो हमारे देश की सभ्यता का एक प्रतीक है और उस सरस्वती नदी के ऊपर बहुत जिम्मेवारी से, उसकी खोज करके पूरे अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों की उसमें मदद लेकर अगर इस सरस्वती नदी की शुरुआत करते तो ये हरियाणा के लिए गौरव की बात थी। केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के उस हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जबरन सरस्वती नदी की दुहाई दे रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका अपना इलाका वहां से कितना नजदीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह वैदिक पिपुल एक किताब है, जो श्री राजेश कोचर ने लिखी है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह के बड़े–बड़े लोग हैं, सभी सलाह मशवरा करके यह किताब लिखी है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो मैं किताब उनके पास भिजवा सकता हूं। उन्होंने अपनी किताब में बड़े विस्तार से यह जिक्र किया है कि हो सकता है सरस्वती नदी का निकास अफगानिस्तान से हो सकता है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे अवशेष और कागजात मिले हैं जिसके कारण घग्गर नदी को भी कई दफा

सरस्वती नदी माना है । लेकिन पिछले दिनों सरस्वती नदी का नाम धर्म के नाम पर यूज किया जा रहा है । हमारे पूर्वज कहा करते थे कि गंगा, जमना, सरस्वती तीनों मिलें प्रयाग, दर्शन वही कर सके जिसके माथे भाग । गंगा–जमुना का कोलकता में गंगा सागर में मिलन होता है और वहां सरस्वती का आना जाना माना जाता था । अब सरस्वती को आदीबद्री के यहां भी माना गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मुझे और कुलदीप शर्मा जी को आदीबद्री जाने का अवसर मिला । वहां बहुत बदहाली है, जिसको देखकर हम बहुत हैरान हो गये । मैंने उस जिले के डिप्टी कमिश्नर को फोन करके कहा कि आदीबद्री महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थान है । यहां पर बेसिक सुविधाएं तो लोगों को मुहैया करवायें । आज प्रदेश में सरस्वती नदी का जबरन जप किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सरस्वती नदी देश की बहुत बड़ी धरोहर है । हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए बिना किसी आधार के जिस तरह से गुड़गांव का नाम गुरूग्राम कर दिया गया उसी तरह से नदियों का नामकरण करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप वाईंड अप करें । आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं जबकि दूसरे सदस्यों को 6 मिनट का समय ही दिया गया है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक–दो बातें कहकर वाईंड अप करता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह लिखा है कि मेरी सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने राज्य के पक्ष में एस.वाई.एल. नहर का फैसला दिया है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस तरह की बातें लिखना गैर जिम्मेदाराना हैं । क्या कोई सरकार सर्वोच्य न्यायालय को अपने पक्ष में करने के लिए अपने प्रयासों का सहारा ले सकती है ? इस तरह की बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं आनी चाहिंए । अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस.वाई.एल. नहर का सवाल है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. नहर की जरूरत होडल, पलवल, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और झज्जर आदि सूखे जिलों के एरिया में पानी पहुंचाने के लिए पड़ी । यह बहुत अफसोस की बात है कि एस.वाई.एल. नहर के नाम पर सभी सरकारें राजनीति करती आई हैं । आज जो मामला है वह हरियाणा के लोगों को समझना होगा कि सतलुज नदी के बाद पौंग डैम बना और गोविंद सागर डैम में ब्यास नदी का पानी आया । उस पानी को इन सूखे एरियाज में लाने के लिए एस.वाई.एल.

नहर का निर्माण होना था । अध्यक्ष महोदय, 1977 में प्रदेश में जो सरकार थी उसने जबरन इन एरियाज का पानी उठाकर भाखड़ा मेन लाईन से सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले के कुछ एरियाज में इस्तेमाल के लिए डाल दिया । भाई अभय सिंह चौटाला जी बैठे हुए हैं, जो सिरसा जिले के लोगों का नेतृत्व करते हैं । ये मेरी बात को अन्यथा न लें । इनकी और इनके परिवार की एक ही दिक्कत रही है कि जब भी ये देखते हैं कि एस.वाई.एल. नहर किसी भी तरीके बनने जा रही है तो ये लोग प्रदेश में धूमशबाजी शुरू कर देते हैं । राजीव लौंगोवाल एकॉर्ड का भी भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवी लाल जी विरोध न करते तो 1987 में ही एस.वाई.एल. नहर बन चुकी होती । चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा के पंच और सरपंचों को एस.वाई.एल. नहर बनती हुई दिखाई थी । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने मेरा नाम लिया है इसलिए मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । इन्होंने कहा है कि जब भी एस.वाई.एल. नहर बनने का इशू आता है तो हम उसके उपर घमासान खड़ा कर देते हैं। मैं इस बाबत यही कहना चाहूंगा कि हमने 100 फीसदी ही घमासान करके यह प्रयास किया कि यह नहर बने और इस नहर में पानी आये। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता के सहयोग से यह प्रयास जारी भी रहेगा। मैंने तो कल भी सबसे कहा था कि हम आने वाली 15 मार्च को भी पार्लियामैंट का घेराव करने जायेंगे आप सभी को भी एक बार फिर मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूं लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा। इन दस वर्षों के दौरान यह मामला माननीय कोर्ट में पैंडिंग था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उस 10 साल के दौरान इन्होंने कोर्ट में क्या प्रयास किये? इन्होंने उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिलकर क्या प्रयास किये? इसी प्रकार से ये यह भी बतायें कि इन्होंने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से मिलकर क्या प्रयास किये? उस दौरान पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में भी इनकी अपनी सरकार थी और केन्द्र में भी इनकी अपनी ही पार्टी की सरकार सत्तासीन थी। ये एस.वाई.एल. के लिए जिस दक्षिणी हरियाणा का नाम लेकर चर्चा कर रहे हैं उस दक्षिणी हरियाणा की प्यास कैसे बुझे इसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किये। जिस स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी का नाम यहां पर लिया जा रहा है। मैंने कल यहां पर पूरी डिटेल में बताया था कि उन्होंने सन् 1991 में स्वयं यह बात स्वीकार की है कि चौधरी देवी लाल के प्रयासों की

वजह से एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए जमीनें एक्वॉयर हुई। उनकी वजह से ही इस नहर के निर्माण में ज्यादा काम हुआ। उन्हीं के प्रयासों से ही इस नहर के ऊपर ज्यादा पुल बने। उन्हीं के प्रयासों से ज्यादा से ज्यादा रास्ते उसके साथ–साथ बनाये गये ताकि उस नहर के निर्माण में कोई बाधा न आये और हरियाणा में उसके हिस्से का पानी जल्दी से जल्दी आ सके। ये केवल और केवल सदन को गुमराह करने के लिए कहीं न कहीं अपने भाषण को आगे बढ़ाने के लिए और इस विवाद को तूल देने के लिए कि एस.वाई.एल. नहर का पानी न आये। यह सब किया जा रहा है। ये सभी इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम इनके इन प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किया हुआ यह वायदा है कि 100 फीसदी आपकी एस.वाई.एल. नहर खुदवाकर देंगे और हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी लाकर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय नेता द्वारा मेरा नाम लेकर यह पूछा गया है कि हमारी सरकार के शासनकाल के दौरान इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये? इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में 2002 और फिर 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के हित में आदेश हो गये थे लेकिन पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर जल समझौते को अस्वीकार कर दिया। (विघ्न) वहां पर सरकार कांग्रेस पार्टी की थी लेकिन अकाली दल के साथ सभी दलों ने इस मामले में सरकार का साथ दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। केन्द्र में हमारी सरकार आते ही हमने इस सम्बन्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी का रैफरैंस करवाया। मैं उस समय सांसद था । उस समय मेरे साथ हरियाणा के सभी सांसद गये और यह आदेश करवाया। यहां पर दक्षिण हरियाणा की भी बात की गई कि इस मामले में हमने क्या प्रयास किया? मैं इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि बी.एम.एल. हांसी बुटाना नहर की खुदाई मेरे समय में हुई है। (विघ्न) हमें उम्मीद है कि इसमें 2000 क्युसिक पानी जरूर आयेगा।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दक्षिणी हरियाणा और एस.वाई. एल. कैनाल की बात है । अगर एस.वाई.एल. बन जाती तो सबसे ज्यादा फायदा दक्षिणी हरियाणा का ही होना था लेकिन यहां पर दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों द्वारा इस मामले में लगातार राजनीति की जाती है। मुझे ये यह बता दें कि रावी–ब्यास

के पानी में से जो हरियाणा प्रदेश को 1.62 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा है। ये उसको सारे का सारा इस्तेमाल कर रहे हैं । इन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि तुम प्यासे मर रहे हो इसलिए इसमें से थोड़ा सा पानी तुम्हें भी दे देते हैं। इन्होंने कभी भी थोड़ा सा पानी स्पेयर करके महेन्द्रगढ़ जिले के लिए नहीं दिया। हम और हमारे पशु भी पीने के पानी के लिए तरसते रहते हैं। हमेशा से ही जो पानी की कमी होती है उसको हमारे ऊपर ही डाल दिया जाता है। मैंने पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर यह बात की थी कि जहां पर सेम की समस्या है। जैसे झज्जर का इलाका सारा डूबा पड़ा है। इसी प्रकार से सिरसा और फतेहाबाद में भी सेम की समस्या है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जहां–जहां पर सेम की समस्या है वहां का अतिरिक्त पानी अगर सीजन में हमें दे दिया जाये तो हमारी पानी की समस्या का भी थोड़ा बहुत समाधान हो जायेगा और हरियाणा के सेम से प्रभावित इलाकों को सेम की समस्या से भी छुटकारा मिल जायेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में केवल कोरी राजनीति न करके कोई न कोई ठोस कदम उठायें जायें। जहां तक इस मामले में वर्ष 2004 के निर्णय की बात है। जब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एब्रोगेट किया उस समय केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। ये सारे के सारे सीनियर ऑफिसर पदबसनकपदह मअमतलइवकल जीमल ादमू पज जींज पज ूं ूतवदह मदंबजउमदज और ये ससटेन नहीं हो सकता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं इस मामले में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार वर्ष 2004 के बाद आई। वर्ष 2004 में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार नहीं

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की नहीं केन्द्र सरकार की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की और पंजाब की बात कर रहा हूं ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अभय सिंह यादव की बात का समर्थन करता हूं लेकिन जिन लोगों ने दक्षिण हरियाणा के साथ धोखा किया आज वे चैक कर लें कि दक्षिण हरियाणा में उनकी कोई सीट आई भी है या नहीं । दक्षिण हरियाणा के लोग इनकी राजनीति को समझ चुके हैं इसलिए वहां पर इनका खाता ही नहीं खुला ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं बेदी जी को बताना चाहता हूं कि 2009 में हमारी कितनी सीटें थी और 2019 में फिर देख लेना कि कितनी सीटें आती हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं और यहां पर मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुये हैं और अभय सिंह चौटाला जी भी बैठे हुये हैं । कल हाउस में सरस्वती नदी की चर्चा हो रही थी कि सरस्वती नदी का पानी हरियाणा में आ रहा है और दूसरी तरफ अभय जी एस.वाई.एल. नहर का पानी ला रहे हैं । इस प्रकार से तो हरियाणा में पानी की मात्रा बढ़ जायेगी । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार बाढ़ नियंत्रण के पूरे इंतजाम करके रख ले तथा हरियाणा को डूबने से बचा लें । (हंसी)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री अभय सिंह यादव जी कह रहे थे कि हमारे हिस्से का पानी कहीं न कहीं दूसरी जगह पर जा रहा है । मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार को आये अढ़ाई साल होने वाले हैं और जब आपकी सरकार के मुखिया भी आपको पानी नहीं दे रहे हैं तो आपको रोज–रोज इस बात को हाउस में नहीं उठाना चाहिए । आप रोजाना यह कहते हैं कि वहां फ्लड आई हुई है, वहां सेम की समस्या है और हमें पानी नहीं मिल रहा है । मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 28 गांवों में सेम की समस्या है जिनमें फसल पैदा नहीं होती है अगर आप वहां से सेम नाला बना कर उस पानी को ले जा सकते हो तो ले जायें । इससे आपको पानी मिल जायेगा और वहां के लोगों की जमीन खेती के लायक हो जायेगी । अभी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात तो क्लीयर कर दी कि वे नहीं चाहते कि एस.वाई.एल. नहर का पानी आये इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह बात कही है कि न तो एस. वाई.एल. नहर का पानी लाओ और न ही सरस्वती नदी का पानी लाओ ताकि कल को हरियाणा में बाढ़ न आ जाये । इनकी नीयत तो यह है कि हरियाणा प्रदेश का किसान भूखा मरे । इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हरियाणा में पानी आये ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बार–बार चौधरी बंसी लाल जी का नाम लिया जाता है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि 1986 में एस. वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था । उसके बाद उनकी सरकार चली गई तथा चौधरी देवी लाल जी की सरकार उसके बाद आई है । यह बात रिकॉर्ड पर लाई जाये ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. नहर बनाना एक मुद्दा है और उस पानी का बंटवारा करना दूसरा मुद्दा है जो सबसे महत्वपूर्ण है । इराडी ट्रिब्यूनल के बाद पंजाब और हरियाणा की नदियों के पानी का बंटवारा अगर कोई कर सकता है तो वह ट्रिब्यूनल ही कर सकता है, सरकारें नहीं कर सकती । 10 साल चौटाला जी की सरकार रही और इस मामले में मैं हरियाणा की सभी सरकारों को दोषी मानता हूं कि हमने आज तक ट्रिब्यूनल नहीं बनाया है । पंजाब हर जगह, हर कोर्ट में एक ही फायदा लेता है कि ट्रिब्यूनल में पानी का बंटवारा किया जाये । अगर ट्रिब्यूनल बनाया होता तो पंजाब यह फायदा नहीं ले सकता था । पिछले दिनों जब अभय सिंह चौटाला जी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अब एस.वाई.एल. नहर को बनवाने के लिए सीरियस है तो उन्होंने पंजाब के लोगों को भड़काने के लिए कस्सी उठाई और नहर खोदने के लिए चल पड़े, क्या कभी कस्सियों से नहर खोदी जाती है? जहां जे.सी.बी. जैसी मशीनें भी छोटी पड़ती हैं वहां कस्सी क्या काम करेगी? ये गये थे नहर खोदने लेकिन सड़क खोद कर वापिस आ गये । ये लोगों को भड़काना चाहते हैं कि क्योंकि अगर एस. वाई.एल. नहर का पानी हरियाणा की सूखी धरती पर आ गया तो सिरसा जिले का पानी कम हो जायेगा । जहां बादल साहब का भी फार्म है और बादल साहब और देवी लाल का परिवार मिल कर यह चाहता है कि हरियाणा में एस.वाई.एल. नहर न बने और उनको इसी तरह से ज्यादा पानी मिलता रहे ।

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, अब आपकी बात पूरी हो गयी है । आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है । इसको आपने काफी लम्बा कर दिया है।

श्री करण सिंह दलाल : सर, मैं बस कन्कलूड ही कर रहा हूं ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, काम की बात होने लग रही है और फिर आप कन्कलूड करने की बात कहते हो।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): माननीय करण दलाल, आपको डॉक्टर ने पैर के ऊपर जोर देने से मना किया है । ये हुड्डा साहब आपको पम्प करते हैं । ये तो एस.वाई.एल. नहर का पानी ला नहीं सके । चौधरी अभय सिंह चौटाला हिम्मत करके गये । उनकी बात की ये खिल्ली उड़ा रहे हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, महामहीम साहब ने जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का ब्यौरा दिया है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : शर्मा जी, आपकी और अभय जी की मिलीभगत थी क्या ? क्या आपने अपनी मिलीभगत से ही उनको नहर खोदने के लिये भेजा था ?

श्री राम बिलास शर्मा : हुड्डा साहब, इतिहास का कुछ पता नहीं लगता । यह तो हमारे पार्टनर रहे हैं और आगे समय का क्या पता चलता है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : शर्मा जी, वही बात हम कह रहे हैं और वही बात आप मान रहे हैं और क्या चाहिए ? ठीक बात है मिली भगत है । अब तुम्हारा राजनीतिक ड्रामा बहुत हो गया है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हितों की लड़ाई हमने मिलकर लड़ी है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ठीक बात है आपकी मिली भगत है । अब तुम्हारा राजनीतिक ड्रामा बहुत हो गया है। अब लोग आप लोगों को समझ गये हैं । अब तक आपने लोगों को बहुत मूर्ख बना लिया है ।

श्री करण सिंह दलाल : महामहिम साहब ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का ब्यौरा दिया है ।

कैनेडियन प्रतिनिधि मंडल तथा सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) की पत्नी का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, कनाडा से लोरीअनमैकलिओड, शेरी ली परूडन्टे, आरन जैकब, ऐरियाने, जोसफ पियरे जश्न और डॉ0 प्रीतम सिंह तथा हमारे सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर की पत्नी श्री वीना ग्रोवर जो कि वी.आई.पी. गैलरीज में मौजूद हैं । मैं पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, महामहिम साहब ने अपने अभिभाषण में जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया है उसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं पॉवर यूटिलिटीज के बारे में कहना चाहता हूं । महामहिम जी ने पॉवर यूटिलिटीज के बारे में कहा है । मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से भी ज्यादा आज एक पुलिस अधिकारी उन पॉवर यूटिलिटीज का चेयरमैन और एम.डी. बना हुआ

है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वहां पर जांच करवाई जाए । वहां अरबों–खरबों रूपयों का सामान खरीद कर डाल दिया है जिसकी कहीं कोई जरूरत भी नहीं थी गांवों में लोग ट्रांसफार्मरों के लिये रोते चिल्लाते रहते हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, अगर यही जानकारी मैं दे दूं कि हमने आते ही पता किया कि पॉवर विभाग में कितना इन्वैंट्री बाकी है तो हमें जानकारी मिली कि जब पिछली सरकार गई तो वह 500 करोड़ रूपये की इन्वैंट्री बाकी छोड़कर गई थी और जब 500 करोड़ रूपये इन्वैंट्री की जानकारी ली गई और पता किया कि कितनी आवश्यकता होती है तो उस समय यह पता लगा कि इसके लिए 70 से 80 करोड़ रूपये की इन्वैंट्री होनी चाहिए । अगर ये उल्टा प्रश्न करते हैं कि 500 करोड़ रूपये का माल खरीदने की जरूरत क्या पड़ी थी तो इसका कोई जवाब नहीं होगा । हम तो धीरे–धीरे से किस प्रकार से उसको खत्म किया जाए और उसको किस प्रकार से कन्जूम किया जाए उस पर विचार कर रहे हैं । हमने तो यहां तक कहा कि अगर इस सामान को वापिस करके पैसा लिया जा सकता है चाहे ये 5 या 10 प्रतिशत कमीशन से भी पैसा वापिस कर दें और चाहे दुकानदार अपना प्रोफिट वापिस ले जाएं और अपना सामान उठा ले जाएं । वरना यह स्टोक आठ साल तक भी खत्म नहीं होना है । पिछली सरकार पॉवर विभाग का 500 करोड़ रूपये का इन्वैंट्री छोड़कर गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, प्लीज आप बैठ जाईये । आप 25 मिनट बोल लिये हैं।

श्री महीपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठिये । आपने 7–8 मिनट बोलना था और आप 25 मिनट बोल लिये है।

श्री महीपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, पहले आप अपना बैलेंस बनाओ ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले जो माननीय सदस्यगण अपनी बात रख रहे थे । उन्होंने हमें कहा कि बी.जे.पी की सरकार अनुभवहीन सरकार है

और अनुभवहीन सरकार कोई ज्यादा अच्छा कार्य नहीं कर पा रही है । मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार अनुभवहीन है । (शोर एवं व्यवधान) करण जी, प्लाज आप बैठ जाईये और हमें बोलने दीजिये । सर, इनके पैर पर दबाव आ रहा है । इनके पैर में चोट है इसलिये इनको बिठाईये ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जो महामहिम राज्यपाल जी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पर ब्यौरा दिया है कि सैंटर गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट का ढ़ाई सौ करोड़ रूपये जो किसानों की खून पसीने की कमाई थी वह विदेशी इंश्योरैंस कम्पनियॉ के खाते में गया है और किसानों को मात्र 9 करोड़ रूपये ही मिले हैं तो बाकी पैसा कहां गया ? अध्यक्ष महोदय, जो मेरे से हिसाब मांगा जा रहा था वह पैसा * में गया है और किसानों के हकों के ऊपर डाका डाला गया है ।

श्री अध्यक्ष : यह जो कर्ण सिंह दलाल जी ने शब्द कहा है, वह रिकार्ड न किया जाए ।

12:00 बजे

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को लूटने और * को भरने के लिए बनाया गया है।

श्री अध्यक्षः * वाले शब्द को रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के खातों से काटा गया पैसा * की जेबों में आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, सभी तरह की बातों का उत्तर आप ही मत दिया करो। इस तरह की बातों का उत्तर बाकायदा सरकार की तरफ से दिया जायेगा। अगर आप हर बात पर टीका–टिप्पणी करेंगे तो दूसरे सदस्यों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं और सरकार के मंत्री चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब तो यह हुआ कि जो करण सिंह दलाल जी कह रहे हैं वह सब कुछ

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है पैसा किसी के पास गया तो जरूर है। अगर करण सिंह दलाल कोई बात कह रहा है तो उसके बारे में तो सदन में पूछा ही जायेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, अगर विपक्ष की तरफ से कोई आरोप लगाया गया है तो उसका जवाब सरकार देगी, आप क्यों बीच में उठकर बोलने लग गए हो? जब आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तब आप अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर हम सरकार में होते तो इस तरह की बातों को शांति से बैठकर सुनने वाले नहीं थे और बाकायदा तौर पर इसका माकूल जवाब दिया जाता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, यदि जनता आपको जिम्मेदारी देती है तो इस तरह के सवालों का जवाब आप दे देना? अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है अतः जवाब भी इन्हीं को देने दो?(शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का एक नया सदस्य हूँ लेकिन जानकारी के अभाव में आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जिस विषय के उपर एक प्रिवीलेजिज मोशन आया है और उस प्रिवीलेजिज मोशन के संदर्भ में प्रिवीलेजिज कमेटी ने अभी रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है बल्कि अगले सैशन तक छह महिने का समय और मांगा है। जिस विषय पर लाये गए प्रिवीलेजिज मोशन का अभी तक फैसला नहीं हुआ है और उसी विषय को बार–बार सदन में दोहराया जा रहा है तो क्या इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार जितने चाहे प्रिवीलेजिज मोशंज लेकर आए या जो चाहे कार्रवाई करे, मैं परवाह नहीं करता?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी, करण सिह दलाल ने जिस प्रिवीलेजिज मोशन से जुड़े हुए विषय के संदर्भ में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी प्रकार की कार्रवाई से नहीं डरता।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, आपके पैर में चोट लगने से जो दर्द हो रहा है, वह दर्द अब पैर से निकलर कही ओर जा रहा है? आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा (पानीपत ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अनुभवहीन सरकार कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी अनुभव वाली सरकार सत्तासीन थी तब इन्होंने हरियाणा प्रदेश के प्रति ऐसी कौन सी सोच डिवेलप की थी जिससे हरियाणा प्रदेश में बहुत सारा विकास हुआ हो ? अध्यक्ष महोदय, कोई एक उपलब्धि इन लोगों के नाम नहीं है। जब मैनें इस अभिभाषण को पढ़ा तो मैंने पाया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपलब्धियों का एक पूरा जखीरा और एक ऐसी सोच जिससे हरियाणा के हर व्यक्ति को लाभ मिलता हो, विद्यमान है। हरियाणा तरक्की और प्रगति करे इस सोच के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सोच भी दो तरह की होती है। एक सोच तो वह होती है जो किसी को डूबोती है और दूसरी सोच विकास व खड़ा करने वाली होती है। मैं विकास व खड़ा करने वाली सोच से ही अपनी बात शुरू करूंगा। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी मेरे विधान सभा क्षेत्र पानीपत में आए थे और यहां आकर उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। वर्ष 2011 में जो लिंगानुपात 830 के आंकड़े पर खड़ा था वह आंकड़ा वर्ष 2016 में 900 को पार कर गया है। सरकार की यह एक अच्छी सोच थी और लिंगानुपात का बढ़ना वास्तव में सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सरकार ने बेटियों के विषय पर पूरी निष्ठा के साथ काम किया है और निष्ठा के साथ काम करने के कारण ही इस सरकार को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले की भी सरकारें थी, उन सरकारों ने इस दिशा में क्या कोई ठोस काम किया था? वास्तव में कोई ठोस काम करने के लिए उन सरकारों के पास सोच ही नहीं थी? कितनी विडम्बना है कि पूर्ववर्ती सरकारें अपने मानव संसाधन को बचाने की भी नहीं सोच पाई? अनुभवहीनता की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुभव होने के बावजूद भी उन्होंने हरियाणा प्रदेश को अंधकार की गर्त में क्यों डूबो दिया

था ? हरियाणा प्रदेश के इस महान सदन में विपक्ष की इस प्रकार की मानसिकता तैयार हो गई है कि हर बात पर विपक्ष के लोग सदन में खड़े हो जाते हैं और किसी अच्छी बात को कहने में भी संकोच किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि विपक्ष के लोगों को अपनी सोच को दुरूस्त करके ही अपनी बात कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय , बेटियों को पढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी सोच के साथ काम शुरू किया है। मैं यमुनानगर जिले के उन अभिभावको को बधाई देता हूँ जिनको बेटियों को पढ़ाने की दिशा में अवार्ड दिया गया है। आज लोग बेटियों की पढ़ाई के मामले में जागरूक हो चुके हैं जोकी सरकार की अच्छी सोच का प्रतीक है और यमुनानगर में यही अच्छी सोच वास्तविकता में निकलकर सबके सामने आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अनुभवहीनता का परिणाम है या अनुभव का? हमारे यहां पर बहुत सी पीड़ित महिलाए हैं जिनको न्याय मिलने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो हमारी सरकार ने करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सैंटर बनाया था । सरकार को जब लगा कि इससे अच्छा रिजल्ट निकल रहा है और पीड़ित महिलाओं को इसमें अच्छी मदद मिल रही है तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हरियाणा प्रदेश के सात जिलों में लागू करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह योजना अपनी अनुभवहीनता के कारण बनाई हैं या सरकार ने अपने अनुभव से बनाई है या यह योजना अनुभवहीन लोगों के द्वारा बनाई गई है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकारों ने जिनको सरकार चलाने का अनुभव था उन्होंने कभी इस प्रकार की योजनाओं की तरफ ध्यान दिया ? (विघ्न) प्लीज आप बैठिये । मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान) आप बैठिये । **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई)** उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग लड़कियों की शिक्षा के लिए हर बीस किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोलेंगे । हमने लड़कियों के लिए कॉलेज खोले और उन बच्चियों को आने–जाने के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है । आज हमारी सरकार की तरफ से हमारे प्रदेश के हर कॉलेज और हर इंस्टीच्यूशन में बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि हमारी बच्चियों को आने–जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो । उपाध्यक्ष महोदया, हमने केवल इतना ही नहीं किया है । मैंने तो छात्रों के बीच रहकर काम किया हुआ है । हमें भी उस वक्त बड़ी प्रोबलम आती थी कि जब बच्चों का पास केवल 60 किलोमीटर तक का बनता था । जब पास केवल 60 किलोमीटर तक का बनता

था तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों को समस्या आती थी । हमने सरकार को जब छात्रों की इस समस्या से अवगत करवाया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ सौ किलोमीटर तक आने–जाने का बस पास बनाने की मंजूरी दे दी । इससे हमारे प्रदेश के लाखों छात्रों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है । हमारे हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के बेड़े में लगभग 4200 बसें शामिल हैं । हमें इसमें कुछ कमियां महसूस हो रही थी इसलिए 600 और बसों को इस बेड़े में शामिल करने का सरकार ने सराहनीय निर्णय लिया है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस निर्णय की बहुत सराहना करता हूं । आज से पहले हमारे यहां पर जो गरीब लोग हैं, जो बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं या जो भी कोई गरीब व्यक्ति है उनके लिए राशन वितरण प्रणाली बनाई गई थी । उस राशन वितरण प्रणाली में बहुत–सी खामियां थी और उन खामियों के कारण सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वह उनको नहीं मिल पाता था । जब लोगों को वह लाभ नहीं मिल पाता था तो इस समस्या को हमारी सरकार ने पूरे अनुभव के साथ इस पर पूरा गौर किया और गौर करने के बाद हमने ऑटोमेशन ऑफ पी.डी.एस. के सिस्टम को ओनलाइन कर दिया । हमारे इस कदम से इस राशन वितरण प्रणाली में जो धांधली किया करते थे उन पर रोक लगेगी । अब हमने इस प्रणाली को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया है और अब हर व्यक्ति को अपना अंगूठा लगाकर ही अनाज मिलेगा । हमने इसकी पूर्ण योजना बनाकर हरियाणा प्रदेश के लोगों के समक्ष रख दिया है । हमने इतना अच्छा काम किया है और विपक्षी सदस्य कह रहे हैं कि हम अनुभवहीन लोग हैं । मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अगर इनको अनुभव था तो इन्होंने इस प्रकार की योजना को लागू क्यों नहीं किया? उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो लोग बैठें हैं जो किसान हित की बड़ी–बड़ी बात करते हैं क्या उन्होंने किसानों के लिए ऐसी कोई योजना बनाई थी ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे ऐसी योजना बनाकर उसको अमल में लेकर आये थे ? हमारा किसान हमारे लिए पर्याप्त अनाज पैदा करता है और उस अनाज को मंडियों में भेज देता है । मैं जानना चाहता हूं कि उसके भण्डारण और रख–रखाव के लिए इन लोगों ने कौन–सी योजना बनाई थी ? मैं आपके माध्यम से सरकार चलाने का ताजा अनुभव रखने वाले सदस्यों से और पुराना अनुभव रखने वाले सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसान हित की कौन–सी योजना बनाई थी ? उनके पास इस तरह की कोई योजना थी ही नहीं और प्रदेश का अनाज

सड़कों पर सड़ता था । वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी और हमारी सरकार ने अनाज को सड़ने से बचाने के लिए साइलोज जैसी आधुनिक टैक्नीक अपनाई है । (विघ्न) इस टैक्नीक को आधार बनाकर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के साढ़े नौ लाख मीट्रिक टन के गोदाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । उपाध्यक्ष महोदया, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना से लाभ मिलने वाला बताइये कि यह अनुभवहीनता के कारण हो रहा है या अनुभव के कारण हो रहा है। जब भी कोई माननीय सदस्य इस तरह की बात कहे तो इस बात का भी ध्यान रखें। उपाध्यक्ष महोदया, पहले कैरोसिन के लिए बड़ी कालाबाजारी हुआ करती थी। यह कालाबाजारी कौन लोग करते थे? और कौन लोग करवाते थे? इस बात को तो वही बता सकते हैं जिनका राजनैतिक का अनुभव ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि जो हमारी बहन और बेटियाँ रसाई में काम करती हैं उनको धुएँ से कैसे बचाया जाये और कैरोसिन की कालाबाजारी को कैसे रोका जाये उसके एक 'उच्चवला योजना' शुरू की है। उपाध्यक्ष महोदया, इस योजना से हरियणा प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों को फ्री में गैस का कनैक्शन देने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे यह बताया जाये कि यह अनुभवहीनता के कारण है या अनुभव के कारण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को 31 मार्च तक कैरोसिन फ्री करने का लक्ष्य रखा है। क्या इस तरह की सोच पहले किसी सरकार ने सोची है? असली बात तो यह है कि इस तरह की सोच पहले किसी भी सरकार के पास नहीं थी और ना ही किसी नेता के पास थी। इसके अभाव के कारण ही आज हरियाणा प्रदेश डूबा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, उस दिशा में काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने दिव्यांगों की अपंगता की रेशो 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी, जिसका नतीजा यह निकला कि लगभग 32 हजार दिव्यांगों को पैंशन का फायदा होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उन सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने यह कहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ भी नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। क्या उन्होंने इस अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ा है? हमारी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए बहुत सारी स्कीमें लेकर आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल का सपना है कि ''डॉ. भीम राव अम्बेडकर नवीनिकरण आवास योजना'' के तहत जरूरतमंद गरीब से

गरीब व्यक्ति के घरों का नवीनिकरण हो इसके लिए 40 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया है। इस योजना से गरीब से गरीब जरूरतमंद व्यक्ति का भला होगा। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने डॉ. भीम राव अम्बेडकर, संत रविदास जी, महर्षि बाल्मीकि और कबीर दास जी की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है ताकि समाज में इन महापुरूषों के विचारों का प्रचार–प्रसार हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गांव कांकरौला, गुरूग्राम में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा मूंदड़ी, कैथल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय अधिसूचित किया गया है और विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। उपाध्यक्ष महोदया, इतने सारे अच्छे काम केवल जिसकी सोच अच्छी होती है, वही कर सकते हैं। जिन लोगों की सोच अच्छी नहीं होती वे तो केवल इस प्रकार का प्रचार करते रहते हैं कि यह सरकार अनुभवहीन है। इस तरह से लोगों को गुमराह करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, पहले सफाई कर्मचारियों की कोई भी बात नहीं सुनता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदयाः ढांडा जी, आप जल्दी वाईंड अप कीजिए ।

श्री महीपाल ढांडाः मैडम, हरियाणा प्रदेश में पहली बार हमारी सरकार ने अदभूत काम किये हैं। अगर मैं सरकार की उपलब्धियों का बखान करना शुरू करूं तो कई दिन लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस साल पूरे हरियाणा के अन्दर 1580 किलोमीटर सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया गया। ऐसा पहले किसी भी सरकार के समय में नहीं हुआ। आपके इलाके की भी सड़क बनी है। कम से कम स्वागत तो कर दो। (शोर एवं व्यवधान) दौलतपुरिया जी ने भी सरकार की उपलब्धियों को सराहा है। इसके अतिरिक्त एक और अदभूत काम हुआ है, जिसमें लगभग 5600 किलोमीटर सड़कों को रिपेयर किया गया। यह कार्य भी हरियाणा प्रदेश में मिसाल बना। विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्य हमारी सरकार पर अनुभवहीनता का आरोप लगाते हैं। उन लोगों को अपने गिरेबान में झाकने की आवश्कता है उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं है और हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं। मैडम, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि उपलब्धि के लिए काम करना पड़ता है, उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। इस सदन में खड़ा होकर आरोप तो कोई भी लगा सकता है लेकिन विकास कार्य करना अलग बात है।

मैडम, हमारी सरकार की एक और बड़ी उपलिब्ध के बारे में इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि आप कल्पना कर सकते हैं हमारे प्रदेश के 9 नेशनल हाईवे डिकलेयर हो गये हैं और 2 हाईवे डिकलेयर होने बाकी हैं। यह कार्य भी पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पायी है। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। पिछली सरकार के समय के.एम.पी. का पत्थर लगा था उसका भी पता नहीं है। मैडम मैं तो हरियणा में पहले यूवा मोर्चा, किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं। इस कारण से मुझे पूरे हरियाणा में घूमता रहता था। पूरे हरियाणा प्रदेश का मुझे पता है। (विघ्न)

श्रीमती शकुन्तला खटकः मेरी बात सुनिए ढांडा जी।

श्री महीपाल ढांडाः मैडम, मेरे हल्के में बहुत विकास हुआ है मुख्यमंत्री जी ने लठ गाढ राखे हैं (शोर एवं व्यवधान) यह विरोध तो कांग्रेस और चौटाला के लोग करते हैं जो आप लोगों द्वारा भाड़े पर बैठाए थे। मैंडम, जब हम हरियाणा में गांवों में घुमने जाते हैं(विघ्न) तो हर वर्ग का व्यक्ति बोलता है कि प्रदेश में पहली बार सबका साथ सबका विकास की धारणा को अगर किसी सरकार ने पूरा किया तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहली बार बिना भेदभाव के प्रत्येक सड़क के निर्माण कार्य करने का काम इस सरकार ने किया है। मैडम, इतना ही नहीं है। (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटकः आपकी सरकार ने 20–20 लाख रूपये देने की घोषणा की थी।

श्री महीपाल ढांडाः मैडम, इसके अतिरिक्त हमारे हरियाणा प्रदेश में 167 रेलवे फाटके हैं। पिछली सरकारों में किसी का शासन 10 साल तथा किसी ने 5–7 साल राज किया। परन्तु उनको रेलवे फाटकों के बारे कोई जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले माननीय मंत्री राव नरबीर जी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि विपक्ष के किसी सदस्य ने उनसे कहा था कि रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाए होती रहती हैं। जिससे जान–माल का नुकसान होता है। इसका समाधान निकालने का उपाय करें। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच और माननीय पी.डब्लयू.डी. मंत्री राव साहब के प्रयास से इन 167 रेलवे फाटकों पर आर.ओ.वी. और आर.यू.वी बनाने का सारा काम लगभग इसी साल में पूरा हो जाएगा जिससे सभी रेलवे फाटक मानव रहित हो जाएगीं। इसके लिए मैं माननीय

मंत्री महोदय राव नरबीर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता है। मैडम, विपक्षी दल तो काम करने की बजाय सिर्फ सदन के दो–दो घंटे का समय खराब करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदयाः महीपाल जी, आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, यह कोई बात नहीं है इसलिए मैं प्वॉईंट आफ आर्डर पर अपनी बात कहना चाहती हूं ।

श्री महीपाल ढांडाः मैडम, हरियाणा प्रदेश के किसानों को पिछली सरकारों में शुगर मिल की पैमेंट टाईम पर नहीं होती थी।(शोर एवं व्यवधान) जिससे प्रदेश के किसान बहुत दुःखी थे। इस समस्या के समाधान के लिए 1200 करोड़ रूपये की अतिरिक्त व्यवस्था करके उन लोगों को देने का काम हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। किसानों को समय पर पैसे मिल जाए, इसकी योजना पहली बार हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। इतना बड़ा काम किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे डाहर में शुगर मिल है, अभी उसकी सिफ्टिंग की बात हो रही है, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। हमारे यहां करनाल में उसकी पिराई की क्षमता बढ़ानी है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। शाहबाद के अंदर आधुनिकरण कर रहे हैं, शाहबाद के अंदर ऐथेनॉल प्लांट साथ में लगाकर ऐसी शुगर मिल जो घाटे में नीचे जा रही थी, वह अच्छी तरह से खड़ा हो जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है और उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। उपाध्यक्ष महोदया, सहकारिता को इन लोगों ने सरकारी बना दिया था और सरकारी बनाने का नतीजा यह निकला की वो जो शेयर धारक कभी बैठे नहीं और अभी 37 साल बाद पहली बार सब शेयरधारकों की मीटिंग होना, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। ये रिकॉर्ड इनेलो के लोगो ने किया इनेलो वाले लोगों ने तो उसको सरकारी बनाकर उसका बेड़ा गर्क करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, उसकी पूरी की पूरी डिटेल है। आप अपनी सरकार में रहते हुए में जो कुछ काम आपने किए हैं, आप उसकी जरा पूरी रिपोर्ट मंगा लें। उपाध्यक्ष महोदया, इतना ही नहीं है। (शोर एव व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात दो या तीन मिनट में समाप्त कर देता हूं। भ्रष्टाचार के ऊपर कल यहां पर बातचीत हो रही थी, अखबार की कागज लेकर भ्रष्टाचार की बातें हम लोगों को बता रहे थे कि देखों साहब इतना भ्रष्टाचार हो गया। वो खुद खबर छपवा रहे थे खुद लिखवा रहे थे (शोर एवं व्यवधान) और यहां पर आकर खुद ही

दिखा रहे थे। ये नाटक कंपनी के मैम्बर होने चाहिए थे, ये लोग गलत जगह पर आ गए, इसलिए गलत जगह पर आए हैं इसलिए आए हैं कि इनको पता नहीं हम लोगों (शोर एवं व्यवधान) को बोलते हैं (शोर एवं व्यवधान) कि ये लोग पहली बार चुनकर आये हैं। हम पहली बार चुनकर जरूर आये हैं, मगर हमने सड़कों पर आंदोलन किए, हमने सड़कों के ऊपर लोगों की समस्याओं को समझा है और समझ के तब हम लोग यहां पर बोल रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं (शोर एवं व्यवधान) जब हमारी सरकार रही थी। (शोर एव व्यवधान) हरियाणा में टीचरों की तबादलों की (शोर एवं व्यवधान) मैं धनखड़ जी का टाइम ले रहा हूं। मैं पहली बार चुनकर आया हूं आप लोग सुन तो लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, कल ये 80 मिनट बोले हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदया : किरण चौधरी जी आपको बुलायेंगे, आप बैठ जाओ।

श्री महीपाल ढांडा : मैडम किरण जी, आप प्वांयट ऑफ आर्डर बाद में ले लेना। आप 20 बार प्वाइंट ऑफ आर्डर ले चुकी हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : महीपाल जी, आप 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करो।

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप उन लोगों को तो बोलने देते हो और हम लोगों को बोलने नहीं देते हो। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले एक बहुत बड़ा घोटाला होता था, वह था अध्यापकों की ट्रांसफर को लेकर और अध्यापक हर रोज स्कूल छोड़कर खड़ा रहता था। (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात सुन तो लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरा टाइम तो यही लोग खा गए।

उपाध्यक्ष महोदया : सभी को बोलने के लिए 10–10 मिनट का समय दिया गया है। आप सभी बैठिए।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, मलिक साहब 80 मिनट बोले हैं इसलिए अब इन्हें भी बोल लेने दिया जाए।

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, पहली बार ये लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी तबादला नीति लेकर आए कि एक बटन दबाया और 54 हजार अध्यापकों की ट्रांसफर हो गई और वो भी पूरी निष्पक्षता के साथ और उससे 95 प्रतिशत अध्यापक संतुष्ट हैं । हमारी इस तबादला नीति को देश के दूसरे राज्य भी फोलो कर रहे हैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं । मैडम, हमारी शिक्षा, संस्कृति और संस्कार दुनियां में पेटैंट के रूप में हैं । ये सब गीता से मिलता है । यही कारण है कि हमारी सरकार ने गीता को पाठयक्रम में लागू किया है । (शोर एवं व्यवधान) मैडम, इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के 50 साल के इतिहास में पहली बार एक साथ 21 विश्व विद्यालय खोलने की घोषणा की है । (शोर एवं व्यवधान) मैडम, मैं अपनी अंतिम बात बोलकर समाप्त करूंगा । (शोर एवं व्यवधान) मैडम, इसी तरह से हमारी सरकार आने के बाद वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेही बना दिया है । लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा करने के लिए कभी सोचा भी नहीं । (शोर एवं व्यवधान) हमारी सरकार ने जो भी पैसा सरकारी खजाने से जायेगा उसको ऑन लाईन करके पारदर्शी कर दिया है । (शोर एवं व्यवधान) मैडम, हमारे यहां कुछ लोग अंगूली काटकर शहीद होना चाहते हैं और ऐसा ही काम पिछले दिनों एस.वाई.एल. नहर को लेकर हमारे साथियों ने किया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र बलियाला : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, प्वॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहती है । पहले उनको बोलने दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः मैडम, इस तरह से शोर शराबे के माहौल में बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप पहले उन्हें बैठायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेता ने बरवाला में जाकर पत्रकारों को धमकाया था । ये लोग उसकी निंदा करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : मैडम, सदन मर्यादा के हिसाब से चलना चाहिए । यहां हा–हुल्लड़ नहीं होना चाहिए । जब कोई माननीय सदस्य अपनी बात कह रहा होता है और दूसरा सदस्य प्वायंट ऑफ आर्डर कहता है तो उसका मतलब यह होता है कि माननीय सदस्य जो कह रहा है उस पर उसे एतराज है और वह अपनी बात रख सकता है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरा प्वायंट ऑफ

आर्डर उस समय नहीं माना । मैडम, मैं तथ्यों पर आधारित बात करती हूं । माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे वह सही नहीं है । सदन के पटल पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए । सदन में हर बात मर्यादा के साथ करनी चाहिए ।यह बात मैं सबके लिए कह रही हूं ।(शोर एवं व्यवधान) It is not just for you. This is the Hon'ble House. डिप्टी स्पीकर मैडम, मेरा ऑब्जैक्शन है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बी.जे.पी. सरकार का प्रोग्राम है। आज के दिन सच्चाई यह है कि दो साल के अंदर केवल 11 स्कूल ही अपग्रेड हुए हैं। कैग की रिपोर्ट में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। जो माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें रखते हैं तो वे उनको अपने ढ़ंग से रखें। ये न कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये एसा नहीं कर सकते। मैं एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहती हूं कि हम करनाल गये थे। वहां हमें यह बताया गया कि करनाल के अंदरूनी इलाकों की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन सड़कों को ठीक करवा लें। अगर वे ऐसा अभी नहीं करवायेंगे तो आने वाले समय में उनकी यह एक समस्या हो जायेगी। यह सच बात है। इसलिए इसके ऊपर जल्द से जल्दी ध्यान दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः सभी माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपा करके बैठ जायें और संसदीय कार्य मंत्री को बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : डिप्टी स्पीकर मैडम, आज श्री महीपाल ढाण्डा हमारी विधायक पार्टी के एक बहुत ही प्रोमिनैंट लीडर हैं। वे प्रदेश में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। वे प्रदेश में किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं। वे पुख्ता प्रमाणों के साथ अपनी बात कर रहे हैं। अब मुसीबत यह हो रही है कि यदि हम कुछ बोलते हैं तो उसे धैर्य के साथ न तो सुना जाता है और न ही समझा ही जाता है। विपक्ष द्वारा हमारे ऊपर तरह–तरह के आरोप लगाये जाते हैं। हमें अनुभवहीन कहा जाता है। अगर अनुभव वालों की बात मही पाल जी कर रहे थे तो उसको इनको शांति के साथ सुनना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर महोदया, कल चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी 80 मिनट बोले। इसी प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 70 मिनट से अधिक बोले। हमारी तरफ से विपक्ष के सभी साथियों की बात को बड़ी शांति के साथ सुना जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, बिना चेयर की परमिशन के जो भी माननीय सदस्य बोलेगा उसकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। इसलिए आप कृपा करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू व सुव्यवस्थित ढ़ंग से चलने दें। महीपाल जी आप कंटीन्यू करें।

श्री महीपाल ढ़ाण्डा : डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं यह कहने जा रहा था कि हमारी सरकार आने से पहले जब प्रदेश में स्कूल अपग्रेड हुआ करते थे (शोर एवं व्यवधान) वे नेताओं के कहने से होते थे। इसके विपरीत हमारी सरकार के शासनकाल में स्कूल नॉर्म्ज़ के हिसाब से अपग्रेड होते हैं। स्कूलों की अपग्रेडेशन के मामले में इतना बड़ा अंतर आया है। पहले स्कूल नेताओं के प्रैशर से अपग्रेड हुआ करते थे। उस समय नॉर्म्ज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। हमारी सरकार के समय में यह अंधेरगर्दी नहीं हो रही है बल्कि सही तरीके से ही स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है। जोकि काबिले तारीफ है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जहां पर जो जरूरी होता है वहां पर वही होता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हम क्वॉलिटी के बजाए क्वांटिटी के आधार पर बात करते हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि पहले रिजल्ट में पास परसैंटेज 34 प्रतिशत था जो कि हमारी सरकार के समय में अब बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है। अब यह बात इनकी समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कि हमारी सरकार आ जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ या नहीं हुआ? (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर महोदया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यह एक मुद्दा विहीन विपक्ष है। न इनके पास कोई मुद्दा है और न ही इनकी कोई नीति है। मेरा समस्त विपक्ष के साथियों को एक सुझाव है कि ये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़कर समझें और उसमें लिखी सरकार की अच्छी बातों और अच्छे कामों के लिए सरकार की सराहना करें और सरकार का आभार प्रकट करें। सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना अच्छी बात नहीं होती और न ही सिर्फ आलोचना के लिए ही आलोचना करना ही अच्छा होता है। डिप्टी स्पीकर महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सुभाष बराला (टोहाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं

आपका धन्यवाद करता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले 3 दिन से बहुत सारगर्भित चर्चा चल रही है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने अपने–अपने तरीके से अपनी–अपनी बात रखी है। अभी हमारे नौजवान साथी श्री महिपाल ढांडा जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है चाहे वह सड़क की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कॉआप्रेटिव क्षेत्र की बात हो, मैं समझता हूं कि हर विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की है । उपाध्यक्ष महोदया, पिछले 2 सालों में जितने भी काम हुये हैं उन पर हमारे साथी श्री महीपाल ढांडा के अलावा भी और बहुत सारे साथियों ने चर्चा की है । उनके अतिरिक्त मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने विकास के साथ सुधार भी किये हैं । माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास और सुधार के जो कार्य साथ–साथ शुरू हुये उसके परिणाम भी आज हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलने लगे हैं । आज विकास के इतने बिंदु हैं जिनके ऊपर अगर विस्तार से चर्चा करने लग जायें तो बहुत समय लग जायेगा । हमारे बहुत से विधायकों ने उस विकास की गाथा को यहां हाउस में बताया है तथा फिर भी वे अपने समय में उस विकास की गाथा को पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं। पीछे की सरकारों ने भी अपने–अपने तरीके से अपनी सोच के अनुसार कार्य किये हैं लेकिन हमारी सरकार ने बहुत बड़े सुधार के कदम उठाये हैं, विशेष कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का, पारदर्शी शासन देने का, सबका साथ–सबका विकास करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है । प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा के सभी 90 विधान सभा क्षेत्रों में जा कर विकास की जो घोषणाएं की हैं वे काबिले तारीफ हैं । उसमें भी यह नहीं देखा गया कि यह सत्ता पक्ष का विधायक है या विपक्ष का विधायक है, बिना किसी भेदभाव के विकास करने का ऐजेन्डा मेरे ख्याल से पहली बार हमारे मुख्यमंत्री ने रखा है । पहले किस प्रकार से भेदभाव होता था यह हम भी जानते हैं और विपक्ष में बैठे हमारे साथी भी जानते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है । हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता इस बात का पूरा अनुभव रखती है कि किस–किस प्रकार की सरकारें हरियाणा प्रदेश में रही हैं । अगर मैं विकास से हट कर जिक्र करूं तो जिस तरह से हमारी साथी श्री महिपाल ढांडा ने जिक्र किया कि जो हमारा दबा कुचला समाज था उसको किस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है उसके ऊपर चलते हुये अन्तोदय के मंत्र को लेकर उनको विकास की मुख्य धारा में लेकर आया जाये इसके साथ–साथ किस प्रकार से इन समाजों का

आत्मबल बढ़े इस बात के लिए कभी कबीर जयंती, कभी रविदास जयंती तथा कभी महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से आयोजित किये गये। उसमें एक यह बात देखने में आई कि कार्यक्रम का कर्ता भी वही था यानि कि कार्यक्रम की तैयारी भी वही कर रहा था और मंच के ऊपर जाकर के भाषण भी वही हमारे समाज का कार्यकर्ता, हमारे समाज का व्यक्ति दे रहा था । उस कारण से उसमें एक सोहार्द का वातावरण दिखाई दिया । इस प्रकार से चाहे हम कैथल के कार्यक्रम की बात करें या पानीपत के कार्यक्रम की बात करें या जीन्द के कार्यक्रम की बात करें । ढ़ोल नगाड़ों के साथ समाज का दबा कुचला व्यक्ति वहां पर निकल कर के आगे आया था । उपाध्यक्ष महोदया, उन कार्यक्रमों में एक अलग तरह का नजारा देखने को मिलता था । लेकिन पूर्व की सरकारों में केवल और केवल इस प्रकार के नारे और लारे दिये जाते रहे हैं । आज पहली बार इस समाज का स्वाभिमान जगा है तो वह मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जगा है । अभी हमारी सरकार ने घुमन्तु समाज की समस्याओं को इक्ट्ठा करके किस प्रकार से उनकी समस्याओं को समझ कर उनका विकास हो इसके लिये घुमन्तु बोर्ड का गठन किया है जिसमें इस प्रकार की जातियों के लोगों को शामिल किया गया है जिनको आजादी के बाद से लेकर हरियाणा के निर्माण के बाद तक इस बात का कभी अहसास नहीं होता था कि वह भी कभी सत्ता का हिस्सा रह सकते हैं । यह कोई छोटी बात नहीं है । यह एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी के नतृत्व में हुआ है । अभी गऊ की भी चर्चा हो रही थी। गीता की चर्चा भी हो रही थी । सरस्वती की भी चर्चा हो रही थी । मैं इन सभी को नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि गाय को रोटी खिलाता है तो क्या केवल बी.जे.पी. पार्टी वाला खिलाता है ? क्या आप लोग गाय को रोटी नहीं खिलाते ? गीता का अध्ययन करता है तो क्या केवल बी.जे.पी का ही कार्यकर्ता करता है यहां राम बिलास शर्मा जी बैठे हैं जिन्होंने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया क्या वही गीता का अध्ययन करते हैं ? क्या आप लोग गीता का अध्ययन नहीं करते ? गीता ज्ञान का, विज्ञान का जो इतना बड़ा भण्डार है उसको क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के इस विचारधारा के लोग ही मानते हैं ? क्या विपक्ष के लोग इसको नहीं मानते हैं ? जहां तक सरस्वती नदी का जिक्र किया गया जिसके बारे में श्री करण दलाल जी ने भी अपनी बात रखी थी । क्या सरस्वती को नमन केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं ? क्या आप लोग नहीं करते ? लेकिन एक बात है कि आप लोग

गीता का केवल अध्ययन करते हैं । हम गीता का अध्ययन भी करते हैं, उसका मनन भी करते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं । इसलिये इस प्रकार के विचारों में बड़ी भारी भिन्नता दिखाई देती है । जब सरस्वती की बात आती है तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम में से यहां बहुत सारे भूगोल के विद्यार्थी रहे होंगें । **(शोर एवं व्यवधान)**

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, इसका मतलब बाकी यहां सारे नास्तिक हैं ।

श्री सुभाष बराला : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने किसी को नास्तिक नहीं कहा । देखिये बहन जी आप यह गलत बात कह रही हैं । मैंने कहा कि आप लोग भी गीता का अध्ययन करते हैं और हम भी करते हैं । बहन जी, हमने आपके अध्ययन के ऊपर सवाल नहीं उठाया । मैंने कहा है कि आप भी पढ़ते हो और हम भी पढ़ते हैं । मैंने इसका केवल फर्क बताने का प्रयास किया है कि कितना फर्क है और वह बहुत ज्यादा नहीं है । जिसमें अन्तर बहुत थोड़ा है लेकिन समझने का अन्तर है कहने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता । उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी सरस्वती नदी की चर्चा आई थी । देखिये यह भूगोल है और भूगोल के बहुत सारे विद्यार्थी यहां हो सकते हैं । धरती में किस प्रकार की उथल–पुथल होती है । वह एक अलग विषय है, वह एक लम्बी कहानी है । नासा ने सरस्वती नदी के रास्ते का जो वर्णन किया है उसी रास्ते से चलकर के सरस्वती नदी आगे जा रही है । इस बात के प्रमाण हैं । यह मैं नहीं कहता यहां सदन में कल नासा की चर्चा की जा रही थी । इसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी कर रहे थे और अभय सिंह चौटाला जी भी कर रहे थे । उसी नासा के नक्शे पर सरस्वती के रास्ते का एक चित्रण आया है ।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है ।

श्री सुभाष बरालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि इसमें प्वायंट ऑफ आर्डर की कोई बात नहीं है क्योंकि यह कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है । दलाल साहब, मेरे बाद में अपनी बात कह लेंगे । अभी वह मेरी बात सुन लें । दलाल साहब, आप बाद में अपनी बात कह लेना । मेरी बात तो बहुत छोटी है ।

उपाध्यक्ष महोदया : बराला जी, एक मिनट दलाल साहब की बात सुन लो ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि सरस्वती नदी के बारे में जो हमारे माननीय सुभाष जी कह रहे हैं । मैंने तो यह कहा था कि यह मैं नहीं कह रहा दुनिया के जो भूगोल शास्त्री हैं वह यह बात कह रहे हैं कि सरस्वती नदी अगर कहीं थी तो उस सरस्वती नदी को ढूंढ़ना है । यह वह नदी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है । यह नदी तो खट्टर सरस्वती है । यह वह सरस्वती नहीं है ।

श्री सुभाष बराला: उपाध्यक्ष महोदया, दलाल साहब ने बहुत ही गलत शब्दावली का प्रयोग किया है। उनकी इस शब्दावली का मैं केवल यही उत्तर देना चाहूँगा कि इस तरह के पवित्र कार्य करने का दुस्साहस यदि कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था और जिस रास्ते पर सरकार काम कर रही है वह रास्ता सरस्वती नदी का ही है यह कहना दुस्साहस की बात है और इसके एक दिन परिणाम निकलकर सबके सामने आयेंगे? यह कोई छोटी बात नहीं है? विपक्ष के लोगों को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, यदि किसी गलत बात के लिए विरोध किया जाता है तो अच्छी बात है लेकिन जो चीज मानने वाली हो उसके लिए भी अगर विरोध किया जाता है तो यह ठीक बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो सच्चाई है उसको भी स्वीकार करने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। सरस्वती नदी की चर्चा की जा रही है। नदियां समय–समय पर बनती और बिगड़ती रही हैं। इतिहास व भूगोल बताता है कि बहुत सारी नदियों के रास्ते भी परिवर्तित हुए हैं। अगर ईश्वर की कृपा हुई और कल सरस्वती नदी चलने लगती है तो उसका लाभ केवल हमारी सरकार को ही होगा ऐसा नहीं है। निःसंदेह इसका लाभ आप सब लोगों को भी मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदया, सरस्वती नदी की खोज वास्तव में हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता के लाभ की बात है और इससे लोगों की आस्थायें भी जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार सरस्वती नदी जनता के लाभ व आस्था का सममिश्रण है। उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन इस अवस्था में मेरा तो केवल यही कहना है कि सोच को खुला रखना बहुत जरूरी है। अगर सरकार की सकारात्मक सोच व जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना खुले दिमाग से और बिना किसी दलीय भावनाओं के देखा जायेगा तो इनका प्रभाव जनता के साथ–साथ विपक्ष के लोगों को भी दिखाई देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है? कई बार क्या होता है कि

खुली सोच न होने की वजह से सरकार की जो सकारात्मक योजनाएं होती हैं, जिनका परिणाम जनता पर भलीभांति देखा जा सकता है, वह परिणाम हमारे विपक्ष के कुछ साथियों को रास नहीं आता है। विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पारदर्शी सरकार तथा सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रास नहीं आई है और यही कारण है कि विपक्ष द्वारा बीच–बीच में बेबुनियादी मुद्दे खड़ा करने का प्रयास किया जाता है ताकि हरियाणा की जनता व सरकार का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाया जा सके और हरियाणा प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है, उस विकास की गति को धीमा किया जाये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूर्व हरियाणा प्रदेश में भाई–भतीजावाद तथा परिवारवाद अपनी चरम सीमा पर था जिसको पूरी तरह से खत्म करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया। इसके कई उदाहरण कल सदन में हमारे कुछ साथी विधायकों द्वारा रखे गए। असीम गोयल जी यहां बैठे हुए नहीं हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के कैंडीडेट्स जो मैरिट के आधार पर एच.सी.एस. के पद पर सिलेक्ट हुए हैं उनका उदाहरण किस प्रकार सदन में रखा था। अगर इस प्रकार की स्वच्छ शासन व्यवस्था किसी प्रदेश में आती है तो उस स्वच्छ शासन व्यवस्था के कारण जो हमारा देश का भविष्य है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं जिनको देश व समाज का कर्णधार बनना हैं और देश व प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर के जाना है, जिनके ऊपर भविष्य में देश के कल्याण का एक बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है, उस नई पीढ़ी को अगर सही दिशा देने का किसी ने कोई काम किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इस पारदर्शिता के कारण ही जो हमारे लाखों बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उन बच्चों में एक नए आत्म विश्वास और एक नई भावना ने जन्म लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, बेराजगार बच्चे मारे–मारे फिर रहे हैं?(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आप प्लीज बैठिए और जब आपको बोलने का मौका दिया जायेगा तब आप अपनी बात रख लेना।

श्री सुभाष बरालाः उपाध्यक्ष महोदया, पारदर्शी शासन व्यवस्था की वजह से हमारी युवा पीढ़ी ने एक नये हरियाणा के निर्माण का सपना देखना शुरू कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि मां–बाप बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करते थे और उसकी पढ़ाई व लिखाई पर लाखों रूपये खर्च कर दिए जाते थे। मां–बाप की रातों की नींद खत्म हो जाया करती थी लेकिन जब नौकरी का समय आता था तो उस समय किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था यह किसी से छिपा हुआ नहीं है ? हरियाणा की जनता इन चीजों से परेशान थी और बाद में इसके परिणाम भी हरियाणा की जनता ने दिए हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री रणबीर सिंह गंगवाः उपाध्यक्ष महोदया, मछली पालन विभाग में जो भर्तियां की गई थी क्या उनमें पारदर्शिता अपनाई गई थी?

श्री सुभाष बरालाः उपाध्यक्ष महोदया, मछली पालन विभाग की सभी भर्तिया रद्द हुई हैं और इसके बारे में ज्यादा कुछ तो माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बता देंगे मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ठीक रास्ते पर व ठीक गति के साथ नित नए रोज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। यह तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब हरियाणा की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं । हमने इस वर्ष बाबा बंदा बहादुर शाह के बलिदान दिवस का 300वां साल मनाया है । इसी के साथ गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयंती पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाई जा रही है । पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ तीन–तीन पीढ़ियों का बलिदान याद किया गया है । मैं निवेदन करता हूं कि जब इस प्रकार का एक सुनहरा अवसर हम सब लोगों के सामने है तो जो बहुत सारी ताकतें इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करती हैं वे ऐसा न करें । सभी देख रहे हैं कि ठीक रास्ते पर चलती हुई सरकार को कस प्रकार से उसकी दिशा से भटकाने का प्रयास किया जाता है और किस प्रकार से जात–बिरादरी के नाम पर लोगों का आपस में भेदभाव करते हुए उन्हें लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं पूरे सदन के सामने एक निवेदन करता हूं यह जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है अपितु यह जिम्मेवारी विपक्ष के सदस्यों की भी है । राजनीति अपने रास्ते पर चलेगी लेकिन हम सब को मिलकर चलना चाहिए । सरकार का विरोध सकारात्मक रूप से करना चाहिए । इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है । लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन सीमाएं नहीं लांघी जानी चाहिए । आदरणीय अटल बिहारी

वाजपेयी जी ने बहुत–सी कविताएं लिखी हैं । मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा । मेरा अनुरोध है कि इस कविता को आज के हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में लिया जाए । इसे किसी एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में न समझा जाए । यह कविता पूरे हरियाणा प्रदेश के विषय से संबंधित है । प्रदेश के माहौल को ठीक करने की जितनी जिम्मवारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी है । ये पंक्तियां इस प्रकार हैं :–

"दूध में दरार पड़ गई ।
खून क्यों सफेद हो गया ?
भेद में अभेद खो गया ।
बँट गये शहीद, गीत कट गए,
कलेजे में कटार गड़ गई ।
दूध में दरार पड़ गई ।
खेतों में बारूदी गंध,
टूट गए नानक के छन्द
सतलुज सहम उठी,
व्यथित सी बितस्ता है,
वसंत से बहार झड़ गई ।
दूध में दरार पड़ गई ।
अपनी ही छाया से बैर,
गले लगने लगे हैं गैर,
खुदकुशी का रास्ता,
तुम्हें वतन का वास्ता,
बात बनाएं, बिगड़ गई ।
दूध में दरार पड़ गई ।"

उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानक (उकलाना)(एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । (शोर एवं व्यवधान) मैं इस महान सदन में समान विकास के विषय पर बात करना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र उकलाना में मुख्यमंत्री जी गए थे । उनके वहां जाने से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र के लिए अनेक घोषणा करके जाएंगे । मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि पहले तो वहां पर आपस में अध्यक्षता का झगड़ा चलता रहा कि किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा । वहां पर अध्यक्षता का फैसला होने के बाद यह ड्रामा चला कि किसका मांग पत्र पढ़कर सुनाया जाए । माननीय मुख्य मंत्री जी के आगमन की

खबर सुनकर हमारे गांव के सरपंच भी बड़े खुश होकर रैली में गए । वे मुझसे भी कहने लगे कि विधायक जी अगर हमको माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ लेना है तो हमें कम से कम मुख्यमंत्री जी की रैली में जाना तो पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा गांव पाबड़ा बहुत बड़ा गांव है । माननीय मुख्य मंत्री जी की रैली में वहां के लोग कम से कम 70–80 गाड़ियां लेकर गए और उन्होंने अपने इलाके में एक कॉलेज के निर्माण की मांग रखी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल पूरे हलके में जो एक–दो बी.जे.पी. को वोट देने वाले गांव थे उन गांवों की एक–दो मांग को छोड़ करके वहां की किसी भी दूसरी मांग को पूरा नहीं किया । (शोर एवं व्यवधान) दूसरी बात, मैं माननीय शिक्षा मंत्री को भी कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है । जेवरा गांव की एक बच्ची सुश्री पुत्री श्री महावीर सिंह को धक्के से आयरन की गोलियां खिलाई गई । इससे उस लड़की की आंखे चली गई। (शोर एवं व्यवधान) के लिए लगभग डेढ़ महीने में 3–4 लाख रूपये से उसने अपना इलाज प्राईवेट अस्पताल में करवाया लेकिन वहाँ उसका इलाज नहीं हुआ । अब वह लड़की आग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल है। वह लड़की 10वीं की छात्रा है और उसकी आँखें चली गई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं भ्रष्टाचार की बात पर आता हूँ । मेरे निर्वाचन क्षेत्र उकलाना में एक पार्क के निर्माण में 80 लाख रूपये का खर्चा दिखाया गया । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय व स्थानीय निकाय मंत्री से अपील करता हूँ कि उसकी जाँच करवायेंगे तो कम से कम 50 लाख रूपये का घोटाला मिलेगा।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, यह मामला स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित नहीं है। फिर भी हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। यह जिस विभाग का मामला होगा, इसकी जांच करवाई जायेगी। दोषी अधिकारियों केखिलाफ एक्शन भी लिया जायेगा। यदि माननीय सदस्य की बात गलत सिद्ध हुई तो इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, किसी माननीय सदस्य ने यदि हाउस में गलत बात कही है तो क्या उसके खिलाफ भी एक्शन होगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन: उपाध्यक्ष महोदया, विधायक के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः सभी सदस्यगण, अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानकः उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अपनी बात सरल शब्दों में कही है। (शोर एवं व्यवधान) मेरी बात को घुमाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अनूप जी, आप अपनी बात जारी रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वेद नारंगः उपाध्यक्ष महोदया, सदन में सरेआम धमकी दी जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय शिक्षा मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय विधायक अनूप जी ने एक छात्रा सरोज के बारे में हाउस में जिक्र किया है। भाई अनूप जी की चिंता वाजिब है। हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। भाई अनूप जी को आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होने देंगे।

आवाजेंः मंत्री जी, उसके ईलाज के लिए क्या करेंगे?

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, छात्रा के इलाज के लिए हरियाणा सरकार मदद करेगी।

13:00 बजे

श्री अनूप धानकः माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र उकलाना मण्डी से मदनुपर के बीच एक सड़क पर पुल का निर्माण किया गया है। उस पुल को बनाने से जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है अगर वह पुल नीचे से बनाकर गाजू वाला रोड़ में मिलाया जाता तो भी हम कुछ फायदा समझते। उस पुल को भूना रोड़ में मिलाया जाता तो भी कुछ फायदा समझ लेते।

श्री सुभाष बरालाः उपाध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है अनूप जी, वहां पर सड़क बहुत अच्छी बनी है उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए तथा पुल जो बनाया गया है उसकी भी आपको तारीफ करनी चाहिए।

श्री अनूप धानकः उपाध्यक्ष महोदया जी, जो पुल बनाया है उसका जनता को कुछ फायदा तो होना चाहिए (शोर एवं व्यावधान)।

श्री सुभाष बरालाः अनूप जी, उकलाना मण्डी से जो रास्ता टोहना की तरफ जा रहा है उस रास्ते पर आप दो साल पहले भी गये होंगे और अब भी जा कर देंखे, आपको खुद पता चल जायेगा आपको ऐसी बेबुनियाद बात सदन में नहीं करनी चाहिए।

श्री अनूप धानकः उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी बात यह है कि मेरा परसों भी क्यूशचन लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है। जिसमें मैंने गांव श्यामसुख ब्याना खेड़ा और सांभरवास गांव में बस लगाने के लिए डिमांड की गयी थी। माननीय परिवहन मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं इनके विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को गुमराह किया कि वहां बस पहले से ही चल रही हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर अभी तक कोई बस नहीं चलायी गयी है। मंत्री जी मेरा एक सवाल यह था। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल भी लगा हुआ था उसको कोई जबाव नहीं दिया गया है। उसके बाद मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला (शोर एवं व्यावधान) मैं अपने हल्के की डिमांड तो रख सकता हूं।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य तो सवाल कर रहे है। (शोर एवं व्यावधान)

श्री अनूप धानकः उपाध्यक्ष महोदया, टोहाना से सूरेवाला मोड़ होकर जो बस हिसार जाती है वह उकलाना मंडी होकर नहीं जाती। कुछ दिन पहले हमारी बेटियों ने सूरेवाला मोड़ पर धरना भी दिया था। लेकिन फिर भी जो बस उकलाना मंडी होकर जाती थी वह अब नहीं जा रही है। लेकिन सरकार बेटी बचाओं, बेटी पढाओं का प्रचार बड़े जोर–शोर से कर रही है। एक बस प्रभुवाला से सुबह सात बजे कालेज के बच्चों को लेकर हिसार जाती थी। उस बस के लिए परिवहन मंत्री जी ने यह आदेश कर दिये कि एक बस लड़कियों के लिए अलग से चलायी जाएगी। लेकिन उकलाना की बस को हटा दिया गया और जो उकलाना से सवारियां चढती हैं उनको बरवाला उतार दिया जाता है। जिससे बच्चों को कालेज जाने में

परेशानी हो रही है। मैंने जब जी.एम. साहब से इस बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी को स्थिति के बारे में पता नहीं है। जब हमारे पास बसें ही नहीं हैं तो हम बसें कहां से चलाएंगे। मंत्री जी आपके विभाग के अधिकारी जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उनके खिलाफ आप नियमानुसार कार्रवाई करें।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, अगर माननीय सदस्य को ऐसा कहा गया है तो जी.एम. के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

परिवहन मंत्री(श्री कृष्ण लाल पंवार): उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य को मैं इनके सवाल के बारे में बताना चाहता हूं। इनका सवाल टोहाना, हिसार व उकलाना मण्डी से बस चलाने संबंधित था जो किसी कारणवश आज लग नहीं पाया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस रूट पर हरियाणा रोडवेज की 26 बसें टोहाना हिसार और उकलाना मंडी मार्ग पर चलती हैं। जिनके समय 5:30, 6:10, 6:30, 6:47 तथा लास्ट 19:10 है। इसके अलावा सहकारी समितियों की बसों के 20 रूट चलते हैं। कुल 46 रूट इनके एरिया में चलते हैं। मैं उस सवाल के जबाव में यह जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाबजूद भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा हमारे विभाग ने लड़कियों के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग व शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर यह लिखित में ब्यौरा मांगा है कि आपके कालेजों में जो अलग–2 रूटों से लड़कियां पढनें आती है उनकी संख्या कितनी है यह लिखित में भेजें। विभाग की तरफ से जो लिखकर आएगा उसकी हिसाब से हम अलग से उन रूटों बसें पर लगा देगें। इसके अलावा हमारे पास तकनीकी शिक्षा विभाग/शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक हमारे पास 130 रूटों का लिखकर आया है हमने 130 बसें चलवा दी हैं। आप इसके लिए लिखकर भिजवा दें आपकी बस भी चलवा दी जाएगी।

श्री अनूप धानकः मंत्री जी, जो मैंने मांग रखी है। उसके विषय में आपने कहा बस चल रही हैं। वे बसें वहां नहीं चल रही हैं। उनके लिए कह रहा हूं कि वह क्यों नहीं चल रही हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, अगर माननीय सदस्य शिक्षा विभाग से लिखकर भिजवा दें। आपकी लड़कियों के लिए बस चलवा दी जाएगी।

श्री अनूप धानकः मंत्री जी, क्या ये सवाल का जबाव आपने दिया है कि बसें चल रही हैं वह गलत है।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इनको बसों के टाईमिंग बता देता हूं जो इस समय इनके रूट पर चल रही हैं। 46 बसों के टाईमिंग आपके रूट के ऊपर चल रहे हैं।

श्री अनूप धानकः मंत्री जी, यह 46 बसे सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं। मैं कह रहा हूं कि एक भी बस नहीं चल रही है। आप इसकी इंक्वायरी करवा लें।

उपाध्यक्ष महोदयाः ठीक है आप इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है, इस मामले की इंक्वायरी करवा लेते हैं। कुल 46 बसे इनके बताए रूट पर चल रही हैं। जिसमें 26 बसे हरियाणा रोडवेज की हैं तथा 20 बसें सहकारी समितियों की हैं।

श्री अनूप धानक : उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद शिक्षा मंत्री जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, जब तक कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक तहसील की बिल्डिंग और मार्केट कमेटी का ऑफिस था, वे दोनों बिल्डिग्ज खाली हो चुकी हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसी सत्र से कॉलेज की क्लासिज उन बिल्डिग्ज में शुरू करवायें। मेरे हल्के के बिठमड़ा गांव और दूसरे जिन–जिन स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, उन सभी स्कूलों में आप इसी सत्र से क्लास शुरू करवाने का काम करें। एक बार फिर मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आपने सूरेवाला मोड़ पर पिछले बजट सत्र में आई.टी.आई बनाने का जो वायदा किया था, उस आई.टी.आई का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उसका भी काम जल्द–से–जल्द शुरू करवाएं। एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि हमारे भुना रोड के पुल के नीचे से एक आर.यू.बी बनाया जायेगा, लेकिन उस आर.यू.बी का काम की अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार उस आर.यू.बी का भी काम शुरू करवाये। मेरे हल्के का पावड़ा गांव जो पांच गांवों से घिरा हुआ है और उसके साथ दो गांव और भी लगते हैं, वह बहुत बड़ा गांव है। वहां पर पहले नवोदय विद्यालय होता था। नवोदय विद्यालय में एक जे.बी.टी सेंटर भी होता था, लेकिन उस जे.बी.टी सैंटर को किसी कारणवश बन्द कर दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर कॉलेज बनाने का काम करें ताकि हमारी बहन–बेटियों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। इस समय सदन में हमारे

पंचायत मंत्री जी नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि पावड़ा गांव में मेन रोड से स्कूल तक कच्चा रास्ता है, उस रास्ते से होकर हमारी बहन–बेटियों को बारिश में स्कूल जाना पड़ता है, बारिश के दिनों में उस रास्ते पर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, इसलिए सरकार स्कूल के उस रास्ते को पक्का करवाने का काम करे। पिछले साल जब बजट सत्र चल रहा था तो उस समय मेरे पास उपायुक्त महोदया का मैसेज आया था कि आप अपने हल्के के बारे में 1 करोड़ रुपए के काम का एस्टिमेट दे दो, ताकि आपके हल्के में आपके कामों को पूरा कर दिया जाए। उन बातों को आज एक साल हो गया है, मैंने उसी समय मेरे हल्के के लिए 1 करोड़ रुपये के कामों का एस्टिमेट दे दिया था, लेकिन मेरे हल्के में अभी तक 1 रुपये का काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उन कामों को भी जल्द–से–जल्द शुरू करवाने का काम करे। कुछ साल पहले मेरे हल्के के बनभौरी गांव में एक सी.एच.सी मंजूर हुई थी लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सरकार उस सी.एच.सी के काम को भी आगे बढ़ाने का काम करे। सदन में लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। पिछले लगातार 2 सालों से बार–बार मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरे हल्के के गांव फरीदपुर से लेकर दौलतपुर तक दो किलोमीटर सड़क का टुकड़ा है वह पिछले कई सालों से खराब पड़ा है। मैं आपके माध्यम से उन से अनुरोध करूंगा कि उस रोड को भी जल्द से जल्द ठीक करवाने का काम करें। हमारे कृषि मंत्री श्री धनखड़ जी बैठे हैं, उन्होंने मेरे हल्के के गांव की सड़कें जो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जानी है उन सड़कों को संदोन से बालक, कूलेरी से खाराखेड़ी और सौथा से खेड़ीजालब तक बनाने का वायदा किया था लेकिन आज तक उन सड़कों पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन सड़कों के काम को भी जल्दी से शुरू करवाएं। मेरे हल्के के गांव कुंभा से खरखड़ा की जो रोड है वह कच्चा रोड है। जिसके कारण किसानों को अपनी फसल बरवाला मंडी ले जाने के लिए 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। अगर यह रोड पक्का हो जाता है तो बरवाला मण्डी का रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर ही रह जायेगा। हमारा बधौड़ माईनर है और सिवानी माईनर है, उनमें टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए सिंचाई मंत्री जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो वे इन माईनर्ज की टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें। डिप्टी स्पीकर महोदया, जो विधायक निधि है उसके लिए बार–बार

डिमांड करनी पड़ती है। इसके बारे में पिछले सत्र के दौरान बार–बार बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो पार्टीज के सभी विधायकों की तरफ से 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि देने की डिमांड की गई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि विधायक निधि के 5 करोड़ रुपए देने का सरकार काम करे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर महोदया, भाई अनूप सिंह ने बिठमड़ा स्कूल के बारे में बात कही है, मैं माननीय सदस्य अनूप सिंह जी को बताना चाहता हूं कि बिठमड़ा का जो विद्यालय हैं उसमें इसी सत्र से क्लासिज शुरू हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा (पृथला): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । वैसे तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि विधान सभा में मैंबर्ज को बुलाने के लिए सिस्टम बना हुआ है । पार्टीवाईज पोजीशन के हिसाब से समय दिया जाता है और उसी हिसाब से मैंबर्ज को बुलाया जाता है । लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक मात्र सदस्य होने के कारण मुझे बाद में बुलाया जा रहा है । जबकि दूसरे दलों के दो–दो सदस्य बोल चुके हैं । भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये । उपाध्यक्ष महोदया, जब बजट सत्र शुरू होता है तो हर विधायक अपने क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ सदन में कहना चाहता है । लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे जैसे सदस्य अपनी बात कहे बगैर ही रह जाते हैं । बिना बात के सदन में समय जाया किया जाता है जिसके कारण हम अपनी बात नहीं कह पाते । सदन को शुरू हुए आज चौथा दिन है । मैंने बड़े ध्यान से सभी सदस्यों की बातें सुनी हैं । एस. वाई.एल. नहर के मुद्दे पर 4 घंटे हर सैशन में खराब होते हैं । एक सदस्य कहता है कि एस.वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत काम हमने करवाया । फिर दूसरा कहता है कि एस.वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत काम हमने करवाया । तीसरा भी कहता है कि एस.वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत काम हमने करवाया जो अब कांग्रेस में आ गये हैं । इस तरह से एस.वाई.एल. नहर का कार्य 285 प्रतिशत हो गया । इसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई जरूर झूठ बोल रहा है । इसमें हर आदमी 95 प्रतिशत नहर बनाने का श्रेय लेना चाह रहा है । इस तरह का गलत वार्तालाप सदन में नहीं होना चाहिए । हमें ईमानदारी के साथ यहां अपनी बात रखनी

चाहिए। हमारे जो नेता आज स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे बीच में नहीं हैं जिन्होंने एस.वाई. एल. नहर को बनाने की कोशिश की उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, इसमें सच्चाई यह है कि किसी ने भी ईमानदारी से एस.वाई.एल. नहर को बनवाने की कोशिश नहीं की थी । यदि ईमानदारी से एस.वाई.एल. नहर को बनाने की कोशिश की जाती तो यह नहर बहुत पहले ही बन जाती । आज यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है । सुप्रीम कोर्ट ही अब हमें पानी लाकर देगा । सुप्रीम कोर्ट में प्रोपर पैरवी करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने के लिए चाहे 5 या 7 मिनट का समय दिया जाये लेकिन बीच में टोका–टाकी न की जाये । यदि मैं कोई गलत बात कह दूंगा तो उसके लिए माफी भी मांग लूंगा लेकिन बीच में डिस्टर्ब न किया जाये । एस.वाई.एल. नहर के मामले में सच्चाई यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने 1998 में रिवाईज्ड रिट पैटीशन डाली थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है । आज सुप्रीम कोर्ट ही हमें पानी दिलवायेगा । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मुझे बिना बात के डिस्टर्ब न किया जाये । साल भर के बाद बजट सैशन आता है और हर सदस्य इसमें अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है । लेकिन कुछ सदस्यों की मंशा होती है कि वे दूसरे सदस्यों को उनकी बात न कहने दें । प्रश्नकाल के अंदर 20 प्रश्न लगते हैं जिसमें से 10 प्रश्नों का ही सवाल–जवाब हो पाता है । इसका कारण यह है कि कोई इधर से कोई उधर से बिना बात के खड़ा हो जाता है । मेरे इस बजट सैशन में अब तक 4 प्रश्न लगे हैं लेकिन एक भी प्रश्न का रिप्लाई नहीं हो पाया । हम न तो अपनी बात प्रश्नकाल में पूछ सकते और न अब हमें बोलने दिया जाता । मेरा अपने सीनियर साथियों से अनुरोध है कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाये । वे जिस समय बहस का मुद्दा हो उसी समय बहस करें । बिना बात के सदन में न खड़े हों । उनको सुनने का भी मादा रखना चाहिए।**(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरा आगरा नहर पर गांव चांदवाली में बल्लभगढ़ मोहना मार्ग पर पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाने का प्रश्न राव नरबीर जी के विभाग का लगा हुआ था लेकिन उसका रिप्लाई नहीं हो पाया । राव साहब शोर्ट में जवाब देते हैं और उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं में दे दिया । अध्यक्ष महोदय, यदि उस पर सवाल–जवाब हो जाता तो मुझे विश्वास है कि मंत्री जी उसका जवाब हां में कर

देते । अध्यक्ष महोदय, अगर मान लें यह प्रश्न आ भी जाता तो राव साहब उसको मानते और उस पुल को बनवाने का आश्वासन देकर उसको हर हाल में बनवाते। ऐसी मुझे उम्मीद है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री टेक चंद शर्मा जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस पुल का इन्होंने अभी जिक्र किया है उस पुल को बनवा दिया जायेगा। स्पीकर सर, मैं इनको यह ऑप्शन भी देता हूं कि अगर इसके अलावा भी ये कोई और पुल बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बता दें मैं इनके सभी पुल बनवा दूंगा।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, इसके लिए मैं माननीय मंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, आज यहां पर एस.वाई.एल. कैनाल और जाट आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी पार्टियों के माननीय साथी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब कोई विरोध ही नहीं है तो फिर अड़चन किस बात की । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण के मुद्दे को बार–बार बिना आवश्यकता के नहीं उठाना चाहिए। मैं एक बात यहां यह भी बताना चाहूंगा कि एक पार्टी के प्रदेश से लोक सभा सांसद कहते हैं कि आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए लेकिन इसके विपरीत उसी पार्टी के इस सदन में सदस्य यह कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर न होकर जातिगत आधार पर होना चाहिए। यह बात मैं और क्लीयर कर देता हूं कि 31 जनवरी, 2017 को गुरूग्राम में श्री दुष्यंत चौटाला जी ने यह कहा था कि आरक्षण जातिगत आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यह खबर दैनिक जागरण न्यूज पेपर में छपी थी। यह यहां पर सदन का समय बर्बाद करने वाली बात होती है। पार्टी के नेताओं को किसी भी विषय पर बयान देने से पहले आपस में सलाह–मशविरा कर लेना चाहिए। एक सांसद अलग बात कह रहा है और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष अलग बात कह रहा है। अगर उनके द्वारा आपस में सलाह कर ली गई होती तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। इससे सदन का समय भी खराब होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, मायावती जी जो बहुजन समाजपार्टी की राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं उन्होंने जाटों को आरक्षण देने की वकालत की थी और श्री टेक चंद शर्मा जी जाटों को आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता

हूं कि क्या इन्होंने अपनी पार्टी की शीर्ष नेता से इस बारे में सलाह–मशविरा नहीं किया था।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, यह एक बड़ा अजीब सा विषय है। माननीय साथी या तो इस बारे में सुनना नहीं चाहते या फिर इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। जब यहां पर यह विषय आया था तो हमने सरकार को सपोर्ट किया था। अपने विचार व्यक्त करना अलग बात होती है लेकिन जहां पर एजेंडे की बात आती है वहां पर हमारी सपोर्ट सरकार के साथ होती है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर यह मामला कहीं अटका हुआ है तो वह इनेलो के कारण ही अटका हुआ है हमारी तरफ से इसमें कोई अड़चन नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर सिंचाई के विषय को उठाया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय अगर हरियाणा को मिलने वाले पूरे पानी का उचित और न्यायसंगत बंटवारा हो जाये तो उससे दक्षिणी हरियाणा की भी प्यास बुझ सकती है और इससे वहां पर भी माहौल चेंज हो सकता है। अगर हमारे हिस्से का पानी सिरसा और हिसार जिले को दे दिया जाता है तो यह भी पूरी तरह से गलत बात है। इसमें भी हमारा यही सुझाव है कि हरियाणा प्रदेश में उपलब्ध पानी का न्यायोचित बंटवारा करके पलवल और फरीदाबाद को भी साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाये और दूषित पानी से मुक्ति दिलवाई जाये। हमारे किसान अपनी जमीन की सिंचाई सीवर के पानी से करने को मज़बूर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पृथला के अंदर स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। इस यूनिवर्सिटी का बहुत जल्दी निर्माण होने जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है इस यूनिवर्सिटी के टैम्परेरी ऑफिस को गुड़गांव शिफ्ट न किया जाये और इसे पृथला में ही बनाया जाये। यह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत, धुधौला ने इसके लिए 85 एकड़ जमीन और रेनीवैल के लिए 6 एकड़ जमीन कुल मिलाकर 81 एकड़ जमीन दी है। इस जमीन की कुल कीमत लगभग 250 करोड़ रूपये के आसपास है । यह बहुत कीमती जमीन है। इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि वहां के स्थानीय निवासियों के लिए एडमिशन और इम्पलॉयमैंट में कम से कम 5 परसैंट का कोटा रिजर्व किया जाये ताकि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

श्री अध्यक्ष : टेक चंद जी, कृपया वाइंड–अप करें।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, मुझे बोलते हुए अभी सिर्फ तीन मिनट ही हुए हैं। इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि मुझे अपनी बात कहने के लिए पूरा समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है टेक चंद जी, आपको जो भी कहना है उसे कृपया जल्दी कहें और अपनी बात कहकर जल्दी वाइंड–अप करें।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा में सरकार के माध्यम से कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम यह देखना था कि हर विधान सभा क्षेत्र के तहसील, सब–डिविजन, थाने इत्यादि सभी एक ही जगह पर होने चाहिएं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरा पृथला विधान सभा क्षेत्र 2 जिलों पलवल और फरीदाबाद में बंटा हुआ है । इसके 4 सब–डिविजन पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खल लगते हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 तहसील हैं जिनमें पलवल, बल्लभगढ़, मोहना, गोंछी और गोंछी तो अभी नई तहसील बनी है जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र से कुछ गांव निकाल कर उसमें लगा दिये गये जबकि वह एन.आई.टी. का क्षेत्र पड़ता है। इसी तरह से बी.डी.पी.ओ. कार्यालय बल्लभगढ़, पृथला, फरीदाबाद और तिगांव पड़ते हैं । तिगांव का जो नया ब्लॉक बना है उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव लगा दिये गये हैं । मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख कर भी दिया है कि मेरी अनुमति के बिना जबरदस्ती मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों को तिगांव तथा गोच्छी सब–डिविजन में जोड़ दिया गया है जो कि गलत बात है । इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव जो नया सब–डिविजन बड़खल बना है उसमें भी जोड़ दिये गये । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसको रिवाइज किया जाये । सौभाग्य से उस समिति के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी यहां पर बैठे हुये हैं उन्होंने नोट भी कर लिया है और आपको भी मैंने यह पत्र दे दिया है इसलिए उनसे भी मेरा निवेदन है कि इसको रिवाइज किया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में वॉटर लॉगिंग की समस्या है । वहां पर 6–7 गांव भनकरपुर, कबूलपुर, सिकरोना, फिरोजपुर कलां हैं इनमें सेम की समस्या है । मैंने पत्र लिख कर भी दिया है कि उस वॉटल लॉगिंग की समस्या का समाधान किया जाये । मैं अपनी भावनाओं को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि लोगों को जा कर कह तो सकूं कि मैंने आपकी बात सरकार तक पहुंचा दी है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता

हूं कि मोहना में 7 एकड़ जमीन 2005 में आई.टी.आई. बनाने के लिए दी गई थी । वह जमीन आई.टी.आई. के नाम पर है लेकिन वहां पर अभी कोई काम नहीं हुआ है इसलिए वहां पर टीचिंग स्टाफ के लिए कोई सैन्टर बना कर उसका दोबारा ठीक ढंग से यूटीलाईजेशन किया जाये । इसी तरह से फतेहपुर बिलौच में 6 एकड़ जमीन ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमैंट ने ली थी और वह पंचायत की जमीन थी तथा वह जमीन सी.एच.सी. के लिए ली गई थी । उसकी चारदिवारी हो चुकी है लेकिन वहां पर अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि या तो वह जमीन पंचायत को वापिस की जाये या वहां पर काम शुरू करवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो आगरा नहर का पानी है वह बिल्कुल तेजाब के माफिक है वह कृषि योग्य नहीं है । इस बारे में कल मंत्री जी ने श्री उदयभान जी के प्रश्न के जवाब में भी बताया था कि उस पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए । यह हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष है इस वर्ष में तो सरकार इस काम को कर दे ताकि हम जनता के सामने यह कह सकें कि इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमने आपको पीने का साफ पानी उपलब्ध करवा दिया । इसी तरह से फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी । हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए चुना गया है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं उनमें अवैध तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है । अवैध कालोनियां काटकर वहां पर बिल्डिंग्ज बनाई जा रही हैं । अगर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करना है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए । इसी प्रकार से जो अवैध भूजल दोहन किया जा रहा है वह भी गलत है । जो ट्यूबवैल्स सरकार की तरफ से लगाये गये हैं उनसे अवैध तरीके से पानी लिया जाता है तथा बाद में उसी पानी को सरकारी कालोनियों में दिया जाता है । इसलिये इस पर सख्ती के साथ निपटा जाए । इसके साथ–साथ हमारे यहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक रेनीवैल की स्कीम एप्रूव की गई है । उसके लिये हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं । रेनीवैल की स्कीम मेवात में भी काम कर रही है और फरीदाबाद में भी काम कर रही है । अब यह रेनीवैल स्कीम पृथला, हथीन और पलवल के गांवों में भी लागू की जायेगी । हमारे यहां मोहना में एक बैराज का होना बहुत जरूरी है इसलिये यमुना नदी पर भी एक बैराज बनाना चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र का जल स्तर काफी

नीचे चला गया है इसलिये आप से अनुरोध है कि जिस तरह से मथुरा, यू.पी. और गोकुल में बैराज बना हुआ है उसी आधार पर मोहना में भी बैराज बनाया जाता है तो हमारे क्षेत्र का वाटर लैवल ऊंचा आ सकता है । जिससे फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों के सभी गांवों को पानी की सप्लाई प्रोपर रूप से कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, कल मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था लेकिन उस प्रश्न का नम्बर नहीं आया । मैंने वह प्रश्न मंत्री महोदय से के.एम.पी. और ई.पी.ई. एक्सप्रैस वेज के लिये पूछा था कि इन एक्सप्रैस वेज के दोनों तरफ औद्यौगिक क्षेत्र को डिवैल्प करने का क्या विचार है ? मन्त्री जी ने उसके जवाब में यह कहा था कि इसके लिये हमने एक संस्था इण्टरनैशनल कम्पनी को एम.ओ.यू. दिया हुआ है और हम इसका 30 जून तक एक मैप बना देंगे कि किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को डिवैल्प किया जाए । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि यहां लगभग दोनों तरफ दो किलोमीटर के जिन क्षेत्रों को डिवैल्प करना है उसके लिए लोकल इम्प्लाईमैंट का कोटा रखा जाए जिससे कि वहां के बच्चों को रोजगार मिल सके । वहां पर किसी भी तरीके से जो सरकार की सब्सिडाइज्ड पॉलिसी हैं उसमें उस क्षेत्र के लोगों को सब्सिडी दी जाए । मैं ज्यादा न कहते हुए अपना स्थान लेता हूं क्योंकि मुझे बोलते हुए समय बहुत हो गया है बाकी बातें मैं बजट पर भी बोलूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पृथला के अन्दर एन.एच.–2 पर एक टोल बनाया जा रहा है । उसके बारे में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस पर तब तक टोल लगाना शुरू न किया जाए जब तक वह रोड़ छः लाईन का पूरा नहीं हो जाता है । पहले भी इस रोड़ पर टोल बना कर मामला बढ़ाया गया था । जहां तक बोलने की बात है बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अपनी बात सदन में रखनी है और भी नये साथी हैं उनको भी शांति पूर्ण ढ़ंग से सुना जाए जैसे मेरी बात को सुना है । उसके लिये मैं पक्ष और विपक्ष सबका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसलिए जो नये साथी बोलें उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए । धन्यवाद ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो बोलने का नम्बर आया हुआ था आपने ही मेरा नम्बर लगाया था । मैंने तो उनको बोलने का मौका दिया है ।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं आपको इनके बाद बुलवा देंगे ।

श्री उदय भान(होडल)(एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार का जो अभिभाषण पढ़ा । उस नीतिगत दस्तावेज के संबंध में मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें एक वर्ष तो सरकार के बारे में जानने में लगा और एक वर्ष हमें सरकार की नीति बनाने में लगा है और अब जो समय है वह सरकार के कार्य करने का है । मैं समझता हूं कि इस सरकार ने ढ़ाई साल में सिर्फ समारोह और मेले ही आयोजित किये हैं जिसमें सरकारी पैसे का और सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग ही किया है । सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती, गीता महोत्सव, सरस्वती, बसंत मेला, डीजी धाम, औद्यौगिक और दूसरे रागनियां, सांग वगैरह पर बुरी तरह से पैसा बहाया गया है और इस दौरान प्रदेश का कोई भी कार्य नहीं हुआ है । सरकार ने इस बात को खुद माना है कि हमें अनुभव नहीं था इसलिए अनुभव के लिये (शोर एवं व्यवधान) सरकार ने तजुर्बे के लिये हरियाणा से नहीं हरियाणा से बाहर दूसरे प्रदेशों से आर. एस.एस. के मास्टर्ज इम्पोर्ट किए हैं। जिनको मुख्यमंत्री व मंत्रियों के कार्यालयों में, सभी जिलों में तथा डी.सी आफिसिज में लगाया गया है। यह आर.एस.एस. के मास्टर दो अढ़ाई साल से जिन कार्यालयों में लगे हुए हैं वहां पर प्रदेश के संसाधनों का दुरूप्रयोग कितनी बेरहमी से किया गया होगा यह देखने वाली चीज है? यह भी प्रश्न उठता है कि उनसे क्या सीखा गया है? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। गरीब कल्याण वर्ष में सरकार ने गरीबों के प्रति कुछ वायदे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषण पत्र जिसकी कॉपी मेरे पास है, में भी गरीबों से कुछ वायदे किए थे। मैं समझता हूँ कि उन वायदों को भी गरीब कल्याण वर्ष के तहत किए गए वायदों के साथ शामिल करते हुए पूरा किया जाये। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शहरों में बी.पी.एल. परिवारों को 50–50 गज जगह के प्लॉट्स दिए जायेंगे व मकान बनवाये जायेंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार में जो गरीब परिवार 100–100 गज के प्लॉट्स लेने से वंचित रह गए थे उनको भी प्लॉट्स देने व इफ्रास्ट्रक्चर देने का काम सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत गलियों, नालियों, बिजली व पानी आदि की भी व्यवस्था गरीब कल्याण वर्ष में गरीब लोगों को मुहैया करवाने में की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लघु व कुटीर उद्योगों के लिए भी वायदे किए

गए थे कि बगैर गारंटी के दो लाख से दस लाख रूपये तक का लोन चार प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा, मैं समझता हूँ कि इसको भी सरकार जरूर लागू करेगी और बताया जाये कि इस कार्य के लिए कितने लोगों को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है तथा इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा गरीबों व सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करने तथा उनकी न्यूनतम मजदूरी 15000 रूपये करने संबंधी बात भी कही गई थी। मैं समझता हूँ कि सरकार को इन चीजों को गरीब कल्याण वर्ष के वायदों में शामिल करते हुए पूरा करना चाहिए। केवल जयंतियां मनाने से या केवल भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि गरीबी हटानी है तो इसके लिए धरातल पर ठोस कार्य करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त सरकार ने खुले में शौचमुक्त हरियाणा की बात करते हुए 14 जिलों का नाम दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई जुमला और कोई दूसरा हो नहीं सकता। सरकार 14 जिलों की बात कर रही हैं जबकि वास्तव में प्रदेश में 14 गांव भी ऐसे नहीं हैं जिनको खुले में शौचमुक्त गांव कर दिया गया हो? केन्द्र सरकार की तरफ से टेलीविजन पर एक बहुत बड़ी एडवर्टिजमैंट आती है जिसमें अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा शौचालयों के लिए ग्रांट दी जाती है। अगर ग्रांट दी जाती है तो यह जाती किसके पास है? ग्रांट किसको दी गई है? यह जानने वाली बात है। वर्ष में एक भी नया पैसा इस मद में खर्च नहीं किया गया है? पलवल जिले में एक पैसा भी शौचालय के मद पर खर्च नहीं हुआ है। आर.टी.आई. से प्राप्त सूचना के हिसाब से सिर्फ 8 शौचालय बने हैं और बड़े–बड़े दावे किए जाते हैं कि हरियाणा को खुले में शौचमुक्त प्रदेश कर दिया गया है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जो कि इस बात की पुष्टि करता हो कि जिसको खुले में शौचमुक्त गांव कर दिया गया हो? यह सारे जुमले बंद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी वायदा किया था कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर बी.पी.एल.परिवारों को एक रूपया किलो अनाज उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप मे मनाया जा रहा है अतः इस गरीब कल्याण वर्ष में एक रूपया किलो अनाज देने के वायदे को भी पूरा किया जाना चाहिए। मैं आज उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अतः अब कंक्रीट अर्थात धरातल पर कुछ कर दिखाने की जरूरत है केवल जुमले मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा यह भी अनुरोध है कि जिन प्राईवेट स्कूलो को सरकार ने जमीन उपलबध कराई है, उन स्कूलो में 25

प्रतिशत सीटों पर गरीबों के बच्चों के दाखिले करवाये जायें। सिर्फ वायदा करने से कुछ नहीं होता है बल्कि हकीकत में कुछ कर दिखाने से ही कोई फायदा होता है। इस गरीब वर्ष में गरीबों के बच्चों के लिए छात्रावासों के निर्माण कार्य को भी करवाया जाना चाहिए। सरकार का अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम धरातल पर देखने को नहीं मिला है। अब सरकार अगले अढ़ाई वर्ष में क्या करने जा रही है? जहां तक अस्पतालों की बात है, इनमें 25 प्रतिशत गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने की बात कही गई थी । पूर्व की सरकार के समय बी.पी.एल. परिवारों को निशुल्क इलाज करवाने के लिए हैल्थ स्मार्ट कार्ड दिए गए थे, मेरा सुझाव है कि इस स्कीम को भी पुनर्विचार करते हुए दोबारा से लागू करने की आवश्यकता है । इसी प्रकार जैसाकि 2 लाख रूपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा देने की बात कही गई थी, उस पर भी विचार करने की जरूरत है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति आयोग को अधिकार संपन्न बनाया जाए ताकि अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाली जुल्म की घटनाओं का तुरंत निपटारा हो सके और अपराधियों का दण्ड सुनिश्चित किया जा सके । पहले जो अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया था उसको भी सरकार ने भंग कर दिया था इस लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर पुनर्विचार करें। अनुसूचित जाति आयोग तुरंत बनाने की कृपा करें ताकि इस आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकें और जो अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाली घटनाएं हैं वे कम हो सकें । अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरी में पहले पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता था । सरकार बनते ही कैबिनेट की मीटिंग में इस सरकार ने वायदा किया था कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा । कोर्ट में सरकार द्वारा इस केस की पैरवी के लिए जिन वकीलों को भेजा जाता है वे वकील भी एंटी दलित हैं । पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सरकार कुण्डली मारकर बैठी है और इस विषय पर कोई बात नहीं कर रही है । उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जो डी.सी. रेट पर, कांट्रैक्ट पर और एडहॉक बेसिज पर भर्ती हो रही है उसके बारे में मैं समझता हूं कि वह संविधान के विरूद्ध है और रिजर्वेशन पोलिसी के एकदम खिलाफ है । यही कारण है कि अनुसूचित जाति का बैकलॉग बढ़ रहा है । आज भी शिडयुल कॉस्ट्स का बैकलॉग 7,169 पोस्ट्स का है । इसी तरह से सी कैटेगरी में 560 पोस्ट्स का, डी कैटेगरी में 270 पोस्ट्स का बैकलॉग है । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में

कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात भी कही थी लेकिन अभी तक इस बारे में सरकार चुप बैठी हैं । सरकार का जो 20 सुत्री कार्यक्रम है उसमें भी और ज्यादा काम करने व ज्यादा बजट एलोकेशन की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के प्राइमरी स्कूल्ज, मिडिल हाई स्कूल्ज तथा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल्ज में शिडयुल्ड कास्ट्स व बैकवर्ड क्लासिज के 75–80 परसैंट बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इन स्कूल्ज में टीचर्स की भारी कमी बनी हुई है । कॉलेज और स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप रेट्स बहुत ही ज्यादा हैं इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में प्रदेश में चार पावर प्लांट्स लगाए गए थे लेकिन इस समय इन प्लॉटस् से पूरी बिजली पैदा न करके अडानी ग्रूप से बिजली खरीदी जा रही है । सरकार की यह बात बिल्कुल असत्य है कि गांवों में 16 घंटे और 24 घंटे बिजली दी जा रही है । यह बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है । 7–8 घंटे से ज्यादा गांव में बिजली नहीं आ रही है इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस बारे में जनता को गुमराह न करे और बिजली की स्थिति में सुधार करे । सब–स्टेशंज को भी मजबूत करने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी पंडित टेक चन्द शर्मा जी ने आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल से कम पानी प्राप्त होने संबंधी बात की है मैंने भी इस संबंध में एक प्रश्न लगाया था जोकि लग नहीं पाया । आज हमारे इलाके में जो पानी दिया जा रहा है वह पूरी तरह से प्रदूषित है और सरकार भी इस बात को भलीभांति मान रही है लेकिन कोई कदम न उठाकर वह बिल्कुल बेखबर बनी हुई है । मैने पिछले सैशन में भी इस बारे में कहा था लेकिन आज तक भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है । यमुना नदी में जो नाले गिर रहे हैं उनके नदी में गिरने से पहले उनके प्लांट में किसी में भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगे हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको दिल्ली सरकार को मजबूर करना चाहिए और उनको वार्निंग देनी चाहिए कि अगर आप यमुना नदी में डाले जाने वाले पानी को ट्रीट करके नहीं डालोगे तो हम तुम्हारा पानी हरियाणा में आना बंद कर देंगे ताकि जो पानी दिल्ली के बाद यमुना नदी में आए वह साफ आए । यह पानी ऐसा हो जिसे लोग उपयोग कर सके । इस प्रदूषित पानी की वजह से हमारा पलवल, मेवात तथा फरीदाबाद जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि वहां पर इस पानी की वजह से कैंसर और हड्डी रोगों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं । (विघ्न) अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए

केवल एक छोटी–सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी थोड़े दिन पहले ही माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी पलवल आये थे । उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि हसनपुर में यमुना के ऊपर पुल बनाया जाएगा लेकिन अभी तक उस दिशा में कार्यवाही शून्य है यानी बिल्कुल भी कार्यवाही नहीं हुई है । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इसकी तरफ ध्यान दे । होडल की अनाज मण्डी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मण्डी है। कांग्रेस के राज में इस अनाज मण्डी के लिए 99 एकड़ और 17 मरले जमीन एक्वायर हुई थी। विकास के लिए पैसे भी पहुँच गए थे लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण नई सरकार बनते ही काम रोक दिया गया। वर्ष 2015 में इस मण्डी के विकास के लिए मैंने एक प्रश्न भी लगाया था। उस समय माननीय कृषि मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि अनाज मण्डी के विकास का काम शुरू किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी भी इस अनाज मण्डी की चार दीवारी पूरी नहीं हुई है। इस अनाज मण्डी में जो विकास होना था जैसे सड़कें, प्लेटफार्म, शैड, ऑफिस, गैस्ट हाउस सारे के सारे काम पैंडिंग पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पिछली सरकार के समय में कॉलेज की नई बिल्डिंग के लिए 26 करोड़ रूपये मंजूर हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इसका काम शुरू करवा देंगे लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल अनाज मण्डी के साथ होडल में बनना था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने भी इसे बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन अब मुझे अखबार से सूचना मिली है कि इस अस्पताल को ड्रॉप कर रहे हैं और पहले वाले अस्पताल को ही अपग्रेड करके सब–डिविजन अस्पताल बना दिया।

श्री अध्यक्षः उदय भान जी, आप जल्दी वाईंड अप कीजिए।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 22 कॉलेजों का उद्घाटन किया था, उसमें भी मेरे हल्के का कॉलेज छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि कन्या महाविद्यालय खाम्बी में जरूर बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पॉलिसी बनाई है की हर ब्लॉक में एक आई.टी.आई. जरूर होगी लेकिन होडल में कोई भी आई.टी.आई. नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डिघोत में वौकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट हैं, इसलिए वहाँ पर बिल्डिंग भी बनी हुई है और जमीन भी पर्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, केवल स्टॉफ भेजकर डिघोत को आई.टी.आई. का

दर्जा दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, होडल और हसनपुर दोनों जगहों पर बस स्टैंड बनने थे, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में मंजूर है लेकिन सरकार की तरफ इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। होडल में पानी और सीवरेज व्यवस्था के लिए स्कीम भेजी हुई है उसके लिए पैसे मंजूर किए जाये। मेरे हल्के के आठ गांवों के लिए एक कलस्टर पीने के पानी के लिए बनना था, उसे भी मंजूर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 22–23 हजार के करीब है और इन गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए लगभग 8 करोड़ रूपये का एस्टीमेट भी आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही लगातार विकास के कार्य कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूँगा कि लगभग दो साल पहले रादौर विधान सभा क्षेत्र में आए थे और 2 करोड़ 73 लाख रूपये विकास के नाम पर देकर गये थे। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के 10 वर्ष के राज में यहां के लोगों को विकास के नाम पर काफी उम्मीदें थी लेकिन उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब चुनाव हुए तो यहां के नाराज लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चारो उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया। अध्यक्ष महोदय, जो सड़क कुरूक्षेत्र से यमुनानगर जाती है, कांग्रेस के शासन काल में जब कोई मुसाफिर उस वक्त इस सड़क से बस में सफर करते हुए यमुनानगर आता था तो यमुनानगर की सीमा तक तो उसका सफर आराम से कट जाता था लेकिन ज्यों ही यमुनानगर की सीमा से आगे का सफर शुरू होता तो उस सड़क पर गड्डे होने की वजह से बस यात्री का बुरा हाल हो जाता था और वह सहज ही कहने लग जाते थे कि यमुनानगर की सीमा शुरू हो गई है। यमुनानगर की इस सड़क का बहुत बुरा हाल कांग्रेस की सरकार के समय हुआ करता था। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सड़क को 20 करोड़ रूपये की लागत से चौड़ा करवाया है। रादौर हल्के में कलानौर से लेकर कैल तक बाईपास बनाया गया है। जिसकी वजह से यमुनानगर, फरीदाबाद और पानीपत जो कि

प्रदूषण की वजह से रहने के लायक नहीं थे, इनमें अब बहुत कुछ सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यमुनानगर से लेकर गुमथला तक की सड़क का भी बहुत बुरा हाल था। अगर वास्तव में कोई साथी इस बात को आज भी जाकर देखें तो पायेंगे कि कहीं पर कोई नर्क था तो वह यमुनानगर की कापी माजरा और रायपुर की कालोनियों के अन्दर था। यहां पर एक परिवार का व्यक्ति जब नहाता था तो घर के बाहर पानी का जो गड्डा होता था, जब तक उस गड्डे का पानी बाहर नहीं निकालते थे तब तक घर का दूसरा व्यक्ति नहा नहीं सकता था। आज हमारी सरकार ने 70 करोड़ रूपये की लागत सेसीवरेज की लाईन वहां पर मंजूर की है। यही नहीं जगाधरी से लेकर पंचकुला तक फोरलेन सड़क बनाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। प्रदेश के अन्दर 9 हाईवे बनाने का काम भी श्री मनोहर लाल जी की सरकार तथा केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने शुरू किया है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के शासन में उपभोक्ता 1–1 सिलेंडर के लिए भी तरसते थे वह भी समय था जब सांसद से गैस कनैकशन व सिलैण्डर मन्जूर करवाये जाते थे (शोर एवं व्यावधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में भी बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर दिये गये थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी से कहना चाहता हूं कि आपने अपने समय में दिये होंगे लेकिन बहुत थोड़े दिये होंगे उस वक्त आप ग्रीन बिग्रेड के अध्यक्ष थे। लेकिन हमारी भाजपा की सरकार ने की देश के अन्दर गैस के 5 करोड़ सिलेण्डर देने का काम किया है।

श्री अध्यक्षः यह तो बहुत पुरानी बात है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, जो 5 करोड़ सिलेंडर दिये गये हैं क्या वे पूरे देश के बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये हैं या अकेले हरियाणा प्रदेश में दिये गये हैं ?

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने 5 करोड़ सिलेंडर देश के गांवों के अन्दर देने का काम किया है। जहां पर लकड़ी से रोटी बनाई जाती थी जिससे धुंआ होता था। बहुत ज्यादा काम आज हमारी सरकार ने किये हैं यह सब आप जानते हैं हमारी सरकार विकास को लेकर काफी गंभीर है। हमारी सरकार ने 20 एकड़ में मंडी बनाने की घोषणा की है। (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः जयप्रकाश जी ये जो 5 करोड़ सिलेंडर बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये हैं वे अकेले हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में वितरित किये गये हैं।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, बात हरियाणा की हो रही है। माननीय सदस्य क्या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को एड्रस कर रहे हैं, यहां पर तो गर्वनर ऐड्रस पर चर्चा हो रही है।

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ सिंलेडर पूरे देश में दिये हैं ढ़ाई करोड़ सिलेंडर बट चुके हैं और इतने ही सिलेंडर अभी बांटे जाने बाकी हैं। स्पीकर सर, विकास की दृष्टि से रादौर और यमुनानगर बहुत पिछड़े हुए थे।

श्री जयप्रकाशः अध्यक्ष महोदय, जब मैं केन्द्र में मंत्री था तब बी.पी.एल. परिवारों को सिलेंडर दिये गये थे। यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री अध्यक्षः जयप्रकाश जी, कोई बात नहीं है। आपको बोलने का समय दिया जाएगा तब आप गवर्नर एड्रैस पर बोल लेना।

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीन कालेज मंजूर किये। आप जानते है पहले जब सरकारी कालेजों में कोई बच्चा दाखिला लेता था तो 8000 रूपये के करीब फीस लगा करती थी लेकिन अब उन्ही सरकारी कालेजों में हमारी सरकार बनने के बाद यह फीस घटकर 250 रूपये तक सीमित हो गई है। गरीब लोगों के बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सरकार में रादौर की नगरपालिका को बनाया गया। इतिहास गवाह है कि सन् 1924 में जब लाहौर में नगरपालिका बनी थी तभी रादौर में भी नगरपालिका बनी थी। लेकिन सत्तासीन हुई विभिन्न सरकारों ने कभी रादौर को पंचायत बना दिया तो कभी नगरपालिका बना दिया। हमारी सरकार ने रादौर को नगरपालिका बनाकर 70 गलियों का निर्माण एकसाथ करवाकर यहां का नक्शा ही बदल दिया है और अब रादौर को उप मण्डल का दर्जा दे दिया गया है जबकि पूर्व की हुडडा साहब की सरकार के समय से हमारा यह हल्का उप मण्डल के दर्जे के लिए भी तरस रहा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रादौर तथा किलोई को उप मण्डल का दर्जा दिया जिसके लिए वे सराहना के पात्र हैं। हुडडा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन वे अपने ही हल्के को उप मण्डल का दर्जा नहीं दिला सके। दोस्तो आप ही बताइये कि हरियाणा नं0 1, कांग्रेस सरकार के राज में या हरियाणा नं0 1 अब भाजपा की सरकार में बना है।

श्री अध्यक्षः किलोई हल्के को उप मण्डल बनाने पर हुड्डा साहब को भी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर तीन पावर हाउस 66 के.वी., 220 के.वी. के बनाये गये हैं।(शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से फसल बीमा योजना के ऊपर हमारे साथी एक बात कहते हैं कि गांवों को इकाई बनाया गया है। एक दिन जब मैं रादौर और यमुनानगर की किसान यूनियन के अध्यक्ष के घर गया तो मैंने उससे कहा कि अगर ओलावृष्टि तथा जल भराव से किसी भाई का एक एकड़ तक का नुकसान हुआ है तो हमारी सरकार उसके लिए मुआवजा देगी। हमारा क्षेत्र यमुनानगर यमुना के साथ लगता इलाका है इसलिए यहां पर जल भराव की स्थिति कभी भी आ सकती है लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई है तब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेरे क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाने संबंधी अनूठे कार्य किए गए। जिसकी बदौलत यमुनानगर लगभग फ्लड फ्री क्षेत्र हो गया है, जबकि कांग्रेस के शासन काल में इस क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती थी और किसानों की हर साल दुर्गति हुआ करती थी। यही नहीं किसानों को उनकी खराब हुई फसलों के मुआवजे के तौर पर 5 रुपये प्रति एकड़ की मुआवजा राशि देकर उनके साथ भद्दा मजाक किया जाता था।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री श्याम सिंह राणा जी से कहना चाहता हूं कि हमारे समय में तो मुआवजा दिया भी गया, लेकिन इनके समय में तो कुछ भी नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप के टाईम में भी किसानों को मुआवजा दिया गया था और वर्तमान सरकार के समय में भी किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है कि किसके टाइम ज्यादा दिया गया और किसके टाइम कम दिया गया, वह सच्चाई तो सामने आ जाएगी।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां यमुना के साथ लगता हुआ उत्तर प्रदेश का एक गांव डिक्का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पापुलर के बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमारे समय में पॉपुलर का रेट ज्यादा था।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, जहां पापुलर होता है, मैं वहीं रहता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) न तो पापुलर आपके यहां होता है, न ही पापुलर शर्मा जी के यहां होता है, लेकिन हमारे यहां पर पापुलर होता है इसलिए इसके बारे में मुझे आप लोगों से ज्यादा पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समय में पापुलर का रेट 1200 रुपये था।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, 1200 रुपये था, लेकिन पापुलर का जो रेट अभी है, वह भी आपके समय में था।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो अभी पापुलर का रेट है वह हमारे समय में शुरू में था और बढ़कर 1200 रुपये हो गया था। अभी वर्तमान सरकार में पापुलर का क्या रेट हैं कृपया ये बताएं ? (विघ्न)

श्री श्याम सिंह राणा : स्पीकर सर, यमुनानगर जिले में उत्तर प्रदेश का एक गांव डिक्का हरियाणा की सीमा के साथ लगता है। बिजली की कमी से ग्रसित इस गांव के लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि उन्हें हरियाणा प्रदेश में चल रही ''हमारा गांव–जगमग गांव'' योजना के तहत बिजली उपलब्ध करवाई जाए। स्पीकर सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारे देश में 15 हजार ऐसे गांव हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। डिक्का गांव के लोगों के अनुरोध पर हमने उत्तर प्रदेश के उस एरिया को 24 घंटे बिजली देने का काम किया। (शोर एवं व्यवधान) ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के उस गांव को बिजली क्यों दे रही है ? क्या वह हरियाणा का गांव है और क्या यह गांव बिजली के बिलों का भुगतान कर रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, ये सारा हिन्दुस्तान अपना ही है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : जय प्रकाश जी, यह गांव बिजली के बिलों की पूरी तरह से अदायगी कर रहा है। बिजली की हर यूनिट इस गांव के लोगों द्वारा दिया जा रहा है। यही कारण है कि हम इन्हें 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के सभी गांवों में बिजली की उपलब्धता हो। हमारी प्रदेश की जहां तक लड़कियों की बात है, आप देखेंगे कि सरकार ने भी इस काम को सर्वोपरि रखा है। ''बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ'' का पुरस्कार हमारे यमुनानगर जिले को मिला है, जहां पर ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' का काम सुचारू रूप से चलाया गया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस एक ही साथ चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं राहुल गांधी जी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। स्पीकर सर, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय जितनी भी नौकरी दी जाती थी उनके लिए रेट पहले से ही निर्धारित होता था जैसे कि तहसीलदार का क्या रेट होगा और अन्य दूसरी नौकरियों का क्या रेट होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, वे सारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ दी गई हैं। केवल नौकरियां ही नहीं अन्य दूसरी चीजों में भी पारदर्शिता आई है। अध्यक्ष महोदय, सदन में एस.वाई.एल नहर की चर्चा चली है, दादुपुर नलवी नहर की चर्चा चली तथा हांसी–बुटाना नहर की भी चर्चा चली। सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे नेता दिल्ली में प्रभावशाली रहे हैं । एक समय ऐसा भी था, जब जयप्रकाश जी सांसद हुआ करते थे। यह वह समय था, जब देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश से संबंध रखने वाले थे। जो यह लोग विपक्ष में बैठे हैं । उस समय इन लोगों का बोल–बाला था और हरियाणा के अंदर एस.वाई.एल. नहर का पानी आ सकता था । उस समय से लेकर आज तक हमें इतना अनुभव हो गया कि ये लोग एस.वाई.एल. नहर का पानी नहीं लाना चाहते । इसका कारण यही है कि शायद ये लोग इस हिस्से का पानी अपने एरिया में यूज कर रहे हैं और जब तक एस.वाई.एल. नहर नहीं बनेगी तब तक ये लोग उस पानी का यूज करते रहेंगे ।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि जब वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया था और केन्द्र सरकार को एस.वाई.एल. नहर बनाने के लिए कहा गया था तो उस समय नहर क्यों नहीं बनवाई गई । उस समय देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे । इसके अतिरिक्त पंजाब का टर्मीनेशन एग्रीमैंट एक्ट भी 2004 में आया था । इन्होंने दो साल का समय ऐसे ही निकाल दिया । केन्द्र सरकार ने उस समय यह नहर क्यों नहीं

बनवाई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र सरकार को यह नहर बनवाने के आदेश दिए थे ।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के अंदर जो पानी बढ़ा हुआ है और ओवर फलो होता है वह पानी इनके एरियाज में काम आ रहा है । उसको ये लोग यूज कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया । (शोर एवं व्यवधान) एस.वाई.एल. नहर में जो पानी आना था वह राजस्थान कैनाल में ट्रांसफर हुआ और ओवर फलो होने के कारण वह पानी इनके एरियाज में ट्रांसफर किया जाता है । इस तरह से आज भी ये लोग भाखढापानी को यूज कर रहे हैं इसीलिए ये एस.वाई.एल. नहर में पानी नहीं लाना चाहते । जब भी कभी एस.वाई.एल. नहर में पानी लाने की बात होती है तो विपक्ष के साथी बिना बात का बखेडा खडा कर देते हैं । वास्तविक सच्चाई यह है कि ये लोग एस.वाई.एल. नहर का पानी नहीं आने देना चाहते । अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है । मुझे पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जाने का अवसर मिला । पश्चिमी बंगाल में 29 साल से काम्यूनिस्टों की सरकार थी और 33 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । वहां पर दोनों हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गये। इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और नीतिश कुमार की सरकार है और पहले भी रही हैं । बिहार में ये लोग मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हो गये । इसी तरह से यू.पी. में भी सपा और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे हो गये । इस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले हरियाणा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के साथी इकट्ठे हो जायेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

14.00 बजे

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, विपक्ष में हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग हैं। हमारा देश गंगा, यमुना और सरस्वती का देश है। हमारा समाज मंदिर और मस्जिद से चलता है। अनेकों अनुष्ठान हमारे समाज का विभिन्न अंग हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में एक साईकिल पर दो नौजवान बैठ गये हैं और जो साईकिल पंक्चर हो गई है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि वे किसी से सलाह करके नहीं बैंठे थे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को कहना चाहूंगा कि हमें और उनको यहीं रहना है और इस बार होली पर हम उनके चेहरे पर भगवे रंग का गुलाल लगायेंगे। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि इनके चेहरे पर भगवा रंग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके चेहरे का रंग गोरा

है। मैं इनको यह सलाह भी देना चाहता हूं कि इनको किसी भी प्रकार की टैंशन में नहीं रहना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सभी सदस्यों की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री श्याम सिंह राणा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि यमुनानगर के पास यमुना दरिया लगता है। हरियाणा प्रदेश के किसानों की 6 से 7 हजार एकड़ जमीन यमुना नदी के पार है। जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो किसानों के ट्यूबवैल्ज पर जाने वाले बिजली के खम्बे गिर जाते हैं। अगर बिजली के खम्बे गिर जाते हैं तो किसानों की फसल को सूखे का सामना करना पड़ता है। हरियाणा की वर्तमान श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यमुना पार के किसानों के लिए विशेष योजना बनाकर टॉवर के माध्यम से बिजली देने का काम किया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 6 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं ताकि वहां पर टॉवर से बिजली जाये और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने हरियाणा प्रान्त के अंदर 36 बिरादरी की बात की है। जब यहां पर पिछली बार जाट आरक्षण आंदोलन चला था तो उस समय मैंने चण्डीगढ़ से लेकर रादौर तक पद यात्रा की थी। मेरी वह यात्रा हरियाणा की 36 बिरादरी के लिए सद्भावना यात्रा थी। हर गांव के अंदर जितने भी जाट बिरादरी के लोग थे वे सब चाहते थे कि धक्के–मुक्के वाला आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं हुड्डा साहब से कहना चाहूंगा कि जब पहला सैशन था उस समय जाते समय ये कह रहे थे कि इन्होंने यह कहा था कि डेढ़ साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जायेगी और हम भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। अपनी उसी योजना के तहत 15 महीने के बाद जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। अब भी कांग्रेस के ही ईशारे पर यह आंदोलन

चल रहा है। इसलिए मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी हमारे संस्थापक रहे हैं। उन्होंने भी राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ा था लेकिन वे ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखते थे। उसके हल्के के लोग कहने लगे कि आप एक बार कह दो कि मैं ब्राह्मण हूं हम आपको चुनाव जिता देंगे। उसने कहा कि यह बात मैं कभी भी नहीं कह सकता। मैं ब्राह्मण हूं मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा चाहे मैं चुनाव ही क्यों न हार जाऊं। आज हमारे यहां पर हरियाणा प्रदेश में ऐसी ही शिक्षा की जरूरत है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जात–पात और क्षेत्रवाद के रास्ते पर न चलकर इनको भारतीय जनता पार्टी से और इसकी विचारधारा से शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तभी इस प्रदेश का विकास होगा। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बऱवा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि खानक पहाड़ मजदूर यूनियन के मजदूर कम से कम दो महीने से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष : बऱवा जी, जब आपको गवर्नर ऐड्रस पर बोलने के लिए मौका मिलेगा उस समय आप अपनी बात कह लेना। अभी आप कृपया करके बैठ जायें। जय प्रकाश जी, अब आपको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया जाता है।

श्री जयप्रकाश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने हरियाणा सरकार का जो विजन डौक्यूमैंट सदन के सामने रखा है आज उस पर बड़े विस्तार से चर्चा चल रही है । इसमें कई मुद्दे ऐसे भी आये जिनकी बड़ी महत्ता थी लेकिन हर पार्टी ने अपने–अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया । अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से शुरू करूंगा कि सबका साथ सबका विकास आपकी सरकार का नारा है । सबका साथ तो है ही कि यह सदन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है । पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी कलायत में गये थे और वहां पर 17 घोषणाएं करके आये थे । कुछ पैसा कलायत में गया भी है । ग्रामीण और शहरी विकास के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये गये हैं । उसके ऐस्टीमेट्स मुझसे भी मांगे गये थे और मैंने दे भी दिये थे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि

8–9 महीने हो चुके हैं लेकिन जो बाकी की मांगें थी उनमें किसी पर भी कार्य शुरू नहीं हुआ है । मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सब–डिवीजन लेवल पर मिनी सचिवालय बनाया जायेगा लेकिन उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है । वहां पर स्टेडियम का काम भी शुरू नहीं हुआ है और न ही कालोनियों का काम शुरू हुआ है । इसी प्रकार से रैस्ट हाउस बनाने की घोषणा थी लेकिन वह काम भी शुरू नहीं हुआ है यानि बहुत सी घोषणाएं कर दी गई तो मैं यह भी चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको इम्पलीमैंट करवाया जाये । वहां के लोग विधायक को यह कहना शुरू कर देते हैं कि आप हमारी आवाज उठाओ, सरकार घोषणाएं करके चली गई लेकिन उन पर काम शुरू नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें वेतन आयोग के बारे में भी अपनी बात रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री यहां पर बैठे हुये हैं और इन्होंने कहा था कि हमने भारत सरकार के बाद पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है । मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो आशा वर्कर और मिड–डे मील वर्कर हैं वे भी इस प्रदेश का हिस्सा हैं आप उनको भी इसमें इन्कल्यूड करने का कष्ट करें । इसके अलावा आज जो हमारे गैस्ट टीचर्स हैं उनके बारे में भी विचार किया जाये । अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों आशा वर्कर के साथ तो सरकार ने बहुत अन्याय किया है । वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी शाम को 5 बजे उन पर पानी की बौछार कर दी गई और वे अपने बच्चों को भी साथ लेकर बैठी हुई थी । इस सर्दी के मौसम में उनको और उनके बच्चों को ठण्ड लग गई । कम से कम नारियों पर तो इस प्रकार के अत्याचार नहीं किये जाने चाहिएं थे ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी की सरकार में तो गैस्ट टीचर्स पर गोलियां चली थी और हमारी एक बहन जो कि खरल गांव की रहने वाली थी, उसकी हत्या हुई थी जहां पर जयप्रकाश जी भी अफसोस जताने गये थे । मेरा जयप्रकाश जी से अनुरोध है कि सभी बातों को जोड़ कर कहें । इनका हरियाणा के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव है और घूम–घूम कर कई घाटों का पानी पीने का भी इनका अनुभव है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इनको सही बात रखनी चाहिए ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव है तभी तो आप लोग यहां पर बैठे हुये हैं । (हंसी)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ साथी हैं और ये एम.पी. भी रह चुके हैं । जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा नहीं होते हैं तो ये हमारे प्रभाव में सही बोलते हैं और जब वे सामने होते हैं तो पता नहीं क्या होता है ये उल्ट–पुल्ट हो जाते हैं । इन्होंने पहले दूसरा कागज पकड़ा हुआ था अब हुड्डा साहब के आने के बाद दूसरा कागज उठा लिया है । इन्होंने शुरूआत अच्छी की थी कि मुख्यमंत्री जी कलायत में गये थे और जो मांगा वह देकर आये थे लेकिन बाद में पलट गये । (हंसी)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब को देखते ही इन्होंने अपना कागज बदल लिया । (हंसी)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, पूरे भारतवर्ष में मैं एक ऐसा विधायक हूं जो न तो सत्ता पक्ष का समर्थन करता हूं और न ही विपक्ष का समर्थन करता हूं । मैं तो अकेला हूं और अकेले आदमी का तो सभी को साथ देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मिड.डे.मील, आशा वर्कर्ज और गैस्ट टीचर्स की जहां तक बात है। इनमें से गैस्ट टीचर्स का बहुत साथियों ने प्रश्न किया है । मेरे इलाके में कम से कम 500 गैस्ट टीचर्स हैं । आदरणीय श्री राम बिलास शर्मा जी अगर उनको पक्का कर दो तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि पहली सरकार की एक पॉलिसी होती थी कि जब भी किसी कर्मचारी को नौकरी करते हुए 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे वह स्वयं ही पक्का हो जाएगा। आप रिटायरमैंट की आयु का 58 साल से 60 साल का निर्णय लेने वाले हो जिसके लिये आपने शायद कोई कमेटी बनाई है । मेरा आपको एक अच्छा सुझाव है कि अगर सरकार गैस्ट टीचर्स को भी ऐसे ही पक्के कर दोगे तो उन लोगों के लिये भी अच्छा हो जाएगा जिनके ऊपर अनिश्चितता की तलवार लटकती रहती है । इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में एक इच्छा भी है और एक सोच भी है कि उनका वेतनमान पंजाब के कर्मचारियों के वेतन के समान हो जाए। जब हम पंजाब का एस.वाई.एल. नहर का पानी ला रहे हैं जिसकी खुदाई के लिये हम लड़ाई लड़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बड़े शर्म की बात है कि पंजाब के कर्मचारियों का हमारे हरियाणा के कर्मचारियों से ज्यादा वेतन है । अभी मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सदन में घोषणा करें कि इसी वित्त वर्ष में हरियाणा के कर्मचारियों का वेतनमान पंजाब के कर्मचारियों से चाहे एक रूपया ज्यादा कर दो लेकिन पंजाब के कर्मचारियों से ज्यादा वेतन कर दो । मेरी आपसे यही प्रार्थना है । हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों का भी बहुत कम वेतन है अगर उनका वेतन भी ज्यादा होगा तो हम आपका

धन्यवाद कर देंगे । अध्यक्ष महोदय, अब मैं गांवों के बारे में कहना चाहूंगा ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में तालाबों की निकासी की बहुत भारी समस्या है । सरकार शायद इस कार्य में लगी भी है लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए । मैं मेरे इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की बात कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पौंड के पानी को पाईपों के माध्यम से बाहर निकालने का काम सरकार ने शुरू किया हुआ है। मेरे हल्के में भी यह काम शुरू किया हुआ है लेकिन वहां पर जमीन नहीं है। अगर वहां पर जमीन नहीं है तो सरकार अंडर ग्राउंड पाईप लगा कर के पौंड के पानी को किसी भी ड्रेन में या आबादी से बाहर निकलवाने का काम करे । क्योंकि पानी खड़ा होने से गांवों में जो गलियां पक्की की जाती हैं वे एक–दो वर्ष में सारी टूट जाती हैं जिससे सरकार का पैसा खराब हो जाता है । हमारे यहां बालू, शेरदा, डुंडवा, बाता, रामगढ़, खरक पाण्डो, यह सभी ऐसे गांव है मंत्री महोदय, पिछली सरकार के समय में बालु गांव में 18 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे। लेकिन आज उस गांव में पानी की निकासी न होने की वजह से सरकार के पैसे का नुकसान हो रहा है । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस गांवों में पानी की निकासी का जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाए । अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में एक चर्चा चली थी अच्छी बात है, ऐसे मुद्दे पर चर्चा होनी भी चाहिए । मैं यह भी कहूंगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पानी का मंत्रालय आया है तब से हमारे इलाके में पानी समान रूप से चल रहा है । मैं समान बंटवारे के लिये आपको दो–तीन राय दूंगा । इसमें मैं मेरे दूसरे साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो हम पानी के लिये लड़ाई लड़ते हैं चाहे हांसी–बुटाना नहर हो, दादूपुर नलवी नहर हो या एस.वाई.एल. नहर हो । इसके लिए मैं सभी सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि जब प्रदेश में एक नहर की खुदाई की गई थी तो प्रदेश की एक पार्टी ने उस पर न्यायालय से स्टे ले लिया था जिसके कारण उस नहर की खुदाई रूक गई थी । उस समय मैंने यह कहा था कि प्रदेश की सभी पार्टिज आपस में एक जुटता दिखाए और नहर की खुदाई के लिए स्टे न ले । नहरों की खुदाई के लिये, नहरों के पानी के लिये कम से कम हम सब सदन में एक दिखाई देने चाहिए क्योंकि जब हम पंजाब से बात करते हैं तो पंजाब की सरकार यही कहेगी कि हरियाणा में जो हांसी बुटाना नहर बनी है उसके लिए हरियाणा की एक पार्टी ने स्टे ले लिया है । इसलिये इस पानी को लेकर के मेरा

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए । जिस प्रकार हमारे साथी श्याम सिंह राणा जी कह रहे थे । मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं उस वक्त एम.पी. नहीं था मैं उस वक्त केन्द्र में मंत्री था । अगर मैं उस समय की बात सदन के सामने रख दूंगा तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा क्योंकि आज यह मामला सर्वोच्य न्यायालय में विचाराधीन है । शायद आज उस पर डिबेट भी होगी । इसलिये उसके बारे में अगर कोई साथी मुझसे पूछना चाहता है तो उस वक्त के बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि नहर की खुदाई में कौन लोग बाधक थे और किन लोगों के दबाव में एस.वाई.एल. नहर की खुदाई नहीं की गई । आज स्वर्गीय चन्द्र शेखर जी स्वर्ग में हैं । चन्द्र शेखर जी ने उस वक्त यह कहा था कि मैं हरियाणा के लिए एस.वाई.एल. नहर खुदवाना चाहता हूं । बरनाला जी भी चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश के लिए एस.वाई.एल. नहर खुदे । इसलिये मेरा सब से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें । कल विपक्ष के नेता कह रहे थे कि मैं बी.जे.पी. के सदस्यों को भी चिट्ठी लिखूंगा कि बी.जे.पी. के सदस्य भी नहर खोदने के लिए पंजाब चलें क्योंकि आई.एन.एल.डी. 15 तारीख को पंजाब में प्रदर्शन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरदार जसविन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं उनकी पार्टी ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी । मैं तो आजाद उम्मीदवार हूं । अगर लोकदल पार्टी के भाइयों ने मुझे चिट्ठी लिखी होती तो वह अलग बात थी कि मैं वहां जाता या नहीं जाता । मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी राजनीति करना चाहती है । इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए । आप सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखो । अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 तारीख से पहले ही एस.वाई.एल. नहर के बारे में कोई न कोई फैसला हो जाएगा ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से बड़े खुले दिल से कहा है कि एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर चाहे देश के प्रधानमंत्री से मिलने की बात हो या चाहे देश के राष्ट्रपति से मिलने की बात ही क्यों न हो, इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी इनकी अगुवानी में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार है और पूरी तनमयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। हमने इस मामले में कतई कोई राजनीति नहीं की है बल्कि हम हर हालत में सरकार के साथ हैं ताकी एस.वाई.एल. कैनाल का पानी हरियाणा प्रदेश में आये। बड़े दुख की बात है कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी

देश के प्रधान मंत्री जी ने हरियाणा सरकार को मिलने का समय नहीं दिया है। हम आज भी खुले दिल से कहते हैं कि एस.वाई.एल. के मामले पर कोई राजनीति नहीं करेंगे और सरकार के साथ है लेकिन सरकार को भी तगड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एक फैसला कर दिया है फिर एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर उदासीनता के क्या कारण है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवदन है कि सरकार को प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लेना चाहिए और निश्चित रूप से हम सरकार का साथ देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की अगुवानी में प्रधानमंत्री से मिलने चलेंगे, आप समय तो लो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणाः संधू जी, इस मामले में आप लोगों की नहीं चलेगी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, राणा जी भी बोलने लग गए हैं इन्हें यह नहीं पता है कि * में इनका दांव लग गया है। इसको तो हजार वोट भी नहीं मिलती थी। इसे कौन पूछता था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः * शब्द को रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, यह सदन जनता की आवाज को रखने का मंच है। यहां पर अपने घर की बात नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, संधू जी मेरे दोस्त हैं मैं उनको चुनौती देता हूँ कि एक बार वह अपने हल्के से बाहर जाकर चुनाव लड़कर देख लें तो पता चल जायेगा इनको कितने वोट मिलेंगे। (हंसी व विघ्न)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मुझे बीच में इंट्रप्ट किया जा रहा है। मुझे अपनी बात रखने दी जाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि खेड़ी लाम्बा माईनर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये। पिछले सत्र में माननीय मंत्री श्री धनखड़ जी ने सदन में इसके लिए हां भरी थी और कहा था कि खेड़ी

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

लाम्बा माईनर का निर्माण जरूर करवाया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इस माईनर को बनवाया जाये ताकि तीन चार गांव को उसका पानी मिले। इसके अतिरक्त हमारे यहां कैलरम माईनर है जोकि बहुत लंबी है। सात किलोमीटर इसकी टेल पड़ती है। यदि कैलरम माईनर को 14 गांवों के साथ सिरसा ब्रांच के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस पानी से खेतों में बहुत ज्यादा सिंचाई होगी और रही बात खर्च की तो वह भी ज्यादा नहीं आयेगा और इस प्रकार यहां होने वाली पानी चोरी की घटनाओं में भी कमी आयेगी। अध्यक्ष महोदय, माईक्रो इरिगेशन की बात भी सदन में आई थी लेकिन मैं इस विषय पर सरकार से भिन्नता रखता हूँ। इसका कारण यह है कि करीबन एक डेढ़ साल पहले हरियाणा सरकार की तरफ से माईक्रो इरिगेशन के लिए 25000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च निर्धारित किया गया था। यदि माईक्रो इरिगेशन के संबंध में भारत सरकार के नॉर्म्ज देखें तो यह खर्चा 50000 रूपये प्रति एकड़ दर्शाया गया है लेकिन हाल ही में जो माईक्रो इरिगेशन के संबंध में जो जैन माइक्रो कंपनी को सरकार की तरफ से ठेका दिया गया है वह कम्पनी माईक्रो इरिगेशन के लिए 125000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से चार्ज करेगी। मैं समझता हूँ कि इसको एग्जामिन करवाने की जरूरत है? कहीं ऐसा न हो कि हरियाणा प्रदेश की जनता की खून और पसीने की कमाई गलत लोगों के हाथों में चली जाये। इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जाये।

कृषि मंत्री(श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी से जानना चाहूँगा कि जैसाकि इन्होंने बताया कि माईक्रो इरिगेशन के लिए जैन माईक्रो कम्पनी को ठेका दिया गया है, तो मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि यह ठेका किसके द्वारा दिया गया है?

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि यह काम इरिगेशन विभाग से संबंधित है और जल्द ही शुरू होने वाला है और मैं इससे संबंधित सभी कागजात माननीय मंत्री जी को दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा। अगर मेरे हल्के के चौशाला गांव में 33 के.वी. का पॉवर हाउस लगा दिया जाये तो यह बहुत अच्छी बात होगी और मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद करूंगा। जब धान का सीजन आता है तो बिजली की बहुत शॉर्टेज हो जाती है

और ऐसे में गांव के लोग बिजली के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते–झगड़ते हैं। अगर 33 के.वी. का पॉवर हाउस लगा दिया जाता है तो चौशाला गांव के लोगों की लड़ाई खत्म हो जायेगी। अब मैं फसल बीमा योजना की विषय पर अपनी बात रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं फसल बीमा योजना पर कोई बहस नहीं करूंगा क्योंकि काफी सदस्यों ने इस विषय पर बहस कर ली है यही नहीं श्री करण सिंह दलाल जी पर प्रिवीलेजिज मोशन भी इस मामले पर लेकर आया गया है परन्तु बावजूद इसके मैं भी एक सुझाव फसल बीमा योजना के बारे में देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसान आर्थिक तौर से बहुत कमजोर है। फसल बीमा योजना का 60 करोड़ रूपये का बजट है। यदि फसल बीमा योजना का प्रीमियम सरकार पे कर दे तो यह एक बहुत अच्छा कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़क संबंधी विषय पर आता हूँ। आज सवेरे मेरे हल्के की दो सड़कों के बारे में तो हां भर ली गई थी लेकिन मेरे हल्के में दो सड़क और हैं अर्थात लाम्बा खेड़ी से सजुमा तक तथा नरड़ गांव से करनाल रोड़ तक। यदि यह सड़कें बन जाती हैं तो निःसंदेह लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में स्टेडियमों का काम पैंडिंग है। मंत्री जी द्वारा 10 गांवों में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की गई थी जिनमें से एक व्यायामशाला का टैंडर लग चुका है और 9 व्यायामशालों का काम अभी पैंडिंग है अतः मेरा निवेदन है कि बाकी बची व्यायामशालाओं का काम भी जल्द से जल्द करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जींद में नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग को तैयार हुए लगभग सवा दो साल हो चुके हैं। यदि इस बिल्डिंग में जल्द से जल्द नर्सिंग कॉलेज खोल दिया जायेगा तो नर्सिंग से जुड़ी लगभग 400 बच्चियों को इससे लाभ होगा। प्राईवेट नर्सिंग कालेज दो–दो लाख रूपये तक का डोनेशन लेते हैं। यदि सरकारी नर्सिंग कॉलेज चालू होता है तो डोनेशन की बात तो दूर रही बल्कि इससे बच्चियों को स्टाईफंड भी प्राप्त होगा। अतः इस नर्सिंग कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक और महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे पूर्व विधायक आपसे भी मिले थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर भी ज्ञापन दिया था मैं उनकी बात भी सदन में उठाना चाहूँगा। पिछले दिनों वर्तमान विधायकों व मंत्रियों के वेतन व भत्ते बढ़ाये गए थे लेकिन पूर्व विधायको की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यदि पूर्व विधायकों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने की एवज में कैशलैस सुविधा दे दी जाये तथा

टोल नाकों पर उनकी गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया जाये, वोल्वों बसों में कंपैनियन छूट दे दी जाये तथा वर्ष में घूमने के लिए इनको यदि अढ़ाई–तीन लाख रूपये दे दिए जायें तो इनका बुढ़ापा ठीक कट जायेगा । अध्यक्ष महोदय, हमें याद रखना चाहिए कि एक दिन आप और हम सबको भी एक्स बनना है।

श्री रणबीर सिंह गंगवा (नलवा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में काफी महिमामंडन किया गया है जबकि धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता इसलिए मैं इस राज्यपाल अभिभाषण का विरोध करता हूँ। पिछले काफी समय से प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब हैं। जब कानून व्यवस्था की हालत खराब होती है तो खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं चाहे वह एस.सी. वर्ग के हों या बी.सी. वर्ग के हों या महिलाएं हों उन सबके उपर निरंतर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। आज प्रदेश के अन्दर आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा संख्या 104 में कहा गया है कि सरकार पिछड़े वर्ग व अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अफसोस है कि उनके कल्याण के लिए कोई नई योजनाएं सरकार की तरफ से लेकर नहीं आई गई हैं। जैसाकि मैंने अभी बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की बात की है, उस परिपेक्ष्य के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि राज्यपाल अभिभाषण में वर्णित है कि वर्ष 2016–17 में संपत्ति की हानि, गम्भीर चोट, हत्या, बलात्कार और अस्थायी एवं स्थायी दिव्यांगता जैसी विभिन्न क्षतियों के 364 पीड़ितों को 2.94 करोड़ रूपये वितरित किए गए। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की हालत यह है कि हर 8 घंटे में एक बलात्कार व एक हत्या हो जाती है तथा हर चार–पांच घंटे में अपहरण की घटनायें घट रही हैं। यह बहुत चिंतनीय है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुलाई माह में करनाल जिले में नर्सिंग छात्राओं पर लाठी चार्ज करवाया था और यही नहीं महिला गैस्ट टीचर्ज एवं कंप्यूटर सहायकों के उपर लाठी चार्ज करवाने का काम किया गया था और सदन में महिलाओं व बेटियों के लिए बड़ी–बड़ी बातें की जाती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, गंगवा जी हर आधे घंटे में बलात्कार की बात कहकर जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो आधे घंटे की समयावधि में एक बलात्कार तथा एक हत्या व चार–पांच घंटे की समयावधि में अपहरण की घटनाओं संबंधी जो बात कही जा रही है, इस परिपेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथी यह कहां के आंकड़े उठाकर ले आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, गंगवा जी आधे घंटे की नहीं बल्कि 8 घंटे की बात कर रहे हैं और यह सभी आंकड़े राज्य सरकार के आंकड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह गंगवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने 8 घंटे की बात कही है। आधे घंटे की बात को सत्ता पक्ष की तरफ से जानबूझकर घूमाकर कहा जा रहा है। यह सब आपकी सरकार के आंकड़े हैं। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। आपकी सरकार के रवैये से दुखी होकर हिसार के भगाना गांव के 100 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन करने का काम किया है। और आज भी मिर्चपुर के जो दलित हैं उनका पुनर्वास का मामला लम्बित है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, रणबीर गंगवा जी हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। राज्यसभा के माननीय सदस्य भी रह चुके हैं। गंगवा जी जो भगाना गांव की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कई बार कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन गंगावा जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है अपितु एक समाज के मुखिया भी हैं। किसी भी दलित परिवार ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। गांव की सामान्य लड़ाई को स्वर्ण और दलित का झगड़ा हमको नहीं बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा गंगवा जी से निवेदन यह है कि वह केवल विधायक ही नहीं बल्कि एक समाज के मुखिया भी हैं। इसी तरह से उनके द्वारा बोली हुई बात उनके ही रिकॉर्ड में आ जाती है। कोई भी धर्म परिवर्तन ना गांव भगाना में हुआ और ना ही मिर्चपुर में हुआ है।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने मिर्चपुर के बारे में कहा है कि उनके पुनर्वास का मामल अभी भी लम्बित है। आज भी वे मेरे घर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर कैमरी रोड़ पर तंवर फार्म हाउस में रह रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, गंगवा जी जो मिर्चपुर का विषय उठा रहे हैं, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। लम्बे समय से मिर्चपुर के प्रकरण के बारे में

अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया है। इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश भी की गई है। कांग्रेस सरकार में तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मिर्चपुर में लाकर पूरे वातावरण को खराब करने का काम भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से मिर्चपुर के सर्व समाज के प्रयास से, आस–पास के खाप पंचायतों के प्रयास से और सरकार के प्रयास से मिर्चपुर में शांति बनी है। उस गांव में अब पुलिस भी तैनात नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय हाल के दिनों में भी फिर वही घटना हुई और उसी तरह उस पर राजनीति करने की कोशिश की गई। यह सबको मालूम है कि उस घटना में आपस में ही कुछ नौजवानों का झगड़ा था, जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल थे। उस झगड़े को भी एक जातिय रंग देने की दिशा में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। पुनर्वास के मामले में मिर्चपुर के सर्व समाज के मौजूदा लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की और कहा कि जैसा वे उचित समझे हम उन लोगों को गांव में मान–सम्मान के साथ बसाना चाहते हैं। ताकि वे लोग अपने समाज को आगे चला सके। यदि वह समाज कहीं और बसना चाहता है और वह समाज सरकार का सहयोग करें तो प्रदेश की सरकार उसके लिए तैयार है। वे समाज के लोग कहीं भी जाकर बसे आपस का भाईचारा तो कायम रहेगा ही। अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की मिर्चपुर की घटना का जिक्र सदन में होता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बातें उठे वह सर्व समाज के हित में उठे। अध्यक्ष महोदय, इस समाज का ताना–बाना बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है इसलिए इस समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि सभी माननीय सदस्यों को इस समाज को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

श्री रणबीर गंगवाः अध्यक्ष महोदय, मैंने समाज को कोई तोड़ने की बात सदन में नहीं उठाई है । मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सरकार उस समाज के पुनर्वास के लिए काम करें । मैंने समाज के ताना–बाना को खराब करने की कोई बात नहीं कही है। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में जो घटना घटी है सिर्फ उसी का ही जिक्र किया है, इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है।

श्री राम बिलास शर्माः गंगवा जी, आपकी पुनर्वास की जो बात है वह ठीक है।

श्री रणबीर गंगवाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जब सरकार पिछड़े वर्ग की बात करती है और कहती है कि उनके

उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले लोग जो खासकर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनके पास मिट्टी लेने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। कई गांवों में तो खाली जगहों पर लोगों के कब्जे हो गए हैं और कई गांवों में खाली जगह बची नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार वास्तव में पिछड़ा वर्ग को रोजगार देना चाहती है और उसके उत्थान की बात करना चाहती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार गांव में उनके लिए 5 एकड़ जमीन एक्वायर करके मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जगह देने का काम करें। ताकि वे लोग अपने रोजगार को चला सकें अपना कार्य कर सकें आज मिट्टी के बर्तन जो लोग बनाते हैं उनको लघु उद्योग का दर्जा देने का काम करें ताकि वे लोग उस काम को निरंतर कर सकें।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणबीर गंगवाः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के स्कूलों की हालत कई जगह पर ऐसी है कि वहां पर बच्चों को पढाने के लिए कई विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केवल कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चे या एस.सी./बी.सी के बच्चे ही पढ़ते हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं वे अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसलिए अगर जिस स्कूल में अध्यापक नहीं हैं वहां गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर स्कूल में अध्यापक नहीं हैं और उस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल वहां पर मनरेगा के मजदूर ही तैयार हो रहे हैं, वे उससे आगे नहीं बढ सकते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा या तो अध्यापकों की भर्ती की जाए या उस स्कूल को बन्द कर दें ताकि वे मां–बाप अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा सकें। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसके ऊपर ध्यान देने योग्य बात है कि स्कूलों में बच्चे सिर्फ मिड डे मील के लिए

ही न भेजे जाए। उनके भविष्य का भी विशेषकर ध्यान रखा जाए। अभी जिस तरह से हमारे एक माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी ने बोलते हुए प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा के बारे में प्रकाश डाला था कि आज जितने भी विभागों के अन्दर कर्मचारी रखे जाते हैं वे ठेकेदारों के द्वारा ही भर्ती किये जाते हैं अगर सरकार ने डी.सी. रेट पर भर्ती करना है तो सरकार ही सीधी भर्ती करे ताकि बिचौलियापन खत्म हो जाए जिससे कर्मचारियों का शोषण न हो। दूसरा विशेषकर ठेकेदारी प्रथा में जो अपने लोगों को लगाया जाता है इसमें संवैधानिक तरीक से वर्ग वाईज भर्ती की जाती है जैसे एस.सी./बी.सी. श्रेणी के लोग हैं यह नियम भी इसमें लागू नहीं होता। इसलिए हर तरह की मार एस.सी./बी.सी. के लोगों पर पड़ रही है। यह भी बिल्कुल गलत तरीके से सरकार कार्य कर रही है। सरकार विशेष रूप से समान विकास की बात कर रही है यह कैसे लागू होगी क्योंकि विपक्ष के विधायकों के पास ग्रांट नहीं। अगर सरकार 5 करोड़ रूपये की ग्रांट देने का प्रावधान कर दे तो वह ग्रान्टस भी गांवों में मैरिट के आधार सुधार के कार्यों पर लगेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय इस बारे में हम आपसे मिले थे और आपने आश्वासन दिया था कि आपकी सर्पोट करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन चाहता हूं कि विधायकों की ग्रान्ट का प्रावधान करें।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के हल्के के विकास के लिए 200 करोड़ रूपये की ग्रांट दी जा चुकी हैं।(शोर एवं व्यावधान)

श्री ओम प्रकाश बरवा: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ग्रांट का पैसा नहीं पहुंचा है।(विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों को चुप कराइये ताकि गंगवा जी अपनी बात पूरी कर सकें।

श्री रणबीर गंगवा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि 200–200 करोड़ रूपये कहां देकर आएं हैं इस बात का पता नहीं। हमारे प्रदेश की सड़कों की हालत यह है कि मुझे और बड़वा साहब को इस विधानसभा को सदस्य बने हुए ढ़ाई साल हो गये हैं लेकिन इन ढ़ाई सालों में हमारे गांवों की जो सड़के हैं वे बहुत ही खस्ता हालत में हैं क्योंकि सरकार के द्वारा पैसा दिये जाने के बाद भी सड़क नहीं बन रही हैं। मैंने इस बारे में एक्सिएन साहब से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि

ठेकेदारों की पैमेंट नहीं हुई है। सरकार जीरो टालरेंस की बात कर रही है। मैंने ठेकेदार से भी बात की तो उसने बताया कि उनकी पैमेंट नहीं हुई है तथा मैनें चीफ साहब से भी टेलीफोन किया था कि इनकी पैमेंट क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि सर, ठेकेदार के द्वारा बड़वा के पास जो रोड़ बनाए गये हैं उन रोडज के अन्दर जो मैटेरियल लगाया गया है वह मैटेरियल बढ़िया नहीं लगाया गया है। इसलिए ठेकेदार की पेमेंट नहीं की गई है। जब ठेकेदार की पेमेन्ट नहीं होती है तो वह चण्डीगढ आता है और वहां पर उसकी पैमेंट होती है। इस तरह से पेमेन्ट को डिले किया जाता है। लेकिन इतने दिन से जो मैटीरियल रोड पर लगाया गया था वह मैटिरियल तो ठीक हुआ नहीं है यह क्या मामला है इसके बारे में सरकार के लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने अभी हाल में जो पांच निगम बनाये हैं उन निगमों में आउटर कालोनियों को शामिल किया गया है। उन कालोनियों की भी हालत ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे हल्के नलवा के अन्दर जैसे आजाद नगर, गंगवा रोड़ तथा कैमरी रोड़ हैं उनकी हालत गांव से भी ज्यादा बदतर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे हल्के नलवा के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि वहां के लोग निगम को प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। वहां न तो कोई अच्छी सड़कें बनी हैं और कुछ सड़कें बनी भी हुई हैं तो ऐसी हैं कि वहां से साईकिल तो क्या स्कूटर भी लेकर नहीं जा सकते। इस तरह की हालत मेरे हल्के के गांवों की है। उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नलवा के अंदर गए थे और 195 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी करके आये थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि वह पैसा आखिर कहां गया। अध्यक्ष महोदय, नलवा हल्के के लोगों की सबसे मुख्य मांग पानी की थी। आज भी वहां के किसानों की हालत यह है कि उनके खेत बरानी हो गए, पीने के पानी की भारी समस्या है। गौरसी, ससाना, बासड़ा, नलवा, बालावास, दूबेटा इस तरह के गांवों में आज भी पीने के पानी की समस्या है। उस समस्या को हल किया जाए। आपने मुझे थोड़ा बोलने का मौका दिया, इसके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब सदन कल दिनांक 3 मार्च, 2017 प्रातः 10 बजे तक के लिए *स्थगित किया जाता है।

*14:35 बजे

(तत्पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार 3 मार्च, 2017 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई)